सूर्योदय 5:47 सूर्यास्त 7:05

आज का तापमान

शिमला	18.0 न्यू	24.0 अधि
धर्मशाला	21.0 न्यू	30.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	78,080
निफ्टी	24,396

सोना 1,52,000 चांदी 2,34,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 | 29 श्रावण, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 110, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

सुप्रीम कोर्ट बोला- पैकेज्ड फूड पर वॉर्निंग लेबल लगाओ

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के वार्निंग लेबल पर केंद्र सरकार और फूड सेफ्टी अथॉरिटी (एफएसएसएआई) को आखिरी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि नमकीन, बिस्किट और चिप्स के पैकेट पर ज्यादा चीनी-नमक और फैट की चेतावनी देने वाले वार्निंग लेबल लगाने पर अगर सरकार फैसला नहीं ले पा रही है तो हम आदेश जारी करेंगे। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा पहले भी आपसे सख्त न्यूट्रिशन वॉर्निंग को लेकर निर्देश दिए थे फिर आनाकानी क्यों। हमने जो कहा है, आपको करना चाहिए, क्या आप पर कॉर्पोरेट घरानों का दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। आपने अब तक क्या किया। 6 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एफएसएसएआई से कहा था कि पैकेज्ड फूड पर वॉर्निंग लेबल लगाने पर विचार किया जाए।

ट्रंप की वफादार कैरोलिन लेविट ने छोड़ी नौकरी

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिनी जाने वाली व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 28 साल की लेविट इस महीने के आखिर में व्हाइट हाउस छोड़ देंगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लेविट अब अपने परिवार और दो छोटे बच्चों को ज्यादा समय देना चाहती हैं। हालांकि, वह ट्रम्प की बाहरी सलाहकार बनी रहेंगी और रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम करती रहेंगी। लेविट 27 साल की उम्र में अमेरिका के इतिहास की सबसे कम उम्र की व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनी थीं। मई में बेटी के जन्म के बाद वह कुछ समय के मातृत्व अवकाश पर गई थीं और कुछ दिन पहले काम पर लौटी थीं। उनका एक दो साल का बेटा भी है। वह मई में बेटी के जन्म के बाद करीब दो महीने छुट्टी पर रहीं, जुलाई में काम पर लौटीं और एक महीने बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया।

श्रीलंकाई नौसेना ने 10 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया

एजेंसी, रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामेश्वरम और आस-पास के इलाकों के दस मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने कच्चातिवु के पास गिरफ्तार किया है। उन पर समुद्री सीमा पार करने और श्रीलंकाई जलक्षेत्र में मछली पकड़ने का आरोप है। तमिलनाडु मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बुधवार सुबह जरूरी टोकन लेने के बाद रामेश्वरम फिशिंग जेटी से 297 मशीनीकृत ट्रॉलर समुद्र में गए थे। देर रात, थंगाचीमडम के राजन नगर के रहने वाले वेलिंगटन की एक मशीनीकृत नाव को कच्चातिवु के पास श्रीलंकाई नौसेना की निगरानी टीम ने रोक लिया। शुरुआती पूछताछ के बाद, नौसेना के जवानों ने नाव और उसके 10 सदस्यों वाले क्रू को हिरासत में ले लिया।

लोकसभा की 19 बैठकों में 17 घंटे 30 मिनट ही चली कार्यवाही

राज्यसभा में एमएमडीआर संशोधन विधेयक पारित, खड़गे ने उठाया शुद्धिकरण का मुद्दा

एजेंसी, नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र वीरवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे।

स्पीकर ओम बिड़ला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं, राज्यसभा में आखिरी दिन एमएमडीआर संशोधन बिल पास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। इधर, विपक्षी सांसद संसद के बाहर बंदर का खिलौना लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है। यानी एक दिन में करीब 6 घंटे कार्यवाही का समय होता है। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन यह करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली। यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्यवाही हुई।

मानसून सत्र में राज्यसभा की बैठकें भी लोकसभा के बराबर रहीं और 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन राज्यसभा में लगभग 37 घंटे 24 मिनट काम हुआ।

- संसद सत्र खत्मः मोदी-शाह व राहुल सदन में रहे मौजूद
- बंदर के खिलौने के साथ विपक्ष ने किया प्रदर्शन

12 नए बिल पेश, 11 दोनों सदनों में पास

2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा व 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल अभी दोनों सदनों से पास नहीं हुआ है। राज्यसभा में पेश किए गए दोनों बिल भी लोकसभा से पास हो चुके हैं।

महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर हमला, अस्पताल में भर्ती

- निहंग ने गुरुद्वारे में कृपाण मारी, हाथ में चोट लगी सुरक्षाकर्मी भी घायल
- महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश

एजेंसी, लुधियाना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में वीरवार को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया। पुलिस ने बताया कि गुरुद्वारा माता साहिब कौर में एक निहंग ने उन पर कृपाण से हमला किया।

बादल के हाथ पर चोट लगी है। उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। सुखबीर सिंह बादल परिवार के साथ नांदेड़ गुरुद्वारा में माथा टेकने गए थे। सुखबीर बादल को उन्हें यशोसाई अस्पताल में भर्ती किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से बात की और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की जांच के आदेश दिए। इस हमले के दौरान बादल के सुरक्षाकर्मी ने भी हमलावर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें वह भी घायल हुआ।

घटना के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अन्य लोगों ने हमलावर को काबू कर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज तथा प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटाई जा रही है।

लाल किला धमाका अलकायदा ने कराया

एजेंसी, नई दिल्ली। लाल किले के पास हुए धमाके में अलकायदा से जुड़े संगठन का हाथ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की 38वीं रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। 10 नवंबर, 2025 की शाम लाल किले के पास हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने इस धमाके को अंजाम दिया। इसमें कहा गया है कि एक्यूआईएस अब छोटे-छोटे सेल के जरिए काम कर रहा है और उसने अपना लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। इससे पहले आई यूएनएससी की 37वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश ने इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया था। यानी इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की लगातार दो रिपोर्टों में दो अलग-अलग आतंकी संगठनों के नाम सामने आए हैं। हालांकि, एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया था कि आरोपी एक्यूआईएस से जुड़े थे।

राहुल ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

- 17 अगस्त को मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल कई याचिकाओं को चुनौती दी है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पास आय ज्यादा संपत्ति है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 17 अगस्त को सुनवाई करेगी।

राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने भी मांग की है। मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया था कि वो राहुल गांधी की संपत्तियों का पता करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश ने याचिका दायर कर कहा है कि राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आरोपों का वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने ये भी कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के मुताबिक उचित कदम उठा सकती हैं। जुलाई में हुई सुनवाई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई के हलफनामे पर अंसतोष जताते हुए कहा कि हलफनामा उसके आदेश के मुताबिक नहीं है।

एयर इंडिया पायलट्स का अब रोज होगा ड्रग टेस्ट

फुकेट-दिल्ली फ्लाइट हादसे के बाद फैसला; पायलट नशे में था

एजेंसी, नई दिल्ली। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी पायलटों की अब रोज जांच होगी कि उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों का नशा तो नहीं किया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। यह टेस्ट आज से अनिवार्य कर दिया गया है। दोनों एयरलाइंस में 5 हजार से ज्यादा पायलट हैं। पिछले हफ्ते फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के एक पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया। दरअसल, इस फ्लाइट के भुवनेश्वर से गुजरते समय अचानक टर्बुलेंस जैसे हालात बने और यह करीब 300 फीट नीचे आ गई थी। जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोटें आई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना के बाद पायलट (कैप्टन) के दो ड्रग्स टेस्ट हुए थे। दोनों टेस्ट पॉजिटिव थे। दूसरे में गांजा पीने की पुष्टि हुई थी। फ्लाइट के पैसेंजर ने आरोप लगाया था कि पायलट नशे में था। पायलट्स के लिए अल्कोहल को लेकर डीजीसीए के नियम बेहद सख्त हैं। एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 24 के तहत, किसी भी पायलट या क्रू मेंबर को उड़ान से 12 घंटे पहले तक किसी भी तरह के मादक पदार्थ या अल्कोहल का सेवन करने की मनाही है। उड़ान के दौरान भी इसका सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

एयरलाइंस ने कहा- भरोसा जीतने के लिए कदम

दोनों एयरलाइंस ने पायलटों से कहा है कि मौजूदा नियमों के तहत प्रतिबंधित सभी नशीले पदार्थों और दवाओं की जांच की जाएगी। पायलटों का टेस्ट गुरुग्राम की अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान होगा। इसके अलावा फ्लाइट के बाद ब्रीफिंग सेंटर, एयरलाइंस के ऑफिस और संबंधित बेस पर भी टेस्ट किए जाएंगे। एयरलाइंस ने कहा कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और उनका भरोसा बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

सीएम रेखा ने गाजीपुर ड्रेन से हिंडन नहर तक दो लेन स्लिप रोड ब्रिज का किया लोकार्पण

- बेहतर सड़कें व आधुनिक कनेक्टिविटी से दिल्लीवासियों को राहत : मुख्यमंत्री

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीरवार को गाजीपुर ड्रेन से हिंडन नहर तक 2 लेन स्लिप रोड ब्रिज का लोकार्पण किया। इस मौके पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, विधायक रविंद्र नेगी, रविकांत, भाजपा जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस नई कनेक्टिविटी से कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों का आवागमन सुगम व यातायात का दबाव कम होगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में विकास का सीधा लाभ लोगों के दैनिक जीवन में दिखाई देने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़कें, सुगम यातायात और आधुनिक कनेक्टिविटी के माध्यम से हमारी सरकार दिल्लीवासियों की जीवन को निरंतर बेहतर बना रही है।

2026-27 में 1.12 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य : मुख्यमंत्री धामी

एजेंसी, देहरादून। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने बड़ी उपलब्धि का दावा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में लखपति दीदियों की संख्या 3 लाख 3 हजार 696 पहुंच गई है। प्रदेश सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक लाख 12 हजार और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मातृशक्ति उत्तराखंड की आर्थिक और सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी संवाहक है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय के नए स्रोत विकसित करने और उनके सम्मान,

- कहा- महिलाएं उत्तराखंड की आर्थिक व सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी संवाहक

सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार नवंबर 2022 में लखपति दीदी योजना शुरू होने के बाद हर साल निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले हासिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रदेश में 3,03,696 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं ने विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से अपनी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक पहुंचाई है।

स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं अनुदान और ऋण आधारित योजनाओं का लाभ लेकर अलग-अलग व्यवसायों से अपनी आर्थिकी मजबूत कर रही हैं। इनमें जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, मसाला निर्माण, हस्तशिल्प, डेयरी एवं पशुपालन, मौन पालन, मशरूम उत्पादन और होमस्टे संचालन प्रमुख हैं। मिलेट आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं मिलेट से तैयार बेकरी उत्पादों का भी निर्माण कर रही हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर आय के नए अवसर विकसित हो रहे हैं।

देश का निर्यात जुलाई में 44.24 अरब डॉलर पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली। देश का निर्यात चालू वित्त वर्ष 2026-27 के जुलाई महीने में 19.63 फीसदी बढ़कर 44.24 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान आयात करीब 17.52 फीसदी बढ़कर 76.22 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे व्यापार घाटा बढ़कर 31.98 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी आंकड़ों में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जुलाई के दौरान निर्यात 17.04 फीसदी की बढ़त के साथ 173.78 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 19.27 फीसदी बढ़कर 292.38 अरब डॉलर रहा। मंत्रालय के मुताबिक जुलाई, 2026 के लिए देश का कुल निर्यात (सामान और सेवाओं को मिलाकर) 80.14 अरब यूएस डॉलर होने का अनुमान है, जो जुलाई, 2025 की तुलना में यह 13.31 फीसदी की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

जनता को जल्द समर्पित होगा दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन: सीएम सुक्खू

190 करोड़ की लागत से बन रहा, मिलेंगी चार सितारा सुविधाएं

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन का दौरा कर भवन के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

उन्होंने निर्माण कार्यों का विस्तृत जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को शेष फिनिशिंग कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि इसे जल्द ही हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निकेतन भवन राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले प्रदेशवासियों, विशेषकर चिकित्सा उपचार और शिक्षा के उद्देश्य से दिल्ली आने वाले लोगों को आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधा उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि इस भवन

में लगभग चार सितारा श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यह दिल्ली आने वाले हिमाचलवासियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण सहायक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित किए जा रहे हिमाचल निकेतन में 107 कमरे, एक रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, दो बहुउद्देशीय हॉल, एक बैठक कक्ष और विद्यार्थियों के लिए डॉर्मिटरी की सुविधा होगी। परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, गार्डन, ईवी चार्जिंग स्टेशन तथा अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शेष कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूरे किए जाएं तथा निर्माण में आवश्यक गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार, मुख्य अभियंता विजय चौधरी, अधीक्षण अभियंता दीपक राज चौहान तथा प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

योगी सरकार ने गोमती को निर्मल बनाने की कवायद तेज की, नदी में गिर रहे 45 नालों को लेकर अब होगी कार्रवाई

एजेंसी, लखनऊ। योगी सरकार राजधानी लखनऊ में गोमती नदी को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

शहर से निकलने वाले सीवेज को सीधे गोमती नदी में पहुंचने से रोकने के लिए नालों की टैपिंग, फ्लो डायवर्जन, एसटीपी की क्षमता बढ़ाने और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद गोमती नदी में गिरने वाले 45 नालों की पहचान हुई है। अब इन नालों के जरिए नदी में पहुंच रहे सीवेज का शोधन सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग एसटीपी से जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। वर्ष 2026 में लखनऊ नगर की अनुमानित आबादी करीब 45.56 लाख है। शहर में कुल 110 वार्ड हैं और करीब 7.52 लाख घर हैं। इनमें से लगभग 4.01 लाख यानी 53.32 फीसदी घर सीवरेज नेटवर्क से जुड़े हैं। ऐसे में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार और नालों के जरिए गोमती में पहुंच रहे प्रदूषित पानी को रोकना नदी संरक्षण के लिए बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में आबादी के सापेक्ष करीब 546.77 एमएलडी घरेलू सीवेज (गंदा और अपशिष्ट जल) उत्पन्न होता है, जबकि वास्तविक डिस्चार्ज करीब 880.70 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) है। इसमें 690.33 एमएलडी सीवेज नालों के माध्यम से और 190.71 एमएलडी सीवर नेटवर्क के जरिए प्रवाहित होता है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि नदियों को स्वच्छ बनाना हमारी प्राथमिकता है। विभाग ने नए नालों की पहचान की है, जिन्हें जल्द शोधित किया जाएगा। इससे शहर के बड़े हिस्से से गुजरने वाली गोमती नदी का स्वरूप बदलेगा। लखनऊ में गोमती नदी करीब 30 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। नगर निगम के रिकॉर्ड में गोमती में गिरने वाले 33 नालों का उल्लेख था।

10 एसटीपी, 629.5 एमएलडी शोधन क्षमता

शहर में उत्पन्न सीवेज के शोधन के लिए कुल 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित हैं। इनकी कुल शोधन क्षमता करीब 629.5 एमएलडी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक वास्तविक डिस्चार्ज और मौजूदा शोधन क्षमता के बीच अंतर बना हुआ है। ऐसे में गोमती में सीधे पहुंचने वाले सीवेज को रोकने के साथ ही शोधन क्षमता को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी है।

आयोजन मुख्यमंत्री ने मुरथल में कौशल केंद्र का किया शुभारंभ, शोधार्थियों को किया सम्मानित

युवाओं के कौशल को मिलेगी नई उड़ान: सीएम नायब सैनी

एजेंसी, सोनीपत। सोनीपत दीनबंधु छोटू राम विज्ञान व प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, मुरथल में वीरवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे।

उन्होंने यूनिवर्सिटी परिसर में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया और वोल्वो आइशर प्रयोगशाला का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शोधार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को तैयार करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र हरियाणा के युवाओं के कौशल, आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला रखेगा। केंद्र में प्रशिक्षण, परीक्षण, निदान, नवाचार और उद्योग अनुकूल कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र तेजी से बदल रहा : महिपाल

प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने कहा आज हम कौशल विकास केंद्र के माध्यम से हरियाणा के युवाओं के भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं। यह केंद्र उद्योग और शिक्षा के संगम का प्रतीक है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र तेजी से बदल रहा है, इसलिए युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। यहां विद्यार्थी वास्तविक प्रणालियों और तकनीकों पर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा वैश्विक स्तर का कौशल प्रमाणपत्र हासिल करेंगे, जिससे देश-विदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को 2047 तक साकार करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में युवा कौशल, नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से प्रदेश और देश को विकसित बनाने में योगदान देंगे।

सर छोटूराम के विचारों का आधुनिक विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी का नाम किसान मसीहा दीनबंधु सर छोटूराम जी के नाम पर है। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा था, जिसमें परिश्रम करने वाले व्यक्ति को सम्मान मिले और गांव का युवा अवसरों से वंचित न रहे। आज शुरू किया गया क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र सर छोटूराम जी के इसी विचार का आधुनिक विस्तार है।

उद्योग व यूनिवर्सिटी के बीच मजबूत सेतु

मुख्यमंत्री ने वीई वाणिज्यिक वाहन लिमिटेड-वोल्वो समूह और आइशर मोटर्स के संयुक्त प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पहल से उद्योग और शैक्षणिक जगत के बीच विश्वास का नया सेतु तैयार हुआ है। शिक्षकों को निरंतर सीखने और विद्यार्थियों को डिग्री के साथ समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने का अवसर मिलेगा।

कृषि दृष्टि व आधुनिक तकनीक का संगम

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सदियों से किसान का हल भारत के भविष्य की दिशा तय करता आया है। आज युवा का कौशल, कंप्यूटर और अभिनव विचार विकसित भारत-विकसित हरियाणा की दिशा तय कर रहे हैं। सर छोटूराम जी की कृषि दृष्टि और आधुनिक तकनीक का यह संगम मुरथल से पूरे प्रदेश के लिए नई प्रेरणा बनेगा।

हिमाचल हाई कोर्ट ने किया साफ, देख-रेख से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जमीन और काश्तकारी विवाद से जुड़े 49 साल पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संपत्ति की केवल लंबे समय तक देखरेख करने वाला केयरटेकर या नौकर उस संपत्ति पर मालिकाना हक या काश्तकारी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। न्यायाधीश रोमेश वर्मा ने करीब 49 वर्ष से चल रहे इस कानूनी विवाद को समाप्त करते हुए प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कानून और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि केवल किसी संपत्ति की देखभाल करने से व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक या किरायेदार नहीं बन जाता।

मामला वर्ष 1976 में उस समय सामने आया था जब पटवारी ने खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी का नाम बतौर किरायेदार दर्ज कर दिया था। हाई कोर्ट ने पाया कि नाम दर्ज करने की प्रक्रिया में हिमाचल प्रदेश लैंड रिकार्ड्स मैन्युअल के नियम 9.8 और 8.15 का पालन नहीं किया गया था। नियमों के अनुसार किसी भी जीवित किरायेदारी को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले तहसीलदार की ओर से दोनों पक्षों को उचित सुनवाई का अवसर दिया जाना जरूरी है। इस मामले में ऐसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

अदालत ने माना कि मालिक की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किया गया। इस प्रकार किए गए बदलाव को कानून की नजर में वैध नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाना अपने आप में उसे संपत्ति का मालिकाना या काश्तकारी अधिकार नहीं दे देता।

परवाणू-शिमला फोरलेन का चीन सीमा तक होगा विस्तार, सरकार तैयार करेगी प्रस्ताव

चीन सीमा तक सड़क नेटवर्क मजबूत करने की तैयारी, रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा प्रस्ताव

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में फोरलेन नेटवर्क को अब सामरिक जरूरतों के अनुरूप चीन सीमा तक विस्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। परवाणू से शिमला तक बन रहे फोरलेन के बाद सरकार अब इसकी कड़ी को आगे बढ़ाकर किन्नौर और चीन सीमा तक ले जाने का मामला केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाने जा रही है। प्रदेश सचिवालय में इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर विचार-विमर्श शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि आगामी मंत्रिमंडल बैठक में प्रस्ताव लाकर केंद्र को भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क को और मजबूत करना तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना है।

परवाणू-शिमला फोरलेन परियोजना को तीन चरणों में विकसित किया जा रहा है। कैथलीघाट तक दो चरणों का काम पूरा हो चुका है, जबकि तीसरे चरण में कैथलीघाट से शिमला तक निर्माण कार्य जारी है। इसके बाद फोरलेन नेटवर्क को रामपुर तक विस्तार देने की मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार अब रामपुर से आगे किन्नौर होते हुए चीन सीमा तक सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। यदि प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलती है तो इस क्षेत्र में सड़क ढांचे को नई मजबूती मिल सकती है।

हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों तक बेहतर सड़क संपर्क का विशेष महत्व है। किन्नौर जिला चीन सीमा से सटा हुआ है और यहां तक मजबूत सड़क नेटवर्क होने से सेना तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों की आवाजाही सुगम हो सकती है। सामरिक जरूरतों के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी बेहतर सड़क सुविधा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में कई इलाकों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क निर्माण चुनौतीपूर्ण है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण निर्माण कार्य में समय और संसाधन दोनों अधिक लगते हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि फोरलेन नेटवर्क के विस्तार से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा के साथ व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। किन्नौर क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़क संपर्क होने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।

परवाणू-शिमला फोरलेन पहले से ही प्रदेश के महत्वपूर्ण सड़क संपर्क का हिस्सा है। इसके निर्माण से शिमला की ओर आने-जाने वाले वाहनों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। कैथलीघाट तक दो चरणों का निर्माण पूरा होने के बाद अब कैथलीघाट से शिमला तक तीसरे चरण का काम चल रहा है। इसके आगे रामपुर तक फोरलेन विस्तार को मंजूरी मिल चुकी है।

5 लाख जमा नहीं किए तो बड़सर स्कूल में नहीं होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह: हाईकोर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के बड़सर स्कूल में आयोजन के लिए पांच लाख रुपये चुकाने होंगे। यदि सरकार ने यह रकम जमा नहीं करवाई तो आयोजन की अनुमति नहीं होगी। हिमाचल हाई कोर्ट ने हमीरपुर जिले के बड़सर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान का उपयोग राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए करने की सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए उपयोग शुल्क के रूप में पांच लाख रुपये का भुगतान स्कूल के बच्चों के लिए वेलफेयर स्कीम के लिए करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि बच्चों के कल्याण के लिए उपयोग की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने उपायुक्त हमीरपुर द्वारा स्कूल के खेल मैदान के अस्थायी उपयोग की अनुमति मांगने वाले आवेदन की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ने बड़सर स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर पहले से कार्ड छपवाने, निमंत्रण देने और अन्य तैयारियां नहीं की होतीं तो अदालत स्कूल परिसर में आयोजन की अनुमति नहीं देती। कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सभी तैयारियां पूरी करने के बाद अदालत से स्कूल परिसर में आयोजन की अनुमति मांगना उचित प्रक्रिया नहीं है। अधिकारियों को पहले अदालत से अनुमति लेनी चाहिए थी और उसके बाद ही आयोजन से जुड़ी तैयारियां शुरू करनी चाहिए थीं।

हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह पहले से सभी तैयारियां कर लेने के बाद अनुमति के लिए अदालत का रुख करना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने राज्य सरकार को सशर्त अनुमति प्रदान कर दी, ताकि स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।

हिमाचल में नए एचआईवी मामलों में 175 प्रतिशत उछाल

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में एचआईवी संक्रमण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बीच संक्रमण के कारणों और नए मामलों से जुड़े आंकड़े चिंता भी बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2025-26 में सामने आए एचआईवी मामलों में 19 फीसदी संक्रमण सिरिंज साझा करने से जुड़ा पाया गया है। वहीं एकीकृत एसटीआई, एचआईवी, टीबी, हेपेटाइटिस बी और सी परीक्षण एवं उपचार अभियान के तहत नए मामलों की संख्या में भी पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं वर्ष 2025-26 में सामने आए मामलों के कारणों के विश्लेषण में 19 फीसदी संक्रमण सिरिंज साझा करने से संबंधित पाया गया। यह आंकड़ा खास तौर पर नशीली दवाओं के सेवन के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली साझा सिरिंज से संक्रमण के जोखिम को सामने लाता है।

प्रदेश में 18 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट

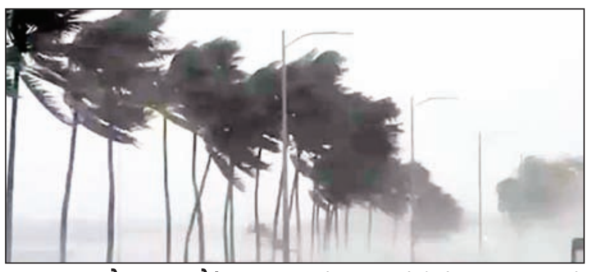

भूस्खलन से 209 सड़कें अवरुद्ध

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच बारिश से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही वर्षा के कारण भूस्खलन और मलबा आने से 209 सड़कें बंद हैं। इससे कई क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच सिरमौर जिले में चंद घंटों के भीतर दूसरा बड़ा हादसा सामने आया। राजगढ़ उपमंडल में तीन मंजिला मकान गिरने से मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि दो छोटी बच्चियां घायल हो गईं। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य किए गए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान भी बारिश से राहत नहीं मिलने का पूर्वानुमान जारी किया है। 18 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ओरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। कई स्थानों पर सड़कों पर मलबा और पत्थर गिरने से यातायात बाधित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के लिए संबंधित विभागों की मशीनरी और कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि बारिश जारी रहने के कारण राहत कार्यों में भी मुश्किलें सामने आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने और संवेदनशील क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है।

प्रदेश में मानसून के कारण पहले भी कई स्थानों पर सड़कें बाधित हुई हैं और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन और विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर 18 अगस्त तक जारी रह सकता है, जिससे सड़कों और अन्य संपर्क मार्गों पर दबाव बना रहने की संभावना है।

एचपीयू में डॉ. आरती पंडित धवन को मिली नई जिम्मेदारी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के ईवनिंग स्टडीज विभाग में प्राचार्य पद का अतिरिक्त कार्यभार अब वाणिज्य विभाग की प्रोफेसर डॉ. आरती पंडित धवन संभालेंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार कुलपति ने डॉ. आरती पंडित धवन को एचपीयू के ईवनिंग स्टडीज विभाग, द मॉल, शिमला के प्राचार्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वह वर्तमान प्राचार्य डॉ. ऊषा रानी के स्थान पर यह जिम्मेदारी संभालेंगी। आदेश के अनुसार डॉ. ऊषा रानी की अधिवर्षता आयु पूरी होने के बाद प्राचार्य पद रिक्त हुआ है। इसके बाद डॉ. आरती पंडित धवन को इस पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगी। डॉ. आरती पंडित धवन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के ईवनिंग स्टडीज विभाग में वाणिज्य की प्रोफेसर हैं।

133 इको टास्क फोर्स ने कुफरी में रोपे 500 पौधे

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। वन महोत्सव 2026 तथा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चलाए जा रहे 'एक पेड़ स्वास्थ्य के नाम' अभियान के तहत 133 इन्फैंट्री बटालियन इकोलॉजिकल डोगरा ने एडवेंचर रिसॉर्ट, कुफरी, शिमला तथा आसपास के क्षेत्रों में सामुदायिक पौधरोपण अभियान आयोजित किया। अभियान का उद्देश्य स्वस्थ पर्यावरण के प्रति सामुदायिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना रहा। इस पहल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया गया। अभियान में स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने पर जोर दिया गया।

यह अभियान वन महोत्सव 2026 के अंतर्गत 133 इको टास्क फोर्स द्वारा मिलिट्री हॉस्पिटल शिमला, कुफरी के स्थानीय निवासियों तथा इको टास्क फोर्स के जवानों के सहयोग से आयोजित किया गया। अभियान में सभी ने मिलकर पौधरोपण किया और पर्यावरण को हरा-भरा बनाने की दिशा में अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक भी किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना को मजबूत करना भी रहा।

मिलिट्री हॉस्पिटल शिमला के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नागराजा एन तथा मैट्रन-इन-चार्ज लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति सुखपाल ने पौधरोपण अभियान का नेतृत्व करते हुए इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी मौजूदगी और सक्रिय भागीदारी ने अभियान में शामिल जवानों तथा स्थानीय लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को सामुदायिक स्वास्थ्य से जोड़ने का संदेश दिया गया। अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण बेहद आवश्यक है। पेड़-पौधे न केवल प्राकृतिक वातावरण को बेहतर बनाते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अभियान के दौरान लगभग 500 पौधों का रोपण किया गया। इतने बड़े स्तर पर पौधरोपण से कुफरी और आसपास के क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिला। पौधरोपण में इको टास्क फोर्स के जवानों के साथ मिलिट्री हॉस्पिटल शिमला के प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हिमाचल में 2175 शिक्षकों की भर्ती अटकी

151 सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का पेच, कैबिनेट में फिर जाएगा प्रस्ताव

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में है। राज्य के 151 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता मिल चुकी है, लेकिन इन स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 2175 शिक्षक पद अभी भी रिक्त हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया लंबे समय से चर्चा में है। सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन कैबिनेट में दो बार चर्चा होने के बावजूद इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। अब शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।

शिक्षकों की भर्ती के लिए सबसे पहले उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपनी सिफारिश में शिक्षकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर करने का सुझाव दिया था। सरकार के सामने रिक्त पदों को जल्द भरने और नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने की चुनौती है। पिछली कैबिनेट बैठक में कमेटी की रिपोर्ट रखे जाने के बाद कुछ वर्गों को नियुक्ति में छूट देने तथा शेष पदों को मेरिट के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया था।

हालांकि अब इस निर्णय को लेकर भी सरकार के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने पूरे मामले पर दोबारा विचार करते हुए नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें सब-कमेटी की सिफारिशों में संशोधन किए जाने की संभावना है। आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की कोशिश करेगी। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यदि किसी वर्ग को नियुक्ति में विशेष छूट दी जाती है तो इसका असर मेरिट सूची पर पड़ सकता है।

शिक्षा विभाग और सरकार इस बात को लेकर भी सतर्क हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह का ऐसा बदलाव न हो जिससे भविष्य में कानूनी विवाद खड़ा हो जाए। यदि मेरिट और छूट के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मामला दोबारा न्यायालय में पहुंचने की आशंका है। इसी कारण सरकार किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने के बजाय सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ इन स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता भी बढ़ी है। 151 स्कूलों में 2175 पदों का रिक्त होना शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विषय है।

हेडटीचर बने जेबीटी को मिलेगा वित्तीय लाभ, सरकार ने दी हरी झंडी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश में हेडटीचर पद पर पदोन्नत जेबीटी शिक्षकों को सरकार के फैसले से राहत मिली है। सरकार ने हेडटीचर पद की पदोन्नति को महज प्लेसमेंट मानने के बजाय नियमित पदोन्नति माना है। इसके बाद पात्र जेबीटी शिक्षकों को पदोन्नति से जुड़े वित्तीय लाभ और वेतन निर्धारण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे लंबे समय से इस मामले को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति भी समाप्त होने की उम्मीद है।

प्रदेश में हेडटीचर पद पर पदोन्नत किए गए जेबीटी शिक्षकों के मामले में वित्तीय लाभ को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। सरकार के स्तर पर इस विषय पर विचार किया जा रहा था। अब विधि विभाग ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को आगे चुनौती देने के बजाय उसे लागू करने की सलाह दी है। विधि विभाग की राय मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने भी इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।

शिक्षा सचिव ने विभाग के निदेशक को पत्र जारी कर विधि विभाग की राय के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद उन जेबीटी शिक्षकों को लाभ मिलने की संभावना है, जिन्हें हेडटीचर पद पर पदोन्नत किया गया है। अब उनकी पदोन्नति को नियमित पदोन्नति माना जाएगा और इसके आधार पर वेतन निर्धारण तथा अन्य वित्तीय लाभ दिए जा सकेंगे।

सरकार के इस फैसले को जेबीटी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का वास्तविक लाभ मिल सकेगा। इससे शिक्षकों के वेतन और पदोन्नति से जुड़े अधिकार भी स्पष्ट होंगे। शिक्षा विभाग को अब आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर पात्र शिक्षकों को वित्तीय लाभ देने की दिशा में कार्रवाई करनी होगी।

कंगना के बयान पर विक्रमादित्य का पलटवार, केंद्र पर साधा निशाना

विक्रमादित्य ने कंगना से पूछा- केंद्र ने पेट्रोल-डीजल कितनी बार बढ़ाया?

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में तेल के दाम बढ़ाए जाने को लेकर सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी पर लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। शिमला में नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सांसद कंगना रनौत को प्रदेश में तेल के दाम बढ़ाए जाने पर सवाल उठाने के साथ केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी पर भी अपनी बात रखनी चाहिए।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत को यह बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कितनी बार बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है और सांसद को इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने इथेनॉल और ब्लेंडिंग जैसे विषयों पर भी बात करने की जरूरत बताई। मंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों और महंगाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते समय केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों को भी सामने रखना चाहिए।

1500 करोड़ देने की घोषणा पर भी उठाए सवाल

विक्रमादित्य ने सांसद कंगना रनौत से प्रधानमंत्री की ओर से हिमाचल प्रदेश के लिए की गई 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि सांसद को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री की ओर से की गई इस घोषणा का क्या हुआ। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के विकास और आर्थिक स्थिति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते समय केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के फैसलों को सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से जुड़े विकास कार्यों, आर्थिक स्थिति और जनता पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर सरकार और विपक्ष के नेताओं को तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। तेल की कीमतों का मुद्दा सीधे तौर पर आम लोगों और परिवहन व्यवस्था से जुड़ा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाले बदलाव का असर आम जनता पर भी पड़ता है।

प्रदेश सरकार की ओर से तेल के दाम में की गई बढ़ोतरी का बचाव करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने जरूरतमंद वर्ग, अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए केवल 60 पैसे की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठाने से पहले केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी पर भी बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते समय पूरे मामले को सामने रखना आवश्यक है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से की गई 60 पैसे की बढ़ोतरी को जरूरतमंद वर्गों के हित में देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस फैसले का बचाव करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव को भी चर्चा का हिस्सा बनाने की बात कही।

बिलासपुर में 80वें जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे पठानिया

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां 15 अगस्त, 2026 को जिला बिलासपुर में पी0एम0 श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर के प्रांगण में 80वें जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कुलदीप सिंह पठानियां 11:00 बजे आयोजन स्थल पर पहुँचेंगे तथा 11 बजकर 2 मिनट पर ध्वजारोहण करेंगे। पठानियां 11 बजकर 5 मिनट पर परेड का निरीक्षण करेंगे तथा मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इससे पूर्व कुलदीप सिंह पठानियां 10 बजकर 40 मिनट पर शहीद स्मारक (चंगर) भी जाएंगे तथा माल्यार्पण करेंगे।

कुलदीप सिंह पठानियां 11 बजकर 20 मिनट पर समारोह में शामिल लोगों को अपने सम्बोधन के माध्यम से शुभ सन्देश देंगे। तदोपरान्त सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे तथा पठानियां अपने कर कमलों द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए चयनित लोगों को पुरस्कार वितरित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। समारोह में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा आम नागरिक भी शामिल होंगे। इस अवसर पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण और मार्च पास्ट समारोह का प्रमुख आकर्षण रहेगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित लोगों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा जाएगा। 15 अगस्त का यह जिला स्तरीय समारोह स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान को स्मरण करने के साथ-साथ देश की एकता, अखंडता और विकास के प्रति संकल्प लेने का अवसर भी बनेगा।

जनगणना जनगणना के लिए 17 अगस्त से मिलेगी ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा

शिमला में जनगणना प्रशिक्षण का दूसरा बैच शुरू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनगणना 2027 के दूसरे चरण को लेकर दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का दूसरा बैच बचत भवन में वीरवार को आरंभ हुआ। इस मौके पर निदेशक जनगणना निदेशालय दीपशिखा शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। निदेशक दीपशिखा शर्मा ने कहा कि दूसरे चरण में करीब 40 प्रश्नों के तहत सूचना एकत्रित की जाएगी। इसमें प्रश्नों की सूची केवल जनसंख्या की संख्या निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार, प्रवास, पारिवारिक और नागरिक पहचान संबंधी स्थिति का विस्तृत चित्र तैयार करने पर केंद्रित है। ऐसे आंकड़े भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आवास, कौशल विकास और अन्य सरकारी योजनाओं की बेहतर योजना एवं लक्ष्य निर्धारण में उपयोगी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में पूर्ण रूप से सही जानकारी ही भरें। जिला स्तर पर अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को जनगणना की प्रक्रिया, निर्धारित मानकों और डिजिटल माध्यम से आंकड़े संकलित करने को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

शिमला में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें जिला, उपमंडल और तहसील स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के लिए जनगणना-2027 का दूसरा चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 1 से 5 अक्टूबर 2026 तक पुनरीक्षण चरण होगा। हिमाचल प्रदेश में यह विशेष समय-सारिणी राज्य की भौगोलिक एवं मौसम संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। दूसरे चरण में प्रगणक घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित निर्धारित जानकारी संकलित करेंगे। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त से 31 अगस्त तक नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। यानी व्यक्ति या परिवार निर्धारित वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जनगणना ड्यूटी में लगे फील्ड स्टाफ अपने चार्ज ऑफिसर को हर दिन रिपोर्ट देंगे, जिसमें उन्हें आने वाली चुनौतियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देनी होगी। इसकी एक प्रतिलिपि जिला राजस्व अधिकारी को सौंपनी होगी। उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि जनगणना कर्मियों के घर पहुंचने पर उन्हें सही, पूर्ण एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाएं तथा जनगणना से संबंधित प्रक्रिया में सहयोग करें। नागरिक यह सुनिश्चित करें कि उनके परिवार एवं घर से संबंधित जानकारी सही तरीके से दर्ज हो।

दूसरे बैच के प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी शिवानी भारद्वाज, ऑफिस कानूनगो सदर ओम प्रकाश सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान जनसंख्या गणना में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों की जानकारी भी दी गई। प्रस्तुत दस्तावेज में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, पारिवारिक, प्रवास तथा पहचान से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाने के लिए प्रश्नों की सूची दी गई है। प्रश्नों का उद्देश्य आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का व्यापक डेटाबेस तैयार करना है।

ठियोग महाविद्यालय में नवागत विद्यार्थियों ने बिखेरा प्रतिभा का रंग, सृजन-2026 में दिखा उत्साह

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राजकीय महाविद्यालय ठियोग में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रथम सेमेस्टर के बी.ए., बी.कॉम. और बी.एससी. के नवागत विद्यार्थियों के स्वागत के लिए गुरुवार को फ्रेशर्स पार्टी सृजन-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के लगभग 500 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. भूपिंदर सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नवागत विद्यार्थियों के स्वागत के लिए गायन, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इनमें मॉडलिंग प्रतियोगिता विद्यार्थियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। मॉडलिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत रैंप वॉक, प्रतिभा प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किए गए। विभिन्न चरणों के आधार पर पियूष को मिस्टर फ्रेशर और स्नेहा को मिस फ्रेशर चुना गया। लड़कों की श्रेणी में सूर्यांश शर्मा और वंशज को क्रमशः प्रथम और द्वितीय रनर-अप घोषित किया गया। छात्राओं की श्रेणी में दीक्षा और अनामिका को क्रमशः प्रथम और द्वितीय मिस रनर-अप का खिताब दिया गया। इसके अतिरिक्त ध्रुवकांत को मिस्टर पर्सनैलिटी तथा आयुषी को मिस पर्सनैलिटी का खिताब प्रदान किया गया। तुषार और दिव्यांशी को क्रमशः मिस्टर टैलेंटेड और मिस टैलेंटेड चुना गया। अनमोल और अतिदी को मिस्टर अटायर और मिस अटायर के खिताब से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. भूपिंदर सिंह ठाकुर ने प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का महाविद्यालय परिवार में स्वागत किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन बनाए रखने तथा शैक्षणिक, सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई देते हुए पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय की डीन छात्र कल्याण डॉ. अनीता राठौर ने भी विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में डॉ. श्रद्धा शांडिल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों और महाविद्यालय के समस्त शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

प्रेमनगर-गढ़ी कैंट की बदहाली पर महानगर कांग्रेस का हल्ला बोल

अनिल थपलियाल

प्रेमनगर एवं गढ़ी कैंट क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही जनसमस्याओं, बदहाल सड़कों, जलभराव, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सीवर एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी ने छावनी परिषद प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी, देहरादून के अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनसमस्याओं को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और छावनी परिषद प्रशासन से समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि प्रेमनगर और गढ़ी कैंट की जनता वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मानसून के दौरान जलभराव, खराब नालियों और क्षतिग्रस्त सड़कें लोगों के लिए परेशानी और दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि दशहरा ग्राउंड स्थित मिनी स्टेडियम का निर्माण पूरा होने के बावजूद उसका संचालन शुरू नहीं किया गया है। प्रेमनगर त्यागी मार्केट का स्मार्ट टॉयलेट भी जनता के उपयोग के लिए शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अनेक स्थानों पर सड़कें और स्ट्रीट लाइटें खराब हैं तथा सफाई और फॉगिंग व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है। डॉ. गोगी ने कहा कि जनता अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर काम चाहती है। छावनी परिषद प्रशासन को चेतावनी है कि प्रेमनगर और गढ़ी कैंट की जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए, अन्यथा महानगर कांग्रेस आंदोलन को और अधिक व्यापक एवं तेज करेगी।

नई तकनीकों के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा दें विश्वविद्यालय : राज्यपाल

कहा- विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों का लाभ विद्यार्थी, समाज और प्रदेश तक पहुंचे

अनिल थपलियाल

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने गुरुवार को लोक भवन में उत्तराखण्ड के स्व वित्तपोषित (निजी) विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित दूसरे चरण की बैठक की। बैठक में 14 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में कुलपतियों ने अपने-अपने विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों और भावी योजनाओं और चुनौतियों की जानकारी दी। इस दौरान अनुसंधान को बढ़ावा देने, पेटेंट संस्कृति विकसित करने, पेटेंट के व्यावसायीकरण, उद्योग-अकादमिक सहयोग, राष्ट्रीय स्तर पर साझा शोध व्यवस्था तथा विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय बढ़ाने से संबंधित

महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए।

बैठक में राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को डिग्री देने के साथ ही उन्हें रोजगार, उद्योग, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए पूर्णत: तैयार करना और वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप सक्षम बनाना होगा। राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान नई शिक्षा नीति-2020 की

- **विद्यार्थियों को रोजगार और राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करें विश्वविद्यालय: राज्यपाल**
- **शिक्षा के साथ युवाओं में नैतिक मूल्य, संस्कार और चरित्र निर्माण पर भी हो जोर**

भावना के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएं और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने युवाओं को सही दिशा देने की है। उन्होंने कहा कि नशे जैसी चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ युवाओं को नशामुक्त और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, संस्कार, परंपराओं और चरित्र निर्माण को भी प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, क्षमता और जिम्मेदारी का विकास भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों को समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि 21वीं सदी में शिक्षा के सामने पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मेटावर्स, सेमीकंडक्टर, स्पेस एवं साइबर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों की चुनौतियां हैं।

स्कूली बच्चों ने थामा 50 मीटर लंबा तिरंगा

रुद्रप्रयाग में 50 मीटर तिरंगे के साथ निकली भव्य रैली, गूंजे भारत माता के जयकारे

अनिल थपलियाल

आगामी स्वतंत्रता दिवस के पावन और गौरवमयी पर्व से पूर्व हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रुद्रप्रयाग जनपद की धरा पर राष्ट्रप्रेम, स्वाभिमान और अटूट राष्ट्रीय एकता का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। जनपद मुख्यालय स्थित आर्मी कैंट के बास्केटबॉल ग्राउंड से अत्यंत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ तिरंगा रैली शुरू हुई, जिसे कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए गुलाबराय मैदान पहुंची, जहां इसका समापन विशाल राष्ट्रप्रेम समागम के रूप में हुआ। रैली का मुख्य आकर्षण स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा श्रद्धा और गरिमा के साथ हाथों में थामा गया 50 मीटर लंबा विशालकाय तिरंगा रहा। हवा में लहराता यह विशाल राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय अखंडता, एकता और भारत की संप्रभुता का सशक्त संदेश दे रहा था।

इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के साथ जिलाधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल, सामाजिक संगठन, वरिष्ठ नागरिक एवं क्षेत्र की जनता पूरी तरह तिरंगामय नजर आई। रैली के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाना और तिरंगे के प्रति सम्मान तथा गौरव को मजबूत करना रहा।

स्किलप्रेन्योरशिप कार्यक्रम में 55 महिलाओं को मिला व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण

अनिल थपलियाल

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा एक्सेंचर कंपनी के वित्तीय सहयोग से दून जिले के नगल बुलंदवाला में महिलाओं के लिए माइक्रो स्किलप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के पांचवें दिन महिलाओं को उद्यमिता एवं व्यवसायिक कौशल से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में यूएसआरएलएम के राज्य परियोजना अधिकारी (आजीविका) मोहन पाण्डेय एवं गिरधर सिंह बिष्ट ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रही 55 महिलाओं के साथ संवाद किया तथा उन्हें उद्यमिता विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मोहन पाण्डेय ने सफल महिला उद्यमियों की प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हुए प्रतिभागियों को अपने हुनर और क्षमताओं को व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सही सोच, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास के साथ महिलाएं न केवल स्वयं रोजगार प्राप्त कर सकती हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं।

उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को टीम वर्क एवं टीम बिल्डिंग के महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने समूह में बेहतर समन्वय, आपसी सहयोग और जिम्मेदारियों के प्रभावी विभाजन के माध्यम से कार्य करने के तरीकों पर प्रकाश डाला।

चमोली में रिश्वत मांगने के आरोपों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

उदित नैनवाल

सोशल मीडिया में प्रसारित एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी गौरव कुमार ने प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यपरक जांच के निर्देश दिए हैं। ग्राम पगना, तहसील चमोली निवासी ताजवर सिंह द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड रूम से पुरानी खतौनी की नकल उपलब्ध कराने के एवज में दो कार्मिकों द्वारा 500 रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने प्रकरण से संबंधित सीसीटीवी फुटेज की जांच किए जाने का भी अनुरोध किया है। प्रकरण की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। समिति में कोषाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली को सदस्य नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने समिति को संबंधित सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट एवं तथ्यपरक जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालयों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नेगी के गीतों ने उत्तराखंड के लोकजीवन और संस्कृति को दी व्यापक पहचान

अनिल थपलियाल

नई टिहरी में गढ़रत्न एवं प्रख्यात लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के 77वें जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार शाम क्रीड़ा भवन में नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और लोकजीवन विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद नई टिहरी के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गोष्ठी में नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन, उनके दीर्घ संगीत सफर तथा उत्तराखंड की लोकभाषा, लोककला, लोकसंगीत और पहाड़ी संस्कृति को संरक्षित एवं समृद्ध करने में उनके योगदान पर चर्चा की गई। नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के गीत सुनकर उत्तराखंड की कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। उनके गीतों में गांव के रिश्तों की आत्मीयता के साथ-साथ पहाड़ के कठिन जीवन की वास्तविक तस्वीर भी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक गांव का जीवन अनेक कठिनाइयों और संघर्षों से भरा है और नेगी जी ने इन वास्तविकताओं को बेहद सहजता से अपने गीतों में उतारा है। जब कोई लोकगायक समाज और आमजन की आवाज बन जाता है तो वह लोकगायक से जनगायक बन जाता है। अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के गीत उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और सामाजिक जीवन का आईना हैं। उनके गीतों में प्रेम और प्रकृति के साथ पहाड़ की सामाजिक परिस्थितियां, गांवों का जीवन, पलायन और विभिन्न सामाजिक मुद्दे भी प्रमुखता से दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि नेगी जी ने अपने गीतों के माध्यम से पहाड़ के सामान्य जनजीवन, गांव-घर, रिश्तों, प्रेम, प्रकृति, परंपराओं, पलायन और सामाजिक सरोकारों को स्वर दिया।

लैंसडौन-यमकेश्वर में भूमि कारोबार की जांच की मांग तेज

अनिल थपलियाल

अधिवक्ता सेवा मंच उत्तराखंड एवं पहाड़ स्वाभिमान सेना ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की खरीद-फरोख्त, भू-कानून के प्रावधानों के कथित दुरुपयोग तथा कृषि भूमि के भूखंडों में परिवर्तन कर बिक्री किए जाने के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अधिवक्ता सेवा मंच उत्तराखंड के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप चमोली एवं पहाड़ स्वाभिमान सेना के अध्यक्ष पंकज उनियाल ने कहा कि यदि इन मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो प्रदेश की बहुमूल्य जल, जंगल और जमीन पर बाहरी भू-माफिया एवं व्यावसायिक संस्थाओं का नियंत्रण लगातार बढ़ता जाएगा।

पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के एराड़ी गांव में दून हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 144 नाली भूमि की खरीद को गंभीर जांच का विषय बताया। आरोप है कि भूमि की खरीद के समय दस्तावेजों में भूमि का प्रयोजन कृषि कार्य दर्शाया गया, जबकि रजिस्ट्री के बाद उक्त भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर बाहरी व्यक्तियों को बेचे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। वक्ताओं ने मांग की कि संबंधित भूमि की खरीद से लेकर वर्तमान स्थिति तक के समस्त राजस्व अभिलेखों, रजिस्ट्री दस्तावेजों, भूमि उपयोग, अनुमति, स्वीकृतियों तथा भूखंडों की बिक्री की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।

पत्रकार वार्ता में यह भी आरोप लगाया गया कि संबंधित कंपनी द्वारा वर्ष 2003 से पूर्व की भूमि खरीद का आधार प्रस्तुत किया जा रहा है और देहरादून में वर्ष 1997 में संपत्ति खरीदने का दावा किया गया है। वक्ताओं के अनुसार, जिस तिथि और पंजीकरण संख्या के आधार पर उक्त संपत्ति का दावा किया जा रहा है, उसके संबंध में उपलब्ध अभिलेखों में प्रथम दृष्टया स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी वर्ष 1995 में गठित होने का दावा करती है, जबकि वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल व्यक्तियों के निदेशक बनने की तिथियां वर्ष 2016 के बाद की बताई जा रही हैं। ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि 2003 से पूर्व की संपत्ति एवं कंपनी की वर्तमान संरचना के बीच वास्तविक कानूनी और स्वामित्व संबंध क्या है।

युवा जीवन में नैतिकता और अनुशासन को दें विशेष महत्व : डॉ. सुनीता भट्ट

अनिल थपलियाल

राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. सुनीता भट्ट ने कहा कि युवा शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी कौशल भी ग्रहण करें ताकि आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सकें। डॉ. भट्ट अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय तपोवन रोड, रायपुर के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि छात्र-छात्राओं को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने युवाओं से जीवन में नैतिक मूल्यों एवं अनुशासन को विशेष महत्व देने का आह्वान किया।

सीआईएमएस एवं यूआईएचएमटी के चेयरमैन एडवोकेट ललित जोशी ने युवाओं को नशामुक्त जीवन अपनाकर अपना भविष्य बनाने का संदेश दिया। साथ ही अपने माता-पिता की हर संभव सेवा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम संचालक व यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉ. अनिल वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस-2026 की थीम विभिन्न संदर्भ, समान आकांक्षाएं विषय प्रवेश करते हुए कहा कि विश्व में विभिन्न सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले युवाओं की समस्याओं तथा समान आवश्यकताओं को समझकर उनका निराकरण करने का प्रयास करना इसका उद्देश्य है।

डॉ. वर्मा ने युवाओं से रक्तदान की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए दूसरों का जीवन बचाने के लिए हर तीन माह में रक्तदान करने का अनुरोध किया। यूसेक्स के संयुक्त निदेशक डॉ. अमित शुक्ला ने कहा कि युवाओं को केवल प्रेरणादायक बातें सुनाना काफी नहीं है बल्कि उनका उचित मार्गदर्शन करते हुए उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलना चाहिए। उन्होंने युवाओं से एड्स के प्रति जागरूक होकर बचने का आह्वान किया।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईएमए में अलंकरण समारोह का हुआ भव्य आयोजन

अनिल थपलियाल

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकादमी में विद्यालय के अलंकरण समारोह का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया। समारोह विद्यालय के प्राचार्य रामचन्द के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। समारोह में विद्यालय के कप्तानों, उपकप्तानों एवं चारों सदनों के कप्तान तथा उपकप्तानों को उनके पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त छात्र पदाधिकारियों ने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने तथा विद्यालय की गरिमा एवं अनुशासन को बनाए रखने की शपथ ली। विद्यालय की मुख्य छात्र परिषद में हेड बॉय के रूप में अर्णव सिंह राणा तथा हेड गर्ल के रूप में अनुवेशा तोपाल को दायित्व सौंपा गया। खेलकूद कप्तान के रूप में बालिका वर्ग से तेजस्वी पवार तथा बालक वर्ग से सिद्धार्थ रावत को चुना गया। अनुशासन कप्तान के रूप में अंशिका मिश्रा तथा अंशुमन सेमवाल ने जिम्मेदारी संभाली। सांस्कृतिक कप्तान के रूप में सृष्टि चंद एवं पीयूष जोशी तथा स्वच्छता कप्तान के रूप में शगुन थापा एवं पीयूष राणा को नियुक्त किया गया। चारों सदनों के कप्तानों एवं उपकप्तानों को भी जिम्मेदारी प्रदान की गई। प्राचार्य मामचंद्र ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सेवा, अनुशासन और दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने का अवसर है।

श्यामपुर में डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा

अनिल थपलियाल

ऋषिकेश विधानसभा के श्यामपुर मंडल में गत दिवस देर शाम ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता ने पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ सहभागिता की। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयघोष के साथ निकली यात्रा ने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस अवसर पर डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि तिरंगा केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और गौरव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देशभर में हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों के बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमारा दायित्व है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करते हुए विकसित एवं सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम् और जय हिंद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। क्षेत्रवासियों ने भी तिरंगा यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में कार्यरत शिक्षकों के लिए होगी अलग टीईटी

- **15 हजार शिक्षकों की टीईटी अनिवार्यता पर सरकार ने शुरू किया मंथन**

अनिल थपलियाल

प्रदेश के करीब 15 हजार शिक्षकों से जुड़ी टीईटी की अनिवार्यता के मामले में अब राहत की उम्मीद जगी है। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी कराने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में लागू व्यवस्था का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मामले को लेकर राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य दिगम्बर सिंह नेगी के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिला और उन शिक्षकों की समस्या रखी, जिनकी नियुक्ति टीईटी अनिवार्य किए जाने से पहले हुई थी।

शिक्षकों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 को कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य किया था। इसके बाद नियुक्त शिक्षकों ने नियमानुसार टीईटी उत्तीर्ण किया है। वहीं, इससे पहले नियुक्त शिक्षकों की भर्ती उस समय लागू सेवा शर्तों और नियमों के आधार पर हुई थी। कई पुराने शिक्षक अब 53 से 54 वर्ष की उम्र में पहुंच चुके हैं। ऐसे में दोबारा पात्रता परीक्षा देना उनके लिए चुनौती है। शिक्षकों का दावा है कि टीईटी से राहत नहीं मिलने पर उनकी पदोन्नति प्रभावित हो सकती है।

छोटे पैकेजों से स्थानीय ठेकेदारों को मिलेगा काम : सतपाल महाराज

- **महाराज ने मुख्यमंत्री धामी से ठेकों को बांटने का किया अनुरोध**

अनिल थपलियाल। उत्तराखंड के लोक निर्माण, सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के बड़े-बड़े ठेकों को छोटे-छोटे पैकेजों में विभाजित किए जाने का अनुरोध किया। श्री महाराज ने कहा कि बड़े ठेकों को छोटे पैकेजों में विभाजित करने से प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से विकास कार्यों में स्थानीय सहभागिता बढ़ेगी और कार्यों के क्रियान्वयन में भी गति आएगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा।

स्थानीय युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

मंत्री ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि प्रदेशहित एवं स्थानीय युवाओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के बड़े ठेकों को छोटे पैकेजों में विभाजित करने की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। उनका कहना था कि छोटे पैकेज होने से स्थानीय स्तर पर अधिक ठेकेदार विकास कार्यों में भाग ले सकेंगे और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतपाल महाराज के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक परीक्षण एवं सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

हिमाद्री आइस रिंक में 17 से 20 अगस्त तक एशियाई मुकाबले

अनिल थपलियाल।

देहरादून में आगामी एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आयोजन 17 से 20 अगस्त तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हिमाद्री आइस रिंक में किया जाएगा। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की आधिकारिक घोषणा की है। लगातार दूसरी बार भारत इस एशियाई प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। इससे देहरादून की पहचान अंतरराष्ट्रीय आइस स्पोर्ट्स और शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत होने की उम्मीद है। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. अमिताभ शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 14 देशों के खिलाड़ियों की भागीदारी की पुष्टि हो चुकी है। हांगकांग, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, मलेशिया, चीनी ताइपे, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, चीन और दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। अब तक 270 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों तथा 102 कोच, रेफरी और अधिकारियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी आईएसयू-मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता मंच है। यह खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्रदान करती है और उन्हें भविष्य की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में सहायता करती है। प्रतियोगिता से उत्तराखंड को खेल और पर्यटन दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलने की उम्मीद है। खिलाड़ियों, कोचों, रेफरी, प्रतिनिधियों और सहयोगी स्टाफ सहित एक हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति अनुमानित है।

उत्तराखंड में पेंशन समावेशन को मजबूत करेगी बैंक और पेंशन फंड की साझेदारी

उदित नैनवाल

देहरादून में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एवं एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमएसएफ (मल्टी स्कीम

फ्रेमवर्क) डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी उत्तराखंड में पेंशन जागरूकता और बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एमओयू पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री हरिहर पटनायक, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ श्री प्रणय रंजन द्विवेदी तथा सीबीओ श्री मुख्तियार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। बैंक ने अपने व्यापक शाखा नेटवर्क के माध्यम से एनपीएस एवं पेंशन समाधान समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

देवग्राम के 27 परिवारों के विस्थापन पर बनी सहमति

उदित नैनवाल

जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसील ज्योतिर्मठ अंतर्गत देवग्राम के 27 परिवारों के विस्थापन से संबंधित प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति ने विस्थापन प्रस्ताव को संस्तुति के लिए शासन को भेजने पर सहमति व्यक्त की। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने समिति को बताया कि देवग्राम के 27 परिवारों के विस्थापन के लिए कुल 1 करोड़ 21 लाख 25 हजार रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में विस्थापित परिवारों के लिए भवन निर्माण, पशुओं के लिए गौशाला निर्माण, विस्थापन भत्ता तथा पुनर्वासित होने वाले ग्रामीण काश्तकारों को पुनर्वास स्थल पर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता सहित अन्य आवश्यक मदों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि देवग्राम के संबंध में इससे पूर्व दो बार भू-वैज्ञानिक जांच कराई जा चुकी है। तहसील स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने सहित विस्थापन से संबंधित अन्य आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक अभिलेख एवं औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए।

नवनियुक्त उप वन संरक्षक प्रणाली रमेश ने पुलिस अधीक्षक से की शिष्टाचार भेंट

उदित नैनवाल

बद्रीनाथ वन प्रभाग की नवनियुक्त उप वन संरक्षक प्रणाली रमेश (भा.व.से.-2023) ने जनपद में अपना पदभार ग्रहण करने के बाद आज पुलिस कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उप वन संरक्षक प्रणाली रमेश ने पुलिस अधीक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिवादन व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक ने भी उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए सफल कार्यकाल की कामना की। मुलाकात के दौरान दोनों अधिकारियों के बीच जनपद में वन एवं पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय और आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हुई। साथ ही वन क्षेत्रों की सुरक्षा, वन अपराधों की रोकथाम, वनाग्नि एवं आपदा जैसी परिस्थितियों में आपसी तालमेल को और मजबूत करने पर भी चर्चा की गई।

पंजाब में चुनावी तैयारियां तेज, राहुल गांधी के दौरे पर टिकी निगाहें

हरमंदिर साहिब में माथा टेककर पंजाब में चुनावी अभियान को गति दे सकते हैं राहुल गांधी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। संसद का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पंजाब पर विशेष ध्यान देने की तैयारी में है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इसी महीने पंजाब दौरे पर आने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेककर पंजाब में कांग्रेस के चुनावी अभियान को गति दे सकते हैं। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के भी पंजाब पहुंचने की संभावना है।

राहुल गांधी के संभावित दौरे को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी नेतृत्व इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहा है। राहुल गांधी के पंजाब पहुंचने पर प्रदेश संगठन की स्थिति, चुनावी रणनीति और पार्टी नेताओं के बीच समन्वय को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

दिल्ली में लगातार हो रहा मंथन : पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात की है। बाजवा की ओर से पंजाब कांग्रेस के विधायकों की राहुल गांधी के साथ बैठक के लिए भी समय मांगा गया है।

इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद राणा गुरजीत सिंह सहित पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इन बैठकों में पंजाब की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, पार्टी संगठन को मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है।

हाईकमान तक पहुंची पंजाब की रिपोर्ट : कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी की टीम पंजाब में पार्टी की चुनावी तैयारियों और संगठन की स्थिति को लेकर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप चुकी है। राहुल गांधी ने पंजाब के कुछ सांसदों से भी मुलाकात कर राज्य में चुनावी तैयारियों की जानकारी ली है। पार्टी की ओर से नेताओं की सक्रियता, संगठन की मजबूती और संभावित चुनावी रणनीति को लेकर विभिन्न स्तरों पर फीडबैक जुटाया जा रहा है। हाईकमान की ओर से पंजाब में प्रमुख नेताओं की स्वीकार्यता और चुनावी संभावनाओं को लेकर सर्वे करवाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सहित अन्य प्रमुख नेताओं को लेकर फीडबैक लिया गया है।

चन्नी-वड़िंग विवाद के बीच दौरा अहम : पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी लंबे समय से हाईकमान के लिए चुनौती बनी हुई है। एक जुलाई को कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस की चुनाव समितियों की घोषणा की थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं।

31 जुलाई से पंजाब के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने करीब दस दिनों में 18 जिलों का दौरा कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कई स्थानों पर चन्नी समर्थकों की ओर से बघेल और राजा वड़िंग के खिलाफ विरोध के स्वर भी सामने आए। ऐसे में चुनाव से पहले संगठन के भीतर चल रही खींचतान को खत्म करना कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ी चुनौती है।

सेक्टर-29 में 7.85 करोड़ से बनेगा आधुनिक कम्युनिटी सेंटर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

सेक्टर-29 में 7.85 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए आधुनिक कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र में सामुदायिक जीवन, सामाजिक समरसता और नागरिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रशासक ने कहा कि किसी शहर की पहचान केवल चौड़ी सड़कों, सुंदर इमारतों और आधुनिक ढांचे से नहीं होती, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि लोगों को आपस में मिलने-जुलने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के कितने अवसर मिलते हैं। नया कम्युनिटी सेंटर बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मनोरंजक गतिविधियों का केंद्र बन सकता है।

उन्होंने कहा कि केंद्र का इस्तेमाल केवल शादी समारोहों के लिए नहीं होना चाहिए। यहां कौशल विकास, रोजगार मार्गदर्शन, खेल, डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण जागरूकता और अन्य सामुदायिक गतिविधियां भी आयोजित की जानी चाहिए। मृत्यु के बाद होने वाली रस्म क्रिया जैसे कार्यक्रमों के लिए भी केंद्र निशुल्क बुक किया जा सकेगा और आयोजन व्यवस्था में नगर निगम की ओर से सहयोग दिया जाएगा।

मेयर सौरभ जोशी ने बताया कि नया कम्युनिटी सेंटर 29,440 वर्ग फुट के प्लाट पर बनाया जाएगा। इसमें भूतल के साथ दो मंजिला भवन होगा और कुल 17,006 वर्ग फुट का कवर्ड एरिया होगा। भूतल 8,511, प्रथम तल 3,968 और द्वितीय तल 4,527 वर्ग फुट का होगा। इसके अलावा 6,600 वर्ग फुट क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।

न्यूज ब्रीफ

ई-केवाईसी नहीं कराई तो महंगा पड़ेगा घरेलू गैस सिलेंडर

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना एलपीजी गैस फेडरेशन ने उपभोक्ताओं से जल्द ई-केवाईसी करवाने की अपील की है। फेडरेशन के पदाधिकारियों के अनुसार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के तहत लंबे समय से उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी के लिए जागरूक किया जा रहा है और निशुल्क शिविर भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद कई उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। फेडरेशन के मुताबिक, 15 अगस्त के बाद बिना ई-केवाईसी वाले उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर करीब 1800 रुपये में खरीदना पड़ सकता है। ऐसे कनेक्शन रद्द भी किए जा सकते हैं।

नोटिस के बावजूद जारी अवैध निर्माण, निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल

भारतेन्दु संवाददाता,जालंधर। एसडी कॉलेज रोड पर अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कॉलेज के सामने पिछले दो महीनों में तीन मंजिला व्यावसायिक इमारतें खड़ी हो गईं। आरोप है कि एक ही प्लाट के तीन हिस्सों में से दो में निर्माण नियमों की अनदेखी कर किया गया। नगर निगम ने दोनों इमारतों पर नोटिस चस्पा किया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि नोटिस के बाद काम रुकने के बजाय निर्माण की गति और बढ़ गई तथा तीसरी मंजिल भी तैयार हो गई। इससे निगम अधिकारियों, निरीक्षक और एटीपी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

भ्रष्टाचार पर विजिलेंस का शिकंजा, 14 आरोपी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता,जालंधर। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुलाई 2026 में 14 अलग-अलग मामलों में 12 सरकारी कर्मचारियों और दो निजी व्यक्तियों सहित 14 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ निजी लोगों की संलिप्तता पर भी नजर रखी जा रही है। जुलाई में भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामले दर्ज किए गए। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भी एक मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा सात आरोपियों के खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें पांच सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

सगू चौक में सरकारी सीसीटीवी उपकरण चोरी, निगरानी हुई ठप

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। सेफ सिटी परियोजना के तहत सगू चौक में लगाए गए सरकारी सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्किंग उपकरण और बैटरियां चोरी होने से इलाके की निगरानी व्यवस्था ठप हो गई। 12 अगस्त को कैमरों का सिग्नल बंद मिलने पर रखरखाव कंपनी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कैबिनेट खोलने पर आठ पोर्ट नेटवर्क पीओई स्विच, बिजली आपूर्ति इकाई और 12 वोल्ट 26 एएच की तीन बैटरियां गायब मिलीं। एचएफसीएल के उप प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे निजी और व्यावसायिक कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

पंजाब कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में निशान कुमार व अन्य बनाम पंजाब सरकार मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भरोसा दिया कि कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने और समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी आदेश अगले दो दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने सरकार का पक्ष रखा। उनके साथ वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा और तरनतारन के उपायुक्त राहुल भी मौजूद रहे। सरकार के आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को सुबह 10 बजे अर्जेंट सूची में रखने के निर्देश दिए।

फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा पर उठे सवाल हाई कोर्ट ने नियुक्तियों पर लगाई रोक

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से 454 फार्मासिस्ट (फार्मेसी ऑफिसर) पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 11 जून 2026 को जारी विज्ञापन के तहत इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने 19 जुलाई 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा को रद करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं के अनुसार परीक्षा के दौरान कथित तौर पर अंतरराज्यीय नकल गिरोह ने नकल करवाने का प्रयास किया था। इसी आधार पर परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इसे रद करने की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा गया। इसके बाद जस्टिस संदीप मौदगिल ने मामले की सुनवाई 17 सितंबर 2026 तक स्थगित कर दी। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि किसी पक्ष की ओर से जवाब दाखिल किया जाना है तो उसे अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले दाखिल किया जाए। साथ ही जवाब की अग्रिम प्रति विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

हाई कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत कहा कि 11 जून 2026 के विज्ञापन के आधार पर फार्मासिस्ट और फार्मेसी ऑफिसर पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। इसका मतलब है कि फिलहाल इन 454 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधी आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

मामले में याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति 19 जुलाई को हुई लिखित परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर है।

सीएसआर फंड के प्रभावी इस्तेमाल के लिए पंजाब में बने प्राधिकरण

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ (यूटी) ह्यूमन राइट्स कमीशन ने प्रदेश में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड के प्रभावी और व्यवस्थित इस्तेमाल के लिए राज्य स्तरीय सीएसआर प्राधिकरण गठित करने की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि ऐसी व्यवस्था से कंपनियों के सीएसआर फंड को स्थानीय कल्याण योजनाओं के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकेगा।

आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस संत प्रकाश और सदस्य जस्टिस गुरबीर सिंह की अगुवाई में यह सिफारिश पंजाब सरकार को भेजी गई है। आयोग ने पिछले वर्ष पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान सीएसआर फंड के इस्तेमाल से जुड़े मामले पर विचार करते हुए कहा कि सीएसआर को केवल कानूनी अनिवार्यता के रूप में नहीं, बल्कि समाज और सरकार के बीच सहयोग तथा सुविधा के माध्यम के तौर पर देखा जाना चाहिए।

आयोग ने बताया कि कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 135 के तहत पात्र कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है। कानून में कंपनियों को अपने संचालन वाले स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है।

आयोग के अनुसार पंजाब में बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय-समय पर जान-माल और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। ऐसे समय सरकार के साथ समाज के विभिन्न वर्ग राहत कार्यों में योगदान देते हैं। आयोग का मानना है कि प्रदेश में काम कर रही पात्र कंपनियों की अधिक भागीदारी से आपदा प्रभावित लोगों तक सहायता तेजी से पहुंचाई जा सकती है।

पंजाब ने 1961 से बकाया जल रायल्टी का भुगतान मांगते हुए राजस्थान को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ जल रायल्टी की मांग पर, पंजाब ने दिया 30 दिन का अल्टीमेटम

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने राजस्थान से नदी जल की आपूर्ति के एवज में 1.44 लाख करोड़ रुपये की रायल्टी और मुआवजे की मांग की है। सरकार ने राजस्थान को अंतिम मांग नोटिस जारी करते हुए 30 दिन के भीतर राशि जमा करने को कहा है। भुगतान नहीं होने की स्थिति में पंजाब ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। पंजाब का दावा वर्ष 1961 से 2025 तक राजस्थान की ओर से इस्तेमाल किए गए नदी जल की रायल्टी से जुड़ा है। इस संबंध में पंजाब के जल संसाधन विभाग ने राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व में कई बार पत्राचार के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इससे पहले 18 मार्च और चार मई को भी राजस्थान सरकार को पत्र भेजे गए थे।

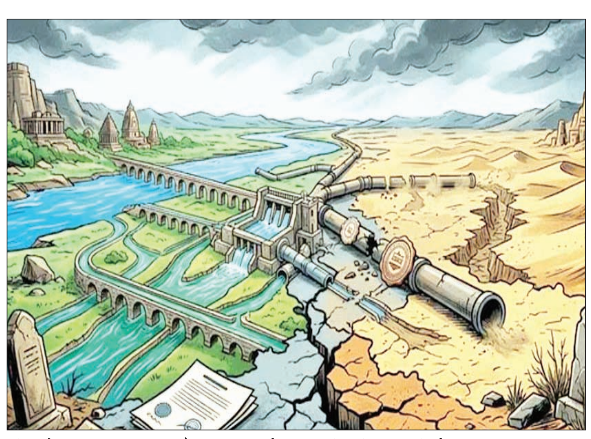

1920 के समझौते को बनाया आधार: पंजाब सरकार ने अपनी मांग का आधार चार सितंबर 1920 को शिमला में बीकानेर, बहावलपुर और पंजाब के तत्कालीन शासकों के बीच हुए जल बंटवारे के समझौते को बनाया है। पंजाब के अनुसार राजस्थान को उपलब्ध कराए जाने वाले पानी के बदले बीकानेर से प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 6.50 रुपये सेस लिया जाता था। बाद में पंजाब ने मौजूदा दर 141.20 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से बकाया राशि की गणना की। इसमें औसतन 10 मिलियन एकड़ फीट पानी की रायल्टी के साथ आठ प्रतिशत ब्याज भी शामिल किया गया है। पंजाब ने यह भी कहा है कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने तक राजस्थान की ओर से रायल्टी का भुगतान किया जाता रहा।

हरियाणा से भी 312.59 करोड़ की मांग : पंजाब सरकार ने हरियाणा से भी भाखड़ा नहर प्रणाली की साझा वाहक नहरों के संचालन और रखरखाव के लिए 312.59 करोड़ रुपये की मांग की है। पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र भेजकर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा है। इसमें भाखड़ा मेन लाइन मंडल के 281.78 करोड़ रुपये और मानसा मंडल के 30.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। पंजाब का कहना है कि हरियाणा ने वर्ष 2015-16 के बाद से नहरों के रखरखाव का भुगतान नहीं किया है।

भाखड़ा नहर की कुल आवंटन क्षमता 12,455 क्यूसेक है। इसमें हरियाणा को 63 प्रतिशत यानी 7,841 क्यूसेक, पंजाब को 25 प्रतिशत यानी 3,108 क्यूसेक पानी मिलता है। राजस्थान का हिस्सा सात प्रतिशत, दिल्ली का चार प्रतिशत और चंडीगढ़ का एक प्रतिशत निर्धारित है।

उधर, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले बकाये के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पंजाब सरकार केंद्र के भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर सहमति के करीब है।

एसडी कॉलेज के बाहर ढाई लाख की हथियार डील नाकाम, पिस्तौल हुई बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित एसडी कॉलेज के बाहर हथियारों की डील होने से पहले ही पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए उसे नाकाम कर दिया। पुलिस ने काले शीशे लगी पंजाब नंबर की एंडेवर कार में घूम रहे एक युवक को दबोच लिया। आरोपित की पहचान फरीदकोट निवासी अरमान प्रीत सिंह के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से ऑस्ट्रिया निर्मित 9 एमएम पिस्तौल बरामद हुई। आरोपित पिस्तौल का लाइसेंस पुलिस के सामने पेश नहीं कर सका।

◆ काले शीशों वाली कार से पहुंचा था सप्लायर, मोबाइल चैट से खुला हथियारों के सौदे का राज

पुलिस के अनुसार अरमान वर्ष 2024 में एसडी कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुका है। सेक्टर-34 थाना प्रभारी शादीलाल की निगरानी में पुलिस टीम रात करीब साढ़े आठ बजे सेक्टर-32डी मार्केट में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक पंजाब नंबर की एंडेवर कार में सवार होकर सेक्टर-32सी स्थित एसडी कॉलेज के बाहर चक्कर काट रहा है। कार के शीशे भी काले थे।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम कॉलेज के बाहर पहुंची। पुलिस को देखते ही चालक ने कार पीछे करने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान कार बंद हो गई। इसके बाद आरोपित कार छोड़कर मौके से भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9 एमएम पिस्तौल बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपित का मोबाइल फोन खंगाला तो उसमें हथियार की खरीद-फरोख्त से संबंधित चैट मिली। जांच में सामने आया कि अरमान किसी व्यक्ति को करीब ढाई लाख रुपये में पिस्तौल बेचने के लिए कॉलेज के बाहर पहुंचा था।

अमृतसर-कनाडा सीधी उड़ान पर अभी इंतजार, केंद्र ने नहीं बताई समयसीमा

अमृतसर से कनाडा के लिए सीधी उड़ान का फैसला एयरलाइंस की मांग और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कनाडा के लिए सीधी उड़ान शुरू होने की मांग के बीच यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भारत और संबंधित देशों के बीच हुए द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते के तहत होता है। एयरलाइंस को निर्धारित क्षमता सीमा के भीतर अमृतसर समेत किसी भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कनाडा जैसे देशों के लिए उड़ान संचालित करने की स्वतंत्रता है। हालांकि, सरकार ने अमृतसर-कनाडा सीधी उड़ान शुरू करने के लिए फिलहाल कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई है।

लोकसभा में अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अमृतसर एयरपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कनेक्टिविटी को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने कनाडा में बड़ी संख्या में बसे पंजाबी प्रवासियों की परेशानी का मुद्दा उठाते हुए अमृतसर से कनाडा के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की जानकारी मांगी थी। उनका कहना था कि सीधी उड़ान नहीं होने के कारण यात्रियों को दिल्ली या किसी विदेशी हवाई अड्डे के माध्यम से यात्रा करनी पड़ती है। इससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं।

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने जवाब में बताया कि वर्तमान में अमृतसर एयरपोर्ट से शारजाह, बर्मिंघम, लंदन, कुआलालंपुर, दुबई, दोहा और सिंगापुर सहित कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। कनाडा के लिए सीधी उड़ान शुरू करने का फैसला एयरलाइंस की व्यावसायिक क्षमता, यात्रियों की मांग, मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य परिचालन कारकों पर निर्भर करेगा।

28 जुलाई से शुरू हुई हब एंड स्पोक सेवा : सरकार ने अमृतसर से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हब एंड स्पोक व्यवस्था शुरू की है। मंत्रालय के अनुसार यह सेवा 28 जुलाई 2026 से शुरू की गई। इस व्यवस्था के तहत अमृतसर जैसे स्पोक एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को वहीं चेक-इन, आव्रजन और सीमा शुल्क की औपचारिकताएं पूरी करने की सुविधा मिल सकती है। इसके बाद यात्री निर्धारित हब एयरपोर्ट के माध्यम से कनाडा सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक पहुंच सकते हैं।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान होने वाली औपचारिकताओं और अतिरिक्त परेशानी को कम करना है। हालांकि, कनाडा में रहने वाले पंजाबी यात्रियों के लिए अमृतसर से सीधी उड़ान अभी भी बड़ी मांग बनी हुई है।

घरेलू उड़ानों का फैसला भी एयरलाइंस पर : सांसद गुरजीत सिंह औजला ने अमृतसर से पूर्वोत्तर, पटना साहिब, नांदेड़ साहिब, चेन्नई और जयपुर जैसे शहरों के लिए सीधी घरेलू उड़ानें शुरू करने की मांग भी उठाई थी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में किसी भी स्थान से घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करना संबंधित अनुसूचित एयरलाइंस का व्यावसायिक निर्णय होता है।

एयरलाइंस यात्री मांग, उपलब्ध स्लॉट, मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और परिचालन संबंधी अन्य परिस्थितियों का आकलन करने के बाद उड़ान शुरू करने का फैसला करती हैं। सरकार विमानन क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराती है, लेकिन एयरलाइंस की परिचालन योजनाओं में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती। ऐसे में अमृतसर से कनाडा के लिए सीधी उड़ान शुरू होने की उम्मीद फिलहाल एयरलाइंस के व्यावसायिक फैसले और यात्रियों की मांग पर टिकी है।

जीरकपुर में 'आप' विधायक के बेटे की कुड़माई में जुटे कई दिग्गज नेता

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर

सनौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के बेटे हरजशन ढिल्लों की तरनजीत सिंह विर्क की बेटी शुभनूर विर्क के साथ कुरमाई (सगाई) हुई। जीरकपुर में आयोजित इस समारोह में पंजाब के कई बड़े राजनीतिक नेताओं सहित परिवार के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। समारोह के दौरान हरजशन और शुभनूर ने परिवार तथा मेहमानों की मौजूदगी में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर अपने रिश्ते को नई शुरुआत दी।

कुरमाई समारोह में दोनों परिवारों के रिश्तेदारों और करीबी लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान नव-मंगेतर जोड़े को बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। मेहमानों ने हरजशन और शुभनूर को जीवन के नए सफर के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। परिवार के सदस्यों ने भी इस खास अवसर पर खुशी जाहिर की।

समारोह में पटियाला के पूर्व मेयर एवं कांग्रेस नेता संजीव बिट्टू भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर नव-मंगेतर जोड़े को बधाई दी। बाद में उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया खाते पर समारोह की तस्वीरें साझा कीं और हरजशन तथा शुभनूर को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं।

आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री एवं समाना से विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने भी समारोह में शिरकत की। उनके अलावा पार्टी के विभिन्न जिला पदाधिकारी और संगठन से जुड़े कई नेता भी कार्यक्रम में पहुंचे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की मौजूदगी के कारण समारोह में खासा उत्साह देखने को मिला।

कार्यक्रम के दौरान परिवार और मेहमानों ने नव-मंगेतर जोड़े के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। समारोह में पारिवारिक खुशी के साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई जानी-मानी हस्तियों की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। दोनों परिवारों के लिए यह अवसर खास रहा और सभी ने हरजशन तथा शुभनूर के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की।

बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल

बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का अंतिम परीक्षण, घाटी में तैयारियां तेज

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। गुरुवार को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। इसी स्टेडियम में 15 अगस्त को कश्मीर संभाग का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रिहर्सल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।

कश्मीर के मंडलायुक्त अंशुल गर्ग ने बख्शी स्टेडियम पहुंचकर फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न सुरक्षा बलों और अन्य टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। जवानों ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनुशासन और कदमताल के साथ परेड की। कार्यक्रम में नागरिक प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में देशभक्ति और उत्साह का माहौल बनाया। वहीं सेना के हेलिकॉप्टरों ने स्टेडियम के ऊपर से उड़ान भरते हुए फूलों की वर्षा की। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों का भी अभ्यास किया गया।

जिला मुख्यालयों पर भी हुई रिहर्सल : स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के साथ घाटी के सभी जिला मुख्यालयों पर भी फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रमों को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य निर्धारित गतिविधियों का अभ्यास किया गया।

मंडलायुक्त अंशुल गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कश्मीर के लोगों से 15 अगस्त के मुख्य समारोह में शामिल होने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपने-अपने जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी भाग लेने का आग्रह किया।

सुरक्षा व्यवस्था को किया गया मजबूत : स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने बताया कि 15 अगस्त के कार्यक्रमों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए घाटी में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सुरक्षा संबंधी तैयारियों का भी परीक्षण किया गया। दक्षिण कश्मीर में हाल में हुए हमलों को देखते हुए संबंधित जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी बढ़ाई गई है।

बिरदी ने बताया कि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा इंतजामों का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है, ताकि वे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक शामिल हो सकें।

लाल किला धमाके को लेकर अटकलों पर सफाई : मीडिया में पिछले वर्ष 25 नवंबर को दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके को लेकर सामने आई उन खबरों के संबंध में भी वीके बिरदी से सवाल किया गया, जिनमें घटना के पीछे अल-कायदा का हाथ होने का दावा किया गया था। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक ऐसी कोई बात उनके संज्ञान में नहीं आई है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में शामिल होकर उन्हें सफल बनाएं। प्रशासन और पुलिस की ओर से लोगों से सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है।

तिरंगे के सम्मान में निकाली एसडीआरएफ रैली, जम्मू में गूंजा देशभक्ति का संदेश

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनजर जम्मू में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रगौरव की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से एसडीआरएफ की ओर से तिरंगा रैली-2026 का आयोजन किया गया। एसडीआरएफ के कमांडेंट मोहम्मद असलम ने एसडीआरएफ बटालियन मुख्यालय जम्मू से तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में एसडीआरएफ के अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

तिरंगा रैली के दौरान एसडीआरएफ कर्मियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। जवानों ने पूरे उत्साह और गर्व के साथ तिरंगा लहराते हुए लोगों को देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश दिया। रैली के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।

रैली एसडीआरएफ बटालियन मुख्यालय से शुरू होकर ग्रीन बेल्ट पार्क, गांधीनगर, पनामा चौक और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। रास्ते में लोगों ने तिरंगा रैली को देखा और जवानों के उत्साह की सराहना की। रैली के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर में देशभक्ति का माहौल बनाने के साथ नागरिकों को राष्ट्रीय पर्व के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में एसडीआरएफ कमांडेंट अल्बीना मलिक, जेकेपीएस डीएसपी दिनेश गुप्ता, डीएसपी लैत कुमार, डीएसपी रोहित देव सिंह सहित एसडीआरएफ के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों और जवानों ने रैली में अनुशासन और उत्साह के साथ भाग लिया।

इस अवसर पर एसडीआरएफ कमांडेंट मोहम्मद असलम ने रैली को सफल बनाने में अधिकारियों और कर्मियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी तथा सराहनीय प्रयासों के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने सभी कर्मियों से राष्ट्र के प्रति सेवा, साहस, अनुशासन और समर्पण की भावना को लगातार मजबूत करने का आह्वान किया।

कमांडेंट ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को याद करने का अवसर भी है। उन्होंने एसडीआरएफ कर्मियों से स्वयं राष्ट्रीय पर्व को गर्व और जिम्मेदारी के साथ मनाने तथा समाज के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया।

स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू में कड़ी सुरक्षा

एमए स्टेडियम समेत सीमांत क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी

संदिग्धों पर नजर, नाके बढ़े; स्टेडियम में प्रवेश से पहले होगी जांच

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न करवाने के लिए जम्मू पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी है। जम्मू संभाग का मुख्य समारोह एमए स्टेडियम में आयोजित होना है। इसके चलते स्टेडियम और आसपास के इलाकों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। स्टेडियम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की जांच की जा रही है।

स्टेडियम के सभी प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर समेत अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं। जांच के बाद ही लोगों और वाहनों को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। बिना उचित कारण स्टेडियम में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सुरक्षा कर्मी स्टेडियम के आसपास आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी लगातार नजर रख रहे हैं।

शहर के संवेदनशील इलाकों में बढ़ी चौकसी : स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीआइजी जम्मू श्रीधर पाटिल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। अधिकारियों को शहर में औचक नाके लगाने और संदिग्ध लोगों तथा वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस की ओर से होटलों में ठहरे लोगों की जानकारी भी जांची जा रही है। पैदल बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है।

सीमांत क्षेत्रों में रात को विशेष निगरानी : जम्मू के सीमांत इलाकों में भी सुरक्षा बलों को विशेष रूप से सतर्क किया गया है। रात के समय गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। सीमा से सटे क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही हैं। पुलिस और सुरक्षा बल शहर से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

1947 के विस्थापन की पीड़ा फिर समिति के सामने गूंजी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जनसांख्यिकी बदलाव पर जम्मू के दौरे पर आई उच्च स्तरीय समिति के समक्ष 1947 में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से हिंदू और सिख समुदाय के विस्थापन का मुद्दा उठाया गया। पीओजेके विस्थापित सेवा समिति ने समिति को ज्ञापन सौंपकर इसे जम्मू-कश्मीर के इतिहास का महत्वपूर्ण और लंबे समय से उपेक्षित अध्याय बताया।

समिति के अनुसार, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के बाद मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, पुंछ और आसपास के क्षेत्रों में हिंसा फैली। समिति ने आरोप लगाया कि इस दौरान हत्याएं, लूटपाट और संपत्तियों की तबाही हुई तथा बड़ी संख्या में हिंदू-सिख परिवारों को अपने घर, जमीन और कारोबार छोड़कर पलायन करना पड़ा। महिलाओं और बच्चों समेत नागरिकों के खिलाफ अत्याचार का भी ज्ञापन में उल्लेख किया गया। समिति ने दावा किया कि करीब 2.5 से 3 लाख हिंदू और सिख विस्थापित हुए, जिससे क्षेत्र के जनसांख्यिकीय स्वरूप में बड़ा बदलाव आया। इसके अलावा 1965 और 1971 के दौरान भी कई क्षेत्रों से हजारों परिवार विस्थापित हुए।

जम्मू-कश्मीर में बरसेंगे बादल, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश से बढ़ी चिंता, 19 अगस्त तक भारी वर्षा के आसार

भारी बारिश से अचानक बाढ़ और भूस्खलन का बढ़ा खतरा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कभी बारिश तो कभी चिलचिलाती धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सावन के मौसम में लगभग हर दिन कहीं न कहीं बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। पुंछ में 53 मिलीमीटर, पुलवामा में 57.5 मिलीमीटर, अवंतीपोरा में 47.8 मिलीमीटर और राजौरी में 44 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।

मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान सुबह और दोपहर बाद कुछ इलाकों में तेज बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम में लगातार बदलाव के कारण लोगों को उमस और गर्मी से राहत के साथ अचानक तेज बारिश का सामना करना पड़ सकता है।

16 से 19 अगस्त तक भारी बारिश के आसार : मौसम विभाग ने 16 से 19 अगस्त के बीच विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इस अवधि में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश और तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं कश्मीर संभाग के एक-दो जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है।

20 से 22 अगस्त तक भी जारी रहेगा बारिश का दौर : मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 से 22 अगस्त के बीच भी जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि इस अवधि में बारिश की तीव्रता पहले की तुलना में कम रहने की संभावना है।

अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा : तेज बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन तथा मलबा गिरने की आशंका जताई है। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन और संबंधित विभागों को भी मौसम की स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है।

बारिश के दौरान नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करते समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने और आवश्यक होने पर यात्रा टालने की सलाह दी गई है।

लद्दाख में चार घंटे के भीतर आए दो भूकंप के झटकों से दहले लोग

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू । केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में गुरुवार को करीब चार घंटे के भीतर मध्यम तीव्रता के दो भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार आए भूकंप के झटकों से लेह और आसपास के क्षेत्रों में लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, अभी तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार पहला और सबसे तेज भूकंप सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर आया। इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र 36.88 डिग्री उत्तर अक्षांश और 74.402 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित था। भूकंप का केंद्र लेह क्षेत्र में जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है।

इसके बाद कल सुबह 9 बजकर 54 मिनट पर एक और भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 4.3 रही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दूसरे भूकंप का केंद्र 36.76 डिग्री उत्तर अक्षांश और 75.326 डिग्री पूर्व देशांतर पर था। यह भूकंप भी लेह क्षेत्र में करीब 10 किलोमीटर की गहराई में आया।

लगभग चार घंटे के अंतराल में दो बार भूकंप के झटके महसूस होने से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई। कई लोगों ने अचानक धरती हिलने का अनुभव किया। भूकंप के बाद लोग किसी संभावित बड़े झटके की आशंका को लेकर सतर्क नजर आए।

लद्दाख भूकंपीय गतिविधियों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहां समय-समय पर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कम गहराई में आने वाले भूकंप के झटके आसपास के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक महसूस किए जा सकते हैं।

पांच वर्षों में नशा पीड़ितों के उपचार का आंकड़ा सबसे अधिक रहा

जम्मू-कश्मीर में नशे का बढ़ता संकट, 46 हजार से अधिक मरीजों ने कराया इलाज

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में नशे की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है और खासकर युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश के नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार के लिए पहुंचने वाले पीड़ितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान जम्मू-कश्मीर में समर्थित नशा मुक्ति केंद्रों में 46,491 लोगों का उपचार किया गया, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में 5,382 लोगों का उपचार हुआ था। 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 27,843, 2023-24 में 40,546 और 2024-25 में 36,588 रही। वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा 46,491 तक पहुंच गया।

जम्मू जिले में सबसे अधिक उपचार : वर्ष 2025-26 में जिलेवार आंकड़ों में जम्मू सबसे आगे रहा। यहां 9,960 लोगों का उपचार किया गया। श्रीनगर में 6,204, बांडीपोरा में 5,769, कुलगाम में 5,765, राजौरी में 5,561, कुपवाड़ा में 4,530, पुलवामा में 3,433 और बड़गाम में 2,693 लोगों का उपचार हुआ। सरकार के अनुसार एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के वर्ष 2018 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में जम्मू-कश्मीर में करीब 5.4 लाख लोगों के ओपियाड सेवन का अनुमान लगाया गया था। 10 से 75 वर्ष की आयु वर्ग में ओपियाड सेवन की अनुमानित दर 4.91 प्रतिशत थी।

33 केंद्रों के माध्यम से उपचार : केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में एकीकृत पुनर्वास केंद्र, तीन आउटरीच एवं ड्राप-इन केंद्र, दो समुदाय आधारित कार्यक्रम, छह जिला नशा मुक्ति केंद्र और 21 उपचार सुविधाओं सहित कुल 33 केंद्रों को समर्थन दे रही है।

कटरा तक बढ़ेगी साबरमती एक्सप्रेस, वैष्णो देवी भक्तों को बड़ी राहत

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे बोर्ड ने साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस को जम्मू तवी से आगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। विस्तारित सेवा जम्मू के रास्ते चलेगी और कटरा पहुंचने से पहले उधमपुर के शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन पर रुकेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी भारत से आने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। अभी यात्रियों को जम्मू तवी उतरकर बस या अन्य साधनों से कटरा जाना पड़ता है। ट्रेन के कटरा तक पहुंचने से उन्हें वाहन बदलने और अतिरिक्त खर्च की परेशानी से राहत मिलेगी।

फेंसिंग में चमका जम्मू-कश्मीर श्रेया ने जीता ऐतिहासिक स्वर्ण

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर की अंतरराष्ट्रीय फेंसिंग खिलाड़ी श्रेया गुप्ता ने नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कामनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 9 से 14 अगस्त 2026 तक आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में श्रेया जम्मू-कश्मीर की पहली महिला फेंसर बनीं, जिन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे केंद्रशासित प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल है।

भारतीय टीम की जीत में श्रेया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शानदार प्रदर्शन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जम्मू-कश्मीर की फेंसिंग प्रतिभा को नई पहचान दिलाई। श्रेया की सफलता को प्रदेश के खेल जगत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।

इसी प्रतियोगिता में जम्मू-कश्मीर के पुरुष फेंसिंग खिलाड़ी विशाल थापर ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पुरुषों की टीम सेबर श्रेणी में रजत पदक अपने नाम किया। इस तरह जम्मू-कश्मीर ने प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर दोहरी सफलता हासिल की।

युवा, सेवा एवं खेल विभाग के आयुक्त सचिव डा. शाहिद इकबाल चौधरी ने श्रेया गुप्ता और विशाल थापर को बधाई देते हुए उनके समर्पण और मेहनत की सराहना की। जम्मू-कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल ने भी दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की।

तवी नदी किनारे एनसीबी की बड़ी कार्रवाई में 438 ग्राम हेरोइन बरामद; हथियारबंद तस्कर हुआ फरार

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जम्मू जोनल यूनिट ने बुधवार को तवी नदी के किनारे निचले रगोड़ा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। विशेष खुफिया सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एनसीबी की टीम ने 438 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की। कार्रवाई के दौरान टीम को हथियारबंद व्यक्ति से खतरा पैदा हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत अधिकारी ने सुरक्षित दिशा में हवा में दो चेतावनी गोलियां चलाईं। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

बताया गया कि एनसीबी की टीम को तवी नदी के किनारे संदिग्ध लोगों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद अधिकारियों ने इलाके में अभियान चलाया। नदी के बहाव क्षेत्र, दलदली जमीन और घनी ऊंची घास के कारण अभियान काफी चुनौतीपूर्ण था। टीम ने सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हुए संदिग्धों को घेरा और एक व्यक्ति के कब्जे से 438 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की।

हथियार दिखाकर टीम को धमकाने का प्रयास : कार्रवाई के दौरान पकड़े गए व्यक्ति के एक सहयोगी ने अचानक हथियार निकाल लिया और एनसीबी टीम को धमकाने का प्रयास किया। इससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अधिकारियों को अपनी सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने पड़े। अधिकृत अधिकारी ने हवा में दो चेतावनी शॉट दागे। इसके बाद हथियारबंद व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा।

एनसीबी टीम ने फरार आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन नदी किनारे के कठिन भू-भाग और घनी वनस्पति का फायदा उठाकर वह वहां से निकल गया। वहीं उसके एक साथी को टीम ने पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।

बीएसएफ ने भी किया सहयोग : ऑपरेशन को सफल बनाने में सीमा सुरक्षा बल ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। दोनों सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से बरामद मादक पदार्थ को सुरक्षित कब्जे में लिया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया।

कारीगरी पचास हजार महिला कारीगरों को मिलेगा बाजार, क्यूआर कोड से उत्पादों की प्रामाणिकता और पहचान होगी सुनिश्चित

जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार देगा नया कारीगरी मंच

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रामाणिक हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए बुधवार को 'जेके कारीगरी' नाम से आधिकारिक बाजार मंच शुरू किया। इसका शुभारंभ नई दिल्ली में आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव के दौरान किया गया। आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना, पारंपरिक हस्तकलाओं का संरक्षण करना और टिकाऊ आजीविका के अवसर पैदा करना है।

'जेके कारीगरी' मंच पर कश्मीर के प्रामाणिक हस्तशिल्प में पश्मीना, कानी और सोजनी शॉल, कागजी लुगदी कला, अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, क्रूएल कढ़ाई और कालीन जैसे उत्पाद उपलब्ध होंगे। जम्मू क्षेत्र के उत्पादों में चबड़ी, मैक्रेमे से बने घरेलू एवं सजावटी सामान, धार्मिक सजावटी वस्तुएं, पारंपरिक खाद्य उत्पाद और लकड़ी से तैयार हस्तशिल्प शामिल किए जाएंगे।

क्यूआर कोड से मिलेगी उत्पाद की पूरी जानकारी : मंच पर सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पाद के साथ क्यूआर कोड उपलब्ध रहेगा। इसे स्कैन करने पर खरीदार को कारीगर की जानकारी, उत्पाद से जुड़े जिले और भौगोलिक संकेतक संबंधी विवरण मिल सकेगा। इससे ग्राहक उत्पाद की प्रामाणिकता और उसके निर्माता की पहचान की पुष्टि कर सकेंगे। उत्पाद की बिक्री से मिलने वाला भुगतान सीधे कारीगर समूहों तक पहुंचेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और कारीगरों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

आयुक्त सचिव मंदीप कौर ने 'जेके कारीगरी' को शहरी महिला कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह मंच महिला कारीगरों को स्थानीय बाजारों से आगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंच बनाने का अवसर देगा।

योजना से 50 हजार महिलाएं जुड़ीं : अधिकारियों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत करीब चार हजार स्वयं सहायता समूहों से लगभग 50 हजार महिलाएं जुड़ी हैं। सरकार स्वयं सहायता समूहों के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए दूसरे राज्यों के साथ सहयोग की संभावनाएं भी तलाश रही है, ताकि स्थानीय उत्पादों को देशभर में व्यापक बाजार मिल सके।

मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी दिया गया है। इससे उनकी कारीगरी, उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद तैयार करने की क्षमता में सुधार हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण के जरिए महिलाएं अपने पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार की मांग के अनुसार विकसित कर रही हैं।

सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, अच्छे रिश्तों और सकारात्मक भावनाओं से भी मिलती है

सुखदेव सिंह
नूरपुर, जिला कांगड़ा

सप्ताह के सात दिनों में शुक्रवार का अपना विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में शुक्रवार को सुख, समृद्धि, सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा दिन माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार का दिन जीवन में धन, वैभव, शांति और खुशहाली का प्रतीक है। हालांकि शुक्रवार का महत्व केवल धार्मिक विश्वासों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन जीवन में संतुलन, प्रेम और अच्छे विचारों को अपनाने की प्रेरणा भी देता है।

भारतीय परंपरा में माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना गया है। शुक्रवार के दिन कई लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपने घर में सुख शांति तथा समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि स्वच्छता, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए शुक्रवार को घर की साफ सफाई, पूजा पाठ और जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसे कार्यों को शुभ माना जाता है।

ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। शुक्र को प्रेम, कला, सौंदर्य, भौतिक सुख और रचनात्मकता का कारक माना गया है। जिन लोगों के जीवन में शुक्र का प्रभाव मजबूत होता है, उनमें कला, संगीत, सौंदर्य और सामाजिक संबंधों के प्रति रुचि अधिक होने की मान्यता है। शुक्रवार का दिन व्यक्ति को अपने जीवन में सुंदरता और सकारात्मकता बढ़ाने का संदेश देता है।

शुक्रवार केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सप्ताह भर की भागदौड़ के बाद यह दिन व्यक्ति को अपने परिवार, मित्रों और स्वयं के लिए समय निकालने का अवसर देता है। आधुनिक जीवन में जब लोग काम और जिम्मेदारियों के दबाव में रहते हैं, तब शुक्रवार उन्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

परिवार और रिश्तों के लिए भी शुक्रवार का विशेष महत्व माना जा सकता है। जीवन में धन और सफलता के साथ प्रेम, सम्मान और आपसी सहयोग भी जरूरी हैं। मजबूत रिश्ते व्यक्ति को मानसिक शांति और भावनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं। शुक्रवार हमें यह संदेश देता है कि जीवन की वास्तविक समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि अच्छे संबंधों और सकारात्मक भावनाओं से भी प्राप्त होती है।

आज के समय में सफलता की दौड़ में लोग कई बार मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में शुक्रवार का महत्व और बढ़ जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में काम और आराम के बीच संतुलन आवश्यक है। अपनी रुचियों को समय देना, परिवार के साथ जुड़ना और अच्छे कार्यों में भाग लेना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।

शुक्रवार कला और रचनात्मकता से भी जुड़ा दिन माना जाता है। संगीत, साहित्य, चित्रकला और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह दिन प्रेरणा का प्रतीक हो सकता है। रचनात्मक सोच व्यक्ति को नई ऊर्जा देती है और जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करती है।

समाज में शुक्रवार का एक महत्वपूर्ण संदेश सेवा और सहयोग का भी है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। समृद्धि का वास्तविक अर्थ केवल स्वयं की उन्नति नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाना है। आधुनिक युग में भले ही जीवन शैली बदल गई हो, लेकिन शुक्रवार जैसे दिनों से जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावनाएँ आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भौतिक विकास के साथ मानसिक शांति और नैतिक मूल्यों का होना भी जरूरी है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

अतुल्य भारत से मजबूत हुई देश की वैश्विक पहचान, पर्यटन को मिला नया विस्तार

डॉ. राज कुमारी
साइकोलॉजिस्ट

भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहरों, आध्यात्मिक परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य और अतिथि सत्कार के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। इन्हीं विशेषताओं को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2002 में अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थापित करना, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना तथा देश की सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना था।

अतुल्य भारत अभियान ने भारत की विविधता को उसकी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर केरल के बैकवाटर्स, राजस्थान के ऐतिहासिक किलों से लेकर गोवा के समुद्री तटों, काशी की आध्यात्मिक संस्कृति से लेकर पूर्वोत्तर भारत की प्राकृतिक सुंदरता तक, इस अभियान ने भारत के विविध पर्यटन स्थलों को आकर्षक ढंग से दुनिया के सामने रखा। आधुनिक विज्ञापन, डिजिटल मीडिया, वृत्तचित्रों और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेलों के माध्यम से भारत की सकारात्मक छवि को मजबूत किया गया।

इस अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी 'अतिथि देवो भव:' रही, जिसका उद्देश्य देशवासियों में पर्यटकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार और आतिथ्य की भावना को विकसित करना था। इस पहल के माध्यम से होटल कर्मियों, टैक्सी चालकों, पर्यटन गाइडों तथा पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य लोगों को शिष्टाचार, स्वच्छता और बेहतर व्यवहार का प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय संस्कृति का यह मूल मंत्र केवल एक नारा नहीं, बल्कि देश की परंपरा और पहचान का प्रतीक बन गया।

समय के साथ अतुल्य भारत अभियान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। सोशल मीडिया, वीडियो अभियानों, वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से देश-विदेश के पर्यटकों तक भारत की विविधता और पर्यटन सुविधाओं की जानकारी पहुंचाई गई। इन प्रयासों से भारत की वैश्विक ब्रांडिंग को नई पहचान मिली और पर्यटन क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सांस्कृतिक विरासत, योग, आध्यात्मिक पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख किए जाने से भी इस अभियान को नई गति मिली। हालांकि, इस अभियान को कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के अनेक कम प्रसिद्ध लेकिन अत्यंत सुंदर पर्यटन स्थलों को अपेक्षित प्रचार नहीं मिल पाया। कई क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, परिवहन और पर्यटकों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।

यदि इन कमियों को दूर किया जाए और ग्रामीण, साहसिक, पारिस्थितिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन को समान महत्व दिया जाए, तो भारत पर्यटन के क्षेत्र में और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आज पर्यटन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। अतुल्य भारत अभियान ने भारत की सकारात्मक वैश्विक छवि बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, आधुनिक आधारभूत सुविधाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी प्राथमिकता दी जाए। निस्संदेह, अतुल्य भारत केवल एक पर्यटन अभियान नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक समृद्धि और अतिथि देवो भव: की भावना का वैश्विक परिचय है।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

संपादकीय

युवाओं को दें बेहतर अवसर

आज हिमाचल प्रदेश के सामने खड़ी सबसे गंभीर सामाजिक चुनौतियों में से एक चिट्टा बन चुका है। यह समस्या केवल नशे तक सीमित नहीं है बल्कि युवाओं के भविष्य, परिवारों की खुशियों और समाज की संरचना को प्रभावित करने वाला संकट बन गई है। जिस तरह कोई बीमारी धीरे-धीरे शरीर को कमजोर कर देती है उसी तरह चिट्टा भी समाज की जड़ों को कमजोर कर रहा है। हालांकि हर बीमारी का उपचार संभव है बशर्ते समय रहते सही दिशा में ईमानदार प्रयास किए जाएं। चिट्टे के खिलाफ लड़ाई कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टे के खिलाफ जिस व्यापक अभियान की शुरुआत की है वह निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अवैध संपत्तियों को जब्त करना और नशे के नेटवर्क को तोड़ने के प्रयास यह संदेश देते हैं कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है। जब नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में कानून का भय पैदा होगा तभी इस अवैध धंधे पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। नशा माफिया केवल पैसे का कारोबार नहीं करता बल्कि वह युवाओं के सपनों, परिवारों की उम्मीदों और समाज के भविष्य को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई समय की मांग है।

सरकार को आपूर्ति श्रृंखला पर प्रहार करने के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नशे की उपलब्धता को कम किया जाए। जब तक चिट्टा आसानी से उपलब्ध होता रहेगा तब तक केवल गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। नशे की तस्करी से जुड़े छोटे स्तर के लोगों से लेकर बड़े नेटवर्क तक की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। डिजिटल माध्यमों और आधुनिक तकनीक का उपयोग भी नशे के नेटवर्क की पहचान और उसे तोड़ने में प्रभावी साबित हो सकता है।

लेकिन केवल कानून का डर पैदा करके चिट्टे की समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण पक्ष नशे की मांग को कम करना है। इसी दिशा में खेलों और युवाओं की भागीदारी के माध्यम से चलाया जा रहा खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान एक सराहनीय प्रयास है। युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना इस लड़ाई का सबसे प्रभावी माध्यम हो सकता है। खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टीम भावना पैदा करते हैं। जो युवा खेलों से जुड़ते हैं उनके सामने अपनी प्रतिभा को विकसित करने और भविष्य बनाने के नए अवसर खुलते हैं। इससे उन्हें नशे जैसी विनाशकारी प्रवृत्तियों से दूर रखने में मदद मिल सकती है।

समाज में यह धारणा बदलने की भी जरूरत है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी है। वास्तव में यह पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, पंचायतें, सामाजिक संस्थाएं, युवा संगठन और धार्मिक संस्थाएं मिलकर इस अभियान को मजबूत बना सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में चिट्टे का कारोबार बढ़ रहा है तो वहां के लोगों को चुप रहने के बजाय प्रशासन को सूचना देने और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। नशे के कारोबार को सामाजिक स्वीकृति या मौन समर्थन किसी भी स्थिति में नहीं मिलना चाहिए।

नशे की शुरुआत कई बार जिज्ञासा, दोस्तों के दबाव या तनाव के कारण होती है। युवा शुरुआत में इसे केवल प्रयोग समझ सकते हैं लेकिन धीरे-धीरे यह गंभीर लत में बदल सकती है। इसलिए शुरुआती स्तर पर पहचान और परामर्श बेहद जरूरी है। अभिभावकों को अपने बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई में अचानक गिरावट, व्यवहार में बदलाव, दोस्तों का बदलना, परिवार से दूरी या लगातार तनाव जैसी परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे समय में डांट या सामाजिक दबाव के बजाय संवाद और समझदारी से काम लेना जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश में चिट्टे से प्रभावित पंचायतों की संख्या चिंता का विषय है। सरकार को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाने चाहिए। केवल एक-दो कार्यक्रम आयोजित करके समस्या का समाधान नहीं होगा। खेल गतिविधियां, युवा संवाद, करियर मार्गदर्शन, नशामुक्ति जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाने चाहिए। युवाओं के पास यदि शिक्षा, रोजगार, खेल और रचनात्मक गतिविधियों के पर्याप्त अवसर होंगे तो वे नकारात्मक रास्तों से दूर रह सकेंगे।

पुलिस की भूमिका भी इस अभियान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस को केवल गिरफ्तारी और कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि जनजागरूकता में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। गांव-गांव जाकर युवाओं और अभिभावकों से संवाद करना, नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देना और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक करना प्रभावी कदम हो सकते हैं।

-शिवांश धाकड़

कविता

चौकीदारों को खून भाया

भीम बसेड़ू राजपूत, महादेव (मंडी)

बरसाई लाठी तानी गन, शर्मसार किया लोकतंत्र हमारा
केंद्र ने बल प्रयोग कर जग हंसाई है करवाई
प्रदर्शन करते युवाओं को खूब पीटा मारा
काले अंग्रेजों, उन्होंने तुम्हारा क्या था बिगाड़ा
ऊंची आवाज में ही तो सुनाने गए थे
ऊंचा सुनने वाली राजधानी दिल्ली को हक-इंसाफ मांगने वालों को
फिर ऐसे क्यों तड़पाया आई कहां से सोच यह सब फिरंगी और गुलाम की
लाठीचार्ज किया संसद की नाक तले, जबरदस्त है कहर बरपाया
भविष्य की आवाज दबाने कैसे-कैसे हुक्मरान हैं आए
भ्रष्टाचार निरंतर पेपर लीक ने धकेला पीछे देश को
काबिल घुट-घुट मर रहे क्यों छीन रहे हमसाया
बरसते आंसू गैस के गोलों से भिड़ते आगे बढ़ते
आज उतरा है युवा भारत सड़क पर
और जंतर-मंतर के चौकीदारों को खून है भाया।

हर समय मोबाइल से जुड़े रहने की आदत से कैसे बदल रही है हमारी दिनचर्या

धर्म देवा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक
गांव धारना, जिला चंबा

आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक अधिकांश लोगों का ध्यान किसी न किसी रूप में मोबाइल स्क्रीन पर रहता है। संदेश देखना, समाचार पढ़ना, सामाजिक माध्यमों पर समय बिताना, वीडियो देखना और काम से जुड़े संदेशों का जवाब देना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। समस्या तब शुरू होती है जब मोबाइल हमारी सुविधा का साधन न रहकर हमारे समय और ध्यान को नियंत्रित करने लगता है। लगातार स्क्रीन देखने, देर रात तक जागने और काम से जुड़े संदेशों के कारण तनाव तथा नींद की समस्या बढ़ सकती है।

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि दिन का कितना समय मोबाइल में निकल गया। कुछ मिनट के लिए फोन उठाने वाला व्यक्ति कब आधे घंटे तक वीडियो देखने या संदेश पढ़ने में व्यस्त हो जाता है, इसका अंदाजा नहीं लग पाता। धीरे-धीरे यह आदत परिवार के साथ बातचीत, पढ़ाई, काम और आराम के समय को प्रभावित करने लगती है। विशेषज्ञों ने भी लगातार डिजिटल जुड़ाव, अधिक काम और खराब नींद के बीच संबंध पर चिंता जताई है।

इस समस्या का समाधान मोबाइल को पूरी तरह छोड़ना नहीं है। जरूरत इस बात की है कि तकनीक का इस्तेमाल हमारी जरूरत के अनुसार हो। सुबह उठते ही फोन देखने के बजाय कुछ समय अपने लिए निकालना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। परिवार के साथ भोजन करते समय फोन अलग रखना, काम खत्म होने के बाद अनावश्यक संदेशों से दूरी बनाना और सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कम करना भी उपयोगी आदतें हो सकती हैं। हाल की जीवनशैली संबंधी सलाह में भी सुबह के शुरुआती समय को बिना फोन और सामाजिक माध्यमों के बिताने तथा विचारों को लिखकर मानसिक बोझ कम करने जैसे छोटे कदमों पर जोर दिया गया है।

दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव बड़ा असर डाल सकते हैं। घर की सफाई करना, कुछ देर टहलना, किताब पढ़ना, परिवार के किसी सदस्य से आमने-सामने बातचीत करना या कुछ समय शांत बैठना मन को राहत दे सकता है। आधुनिक जीवन की तेज गति में ऐसे छोटे विराम व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने का अवसर देते हैं।

आज काम और निजी जीवन के बीच अंतर बनाए रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। मोबाइल ने कार्यालय और घर के बीच की सीमा को काफी हद तक धुंधला कर दिया है। कई लोगों को काम खत्म होने के बाद भी संदेशों और फोन का जवाब देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मानसिक थकान बढ़ सकती है और व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि वह लगातार काम की स्थिति में है।

इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिन में कुछ समय ऐसा रखें जो पूरी तरह हमारा हो। उस समय न काम हो, न मोबाइल की चिंता और न ही दूसरों से तुलना। अपने लिए निकाला गया यह समय किसी विलासिता का हिस्सा नहीं बल्कि संतुलित जीवन की आवश्यकता है। मोबाइल हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, जीवन को चलाने के लिए नहीं। सही संतुलन बनाकर ही हम तकनीक का लाभ लेते हुए अपने रिश्तों, स्वास्थ्य, काम और मानसिक शांति को बेहतर बनाए रख सकते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

प्रकृति की गोद में बसा हिमाचल, मानसून में बढ़ जाता है प्राकृतिक आपदाओं का खतरा

विशाल कल्याण, सहायक प्रोफेसर
महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, सोलन

हिमाचल प्रदेश अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे-ऊंचे पर्वतों, कल-कल बहती नदियों, घने वनों और मनमोहक घाटियों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रकृति ने इस प्रदेश को अद्भुत सौंदर्य का वरदान दिया है, परंतु यही प्रकृति कभी-कभी विकराल रूप धारण कर जनजीवन को गंभीर संकट में डाल देती है।

विशेषकर मानसून के दिनों में होने वाली भारी वर्षा, बादल फटना, भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ तथा पहाड़ों का दरकना प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। प्रत्येक वर्ष अनेक परिवार अपने प्रियजनों, घरों, खेतों, पशुधन और जीवनभर की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। ऐसी परिस्थितियों में केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जागरूकता, सतर्कता और समय पर अपनाए गए एहतियात ही जान-माल की सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम बनते हैं।

हिमाचल प्रदेश का अधिकांश भाग पर्वतीय है। यहां की भौगोलिक संरचना अत्यंत संवेदनशील है। लगातार होने वाली वर्षा के कारण मिट्टी कमजोर हो जाती है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। नदियां और नाले उफान पर आ जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, पुल बह जाते हैं और अनेक गांवों का संपर्क शेष प्रदेश से कट जाता है। चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, किन्नौर तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में समय-समय पर ऐसी प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनसे भारी जन-धन की हानि हुई है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उचित तैयारी और सावधानी अपनाकर इनके दुष्प्रभाव को अवश्य कम किया जा सकता है।

मानसून के मौसम में प्रत्येक व्यक्ति को मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि भारी वर्षा, भूस्खलन अथवा बादल फटने की संभावना व्यक्त की जाए तो अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में रात्रि के समय यात्रा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। तेज वर्षा के दौरान नदियों, नालों और पुलों को पार करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में जलस्तर कई गुना बढ़ सकता है। पहाड़ों से पत्थर गिरने वाले क्षेत्रों में वाहन रोकना या पैदल चलना भी अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यदि किसी क्षेत्र में भूस्खलन की आशंका दिखाई दे, पहाड़ों से छोटे-छोटे पत्थर गिरने लगें, भूमि में दरारें दिखाई दें अथवा असामान्य आवाजें सुनाई दें, तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए और स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए। घरों के आसपास जल निकासी की उचित व्यवस्था रखना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि वर्षा का पानी जमा होकर भवनों की नींव को कमजोर न करें।

बिजली गिरने की संभावना के समय खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों तथा बिजली के खंभों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। बिजली के उपकरणों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए तथा आवश्यकता होने पर मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा के समय अफवाहों से बचना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि वास्तविक खतरे से बचना। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर अनेक भ्रामक सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, जो लोगों में अनावश्यक भय और भ्रम उत्पन्न कर देती हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

स्वतंत्र भारत की पहली सुबह से पहले 14 अगस्त की रात ने लिखी नए राष्ट्र के निर्माण की कहानी

रामलाल पाठक
निहारखन बासला, ब्रह्मपुखर
बिलासपुर (हि.प्र.)

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था। यह वह दिन था जब देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने की दहलीज पर खड़ा था और नई दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी थीं। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होने वाला था, इसलिए 14 अगस्त की रात और उससे पहले का पूरा दिन देश के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में विशेष महत्व रखता है। वर्षों के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद भारत अपने भाग्य का नया अध्याय लिखने जा रहा था। देश के सामने एक ओर स्वतंत्रता की खुशी थी तो दूसरी ओर विभाजन की पीड़ा और उससे पैदा हुई गंभीर परिस्थितियां भी मौजूद थीं।

नई दिल्ली में संविधान सभा की गतिविधियां तेज थीं। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। ब्रिटिश शासन से सत्ता भारतीय नेतृत्व को सौंपे जाने के साथ यह आवश्यक था कि देश के प्रशासन, शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट दिशा तय की जाए। संविधान सभा में देश के भविष्य, शासन व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श हो रहा था। स्वतंत्र भारत के निर्माण की जिम्मेदारी अब भारतीय नेताओं और प्रतिनिधियों के सामने थी।

14 अगस्त की रात संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसे बाद में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के नए युग की शुरुआत की बात कही और देश की सेवा के संकल्प पर जोर दिया। यह अवसर केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि लंबे संघर्ष के बाद भारतीय जनता के आत्मसम्मान और स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा का भी प्रतीक था। संविधान सभा का यह ऐतिहासिक सत्र स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत का महत्वपूर्ण क्षण बना।

सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया भी इसी दौरान अंतिम रूप ले रही थी। ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में सत्ता भारतीय नेतृत्व को सौंपने की तैयारी की जा रही थी। प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे थे। ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय प्रशासन के बीच जिम्मेदारियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। सेना, सरकारी विभागों, संचार व्यवस्था और प्रशासन से जुड़े विषयों को नए राजनीतिक वातावरण के अनुसार व्यवस्थित करना आवश्यक था। देश के सामने एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती थी जो स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

लेकिन 14 अगस्त की खुशी के साथ देश विभाजन की त्रासदी से भी गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान के निर्माण के साथ लाखों लोगों के सामने विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पंजाब और बंगाल सहित कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थीं। बड़ी संख्या में लोग अपने घर और संपत्ति छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर थे। ऐसे कठिन समय में स्वतंत्रता का उत्सव देश के लिए भावनात्मक रूप से बेहद जटिल था। एक ओर सदियों की गुलामी से मुक्ति का सपना पूरा हो रहा था तो दूसरी ओर विभाजन के कारण समाज गहरे दर्द से गुजर रहा था। 14 अगस्त 1947 का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन स्वतंत्र भारत की जिम्मेदारियों का वास्तविक स्वरूप सामने आने लगा था।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

हास्य अभिनय के बादशाह

जॉनी लीवर
जन्म : 14 अगस्त 1957

जॉनी लीवर का जन्म **14 अगस्त** 1957 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। वह भारतीय मनोरंजन जगत के लोकप्रिय हास्य कलाकार और अभिनेता हैं। अपनी खास संवाद अदायगी, चेहरे के हाव-भाव और अलग अंदाज की कॉमेडी के कारण उन्होंने दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनाई। फिल्मों में उनके हास्य किरदारों ने लंबे समय तक लोगों का मनोरंजन किया और उन्हें हिंदी सिनेमा के प्रमुख हास्य कलाकारों में स्थान दिलाया।

जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के कनिगिरी क्षेत्र में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था और उनका पालन-पोषण मुंबई में हुआ। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। शुरुआती दौर में उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए कई तरह के काम किए। इसी दौरान उनकी हास्य प्रतिभा और लोगों को अपनी बातों से हंसाने की कला सामने आई। वह मंच पर कार्यक्रम करने लगे और धीरे-धीरे उनकी पहचान बढ़ती गई।

मंचीय प्रस्तुतियों के दौरान उनकी प्रतिभा पर फिल्म जगत की नजर पड़ी और इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने के अवसर मिलने लगे। उन्होंने अपने अभिनय करियर में अनेक फिल्मों में हास्य भूमिकाएं निभाईं। उनकी अभिनय शैली में संवाद बोलने का विशेष अंदाज, शारीरिक हाव-भाव और परिस्थितियों के अनुसार हास्य पैदा करने की क्षमता प्रमुख रही है। दर्शकों ने उनके किरदारों को खूब पसंद किया।

व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जॉनी लीवर का विवाह सुजाता लीवर से हुआ। उनकी दो संतानें हैं। उनकी बेटी जैमी लीवर भी मनोरंजन जगत से जुड़ी हैं और हास्य प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती हैं। जॉनी लीवर ने अपने परिवार के साथ लंबे समय तक संतुलित जीवन बिताया है और अपने बच्चों को भी कला तथा मनोरंजन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जॉनी लीवर का जीवन संघर्ष, मेहनत और प्रतिभा का उदाहरण माना जाता है। उन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से शुरुआत कर हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी मजबूत पहचान बनाई।

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

यूपी में सात पीसीएस अफसरों के तबादले, कई जिलों के बदले अधिकारी

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गुरुवार सुबह सात पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। शासन की ओर से जारी सूची में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादलों के तहत अलग-अलग जिलों और मंडलों में तैनात अधिकारियों को नई जगह भेजा गया है। माना जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर यह फेरबदल आगामी दिनों में भी जारी रह सकता है और शाम तक तबादलों को एक और सूची सामने आ सकती है। लखनऊ में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात निधि पाण्डेय को जन भवन में कम्पट्रोलर के पद पर भेजा गया है। वहीं ज्योति राय को अपर जिलाधिकारी अपर आयुक्त आजमगढ़ से बलरामपुर मंडल में नई जिम्मेदारी दी गई है। संदीप केला को नगर मजिस्ट्रेट बांदा के पद से स्थानांतरित कर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बलरामपुर बनाया गया है। इसके अलावा बुलंदशहर में उपजिलाधिकारी के पद पर तैनात दिनेश चन्द्र को नगर मजिस्ट्रेट बांदा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंदौली में उपजिलाधिकारी के पद पर तैनात दिव्या ओझा का तबादला करते हुए उन्हें अपर जिलाधिकारी न्यायिक बरेली के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल में विनय कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज से नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर भेजा गया है। इसी क्रम में उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर के पद से स्थानांतरित कर नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है। इस फेरबदल से दोनों प्रमुख शहरों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है। शासन का उद्देश्य अधिकारियों के अनुभव और कार्यक्षमता के अनुसार उन्हें नई जिम्मेदारियां देना माना जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

एलडीए घूसकांड में नया मोड़, 11 इंजीनियर और एक पीसीएस जांच के घेरे में

एजेंसी, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के चर्चित घूसकांड में विजिलेंस जांच का दायरा बढ़ गया है। विजिलेंस विभाग की टीम ने बुधवार को एलडीए मुख्यालय पहुंचकर करीब ढाई घंटे तक संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की। विजिलेंस सूत्रों के अनुसार 11 इंजीनियरों और एक पीसीएस अधिकारी के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की गई है। इससे पहले एक अगस्त को विजिलेंस टीम ने एलडीए के अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और बिचौलिए श्रवण कुमार को ढाई सात लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि व्यावसायिक संपत्ति के निर्माण पर कार्रवाई न करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। अब अवैध निर्माणों को संरक्षण देने और बिचौलियों के माध्यम से काम कराने से जुड़े मामलों की भी जांच की जा रही है।

बूढ़ी गंगा की जन्मपत्री तैयार, 1326 साल पुराने नक्शे खोलेंगे नदी के राज

एजेंसी, मेरठ। बूढ़ी गंगा के सदियों पुराने इतिहास को सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर बूढ़ी गंगा से जुड़े 1326 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मानचित्र और दस्तावेज राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपे गए हैं। इन मानचित्रों में राजा हर्षवर्धन के काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक के विभिन्न दौर की जानकारी शामिल है। दस्तावेजों के माध्यम से बूढ़ी गंगा के उद्गम, पुराने नदी मार्ग, हस्तिनापुर क्षेत्र में इसके विस्तृत प्रवाह और गंगा में इसके मिलन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत मिलने की उम्मीद है। इन ऐतिहासिक प्रमाणों को नदी के वास्तविक स्वरूप और पुराने प्रवाह को समझने में अहम माना जा रहा है। अब इन दस्तावेजों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से शिक्षक भर्तियों का रास्ता होगा साफ

एजेंसी, प्रयागराज। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने शिक्षक भर्ती से जुड़े मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की मांग उठाई है। छात्रों का कहना है कि न्यायालयों में पहले से लंबित मामलों की अधिकता के कारण भर्ती संबंधी विवादों का फैसला आने में लंबा समय लग जाता है। इसका सीधा असर अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ता है। कई बार अगली भर्ती में देरी के कारण बड़ी संख्या में प्रतियोगी अधिक उम्र के हो जाते हैं और अवसर से वंचित रह जाते हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं के मामलों का जल्द निस्तारण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि त्वरित न्याय मिलने से लंबित चयन प्रक्रियाएं पूरी होंगी और नई भर्तियों का रास्ता भी साफ होगा।

टोल प्लाजा पर दबंगई मामले में अतीक के बेटे उमर और अली के समर्थकों पर होगा एक्शन

एजेंसी, प्रयागराज। प्रयागराज में टोल प्लाजा पर दबंगई करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस माफिया अतीक के बेटों उमर और अली के उन समर्थकों की सूची तैयार कर रही है, जिन पर टोल टैक्स नहीं देने, बूम बैरियर तोड़ने, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। पुलिस ने संबंधित वाहन मालिकों का पूरा ब्योरा जुटाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से जानकारी मांगी है। वाहन मालिकों की पहचान होने के बाद पुलिस टोल टैक्स की वसूली के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी करेगी। बताया गया कि अतीक का छोटा बेटा अबान अहमद झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था।

रक्षाबंधन पर छह दिन चलेगी विशेष बस सेवा

एजेंसी, लखनऊ। रक्षाबंधन पर्व पर बहनों और यात्रियों के सुगम सफर के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने विशेष तैयारी की है। 26 से 31 अगस्त तक छह दिनों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। प्रयागराज से लखनऊ, कानपुर समेत प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें उपलब्ध रहेंगी। रोडवेज ने चालकों और परिचालकों को निर्देश दिए हैं कि बस अड्डों के अलावा मार्ग में निर्धारित ठहराव और संकेत देने वाले यात्रियों को भी बस में बैठाया जाए। विशेष रूप से यदि कोई बहन सड़क पर बस रोकने के लिए हाथ दे तो चालक बस रोककर उसे सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाए। कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

गोरखपुर-सोनौली फोरलेन से दिल्ली से नेपाल का सफर अब 11 घंटे में

गोरखपुर-सोनौली फोरलेन से बदली विकास की तस्वीर

एजेंसी, लखनऊ

गोरखपुर-सोनौली फोरलेन सड़क परियोजना ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। गोरखपुर से सोनौली तक बेहतर सड़क संपर्क बनने से नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए सफर पहले की तुलना में काफी सुगम हो गया है। सोनौली भारत-नेपाल सीमा का प्रमुख प्रवेश मार्ग है और यहां से नेपाल जाने वाले पर्यटकों, व्यापारियों तथा अन्य यात्रियों के लिए गोरखपुर महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। पहले गोरखपुर से सोनौली तक सड़क की स्थिति और यातायात व्यवस्था के कारण यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब फोरलेन निर्माण के बाद यात्रा की गति बढ़ी है और दिल्ली से नेपाल तक पहुंचने में लगने वाला समय भी कम होने की उम्मीद है। इस मार्ग के बेहतर होने से दिल्ली से नेपाल की यात्रा करीब 11 घंटे में पूरी करने की सुविधा विकसित हो रही है।

गोरखपुर-सोनौली सड़क को टू लेन से फोरलेन में बदलने का काम छह

◆फोरलेन बनने से जमीनों की कीमतें करोड़ों तक पहुंचीं

मार्च 2023 को शुरू हुआ था। इस परियोजना का उद्देश्य केवल यात्रा को आसान बनाना नहीं है, बल्कि भारत-नेपाल के बीच संपर्क को मजबूत करना भी है। यह मार्ग व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों के अलावा नेपाल से भारत आने वाले यात्रियों और व्यापारियों के लिए भी यह सड़क महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेहतर सड़क संपर्क से माल परिवहन आसान होगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

फोरलेन निर्माण का असर आसपास के क्षेत्रों की जमीन की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। जिन क्षेत्रों में पहले जमीन अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध थी, वहां सड़क के किनारे जमीनों की मांग बढ़ी है। बेहतर संपर्क व्यवस्था के कारण आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं। कई स्थानों पर जमीन की कीमतों में तेजी आई है और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। सड़क के आसपास नए कारोबार, प्रतिष्ठान और अन्य सुविधाएं विकसित होने की संभावना भी बढ़ी है। आधुनिक सड़क और टोल व्यवस्था से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सुगम यातायात से ईंधन की बचत हो सकती है और लंबे सफर के दौरान समय की भी बचत होगी।

मेरठ में चार प्रमुख मार्गों पर बनेगी ग्रीन बेल्ट, तीन माह में होगा काम

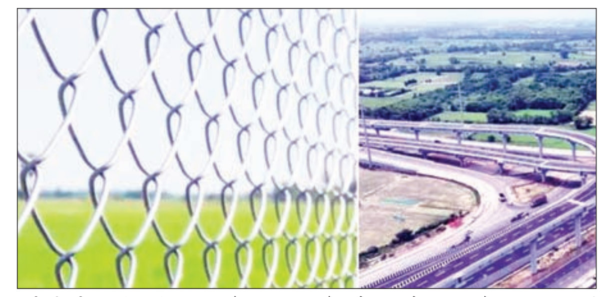

एजेंसी, मेरठ। मेरठ में सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए काटे गए पेड़ों के बाद अब शहर में हरियाली लौटाने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम ग्रिड योजना के तहत शहर के चार प्रमुख मार्गों पर ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। इस कार्य में वन विभाग, नगर निगम और मेरठ विकास प्राधिकरण मिलकर काम करेंगे। योजना के तहत करीब 435 पेड़ों की कटाई के बाद अब संबंधित मार्गों पर पौधारोपण और हरियाली विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों ने ग्रीन बेल्ट का काम तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ग्रीन बेल्ट को केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे लोगों के लिए आकर्षक और उपयोगी बनाने की भी योजना है। इसके लिए छह फीट ऊंची रैलिंग लगाई जाएगी। लोगों के आवागमन के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे और बैठने के लिए सीटें भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा आकर्षक लैंडस्केपिंग के साथ पौधों की सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाएगा। ग्रीन बेल्ट की दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी कर शहर की सुंदरता बढ़ाने की योजना है। छोटे फव्वारे और रंग-बिरंगी रोशनी भी लगाई जाएगी।

ग्रीन बेल्ट विकसित करने का कार्य कमिश्नरी आवास चौराहे से जेलचुंगी चौराहे तक, गंगानगर मुख्य डिवाइडर रोड के किनारे, एल ब्लाक तिराहे से एमसीसी अस्पताल होते हुए पीएससी मैदान तक और तेजगढ़ी से एल ब्लाक तिराहे तक किया जाएगा। इन सभी स्थानों पर अलग-अलग सिविल कार्य और ग्रीन बेल्ट कार्य कराए जाएंगे। संबंधित विभागों की ओर से कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है। अधिकारियों के अनुसार सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क विकास के लिए जिन स्थानों पर पेड़ काटे गए थे, वहां पौधे लगाकर हरियाली विकसित करना प्राथमिकता है।

तिरंगा यात्रा से पहले फटा हीलियम सिलिंडर, दो लोग घायल

एजेंसी, बुलंदशहर

बुलंदशहर के कालाआम चौराहा पर गुरुवार सुबह तिरंगा यात्रा के शुभारंभ से पहले बड़ा हादसा हो गया। यात्रा की तैयारियों के दौरान गुब्बारे भरते समय हीलियम गैस का सिलिंडर अचानक फट गया। सिलिंडर फटने से मौके पर अफरातफरी मच गई। हादसे में दो लोग घायल हो गए। इनमें एक युवक की हालत गंभीर बताई गई है। गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कालेज की इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं दूसरे घायल का अस्पताल के वार्ड में उपचार चल रहा है।

जानकारी के अनुसार कालाआम चौराहा से गुरुवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे भाजपा की विशाल तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होना था। कार्यक्रम को लेकर शहर में पहले से तैयारियां चल रही थीं। यात्रा के लिए कई स्थानों पर टेंट लगाए गए थे और सुंदर गेट बनाकर सजावट की जा रही थी। इसी क्रम में गुरुवार सुबह कालाआम चौराहा पर गुब्बारे भरने का काम चल रहा था।

बताया गया कि शिकारपुर बाईपास स्थित चीरघर निवासी 41 वर्षीय राकेश पुत्र रामगोपाल और शहर के मोहल्ला साठा गड़रियों वाली गली निवासी राजेश पुत्र राम सिंह हीलियम गैस के सिलिंडर से गुब्बारे भर रहे थे।

चुनाव से पहले यूपी भाजपा में क्षेत्रीय संगठन की कवायद तेज

एजेंसी, अलीगढ़

◆प्रदेश के सभी छह क्षेत्रों में नई टीम के गठन को लेकर अगस्त के अंत तक घोषणा किए जाने की संभावना है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व विभिन्न स्तरों पर नामों और समीकरणों की समीक्षा कर रहा है। क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी दिल्ली बुलाकर संगठनात्मक तैयारियों और स्थानीय परिस्थितियों पर चर्चा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपने संगठन को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश में संगठन को नई दिशा और धार देने के लिए पार्टी स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी छह क्षेत्रों के लिए नई टीम के गठन को अंतिम रूप देना रहा। पार्टी नेतृत्व ने क्षेत्रीय टीमों में जातीय और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए संभावित पदाधिकारियों के नामों पर मंथन किया। इसके साथ ही निगम, आयोग और विभिन्न बोर्डों में जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारियों के नामों को भी परखा गया। माना जा रहा है कि भाजपा संगठन में संतुलन कायम करने के साथ ही आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अनुभवी और सक्रिय कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे सकती है।

भाजपा ने 25 जून को प्रदेश पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा की थी। इसके बाद अब क्षेत्रीय स्तर पर संगठन को और मजबूत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठन की सभी इकाइयों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया जाए और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो।

इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चार और पांच जून को दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश संगठन की कार्यशैली और आगामी रणनीति को लेकर पार्टी नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की थी। अब दिल्ली में हुई बैठक को उसी संगठनात्मक प्रक्रिया की अगली कड़ी माना जा रहा है।

भाजपा ने बूथ सम्मेलन, संत रविदास समरसता संकल्प अभियान और हर घर तिरंगा अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय करने की योजना बनाई है।

शाह और दामूपुर में दलितों की जमीनों की जांच शुरू

एजेंसी, लखनऊ। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ से जुड़ी संपत्तियों की जांच के दौरान दलितों की बेशकीमती जमीनों को कथित तौर पर कम कीमत में लिखवाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शहर पश्चिमी क्षेत्र के शाह उर्फ पीपल और दामूपुर गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें कथित रूप से डराने-धमकाने और दबाव बनाकर कौड़ियों के दाम लिखवाई गई थीं। जांच में यह भी सामने आया है कि इन जमीनों की रजिस्ट्री अतीक और अशरफ के करीबी राजीव नागर के नाम कराई गई थी। प्रशासन अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संपत्तियों की वास्तविक स्थिति और लेन-देन की जांच कर रहा है।

बताया गया है कि इन जमीनों में से कई अराजियों और गाटों को अब बेचने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आरोप है कि अतीक के गुर्गों और रिश्तेदारों के माध्यम से इन संपत्तियों की बिक्री की जा रही थी और उससे प्राप्त धन परिवार तक पहुंचाया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने उच्चस्तरीय बैठक में संबंधित रिपोर्ट पर चर्चा की।

सीएमओ की कुर्सी संभालते ही एक्शन में डॉ. नरेंद्र प्रताप

एजेंसी, वाराणसी। वाराणसी के नवागत मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की सतत निगरानी करते हुए पिछले दिनों हुई लापरवाही पर नाराजगी जताई और संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। नवागत सीएमओ ने कबीर नगर स्थित कार्यालय में अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के एक-एक बिंदु की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से एंबुलेंस सेवा को प्राथमिकता देते हुए इसकी उपलब्धता और संचालन की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अन्य योजनाओं की प्रगति पर भी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित कार्यों में लापरवाही के मामले में पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी मुकेश कुमार के खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई हो चुकी है।

गोरखपुर में डॉक्टर ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर दी जान, 1.40 करोड़ की ठगी से था परेशान

◆डॉक्टर की आत्महत्या से सनसनी सुसाइड नोट में आरोपित का नाम

एजेंसी, गोरखपुर

गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र स्थित बसंत इंक्लेव अपार्टमेंट में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। पशु चिकित्सक डा. परमात्मा सिंह ने अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजन उन्हें गंभीर हालत में पास के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार डा. परमात्मा सिंह कथित तौर पर 1.40 करोड़ रुपये की ठगी से परेशान थे।

पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है। बताया जा रहा है कि नोट में जालसाजी के मामले में जेल भेजी गई गरिमा सिंह का नाम लिखा है। पुलिस अब सुसाइड नोट और उससे जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। करीब आठ दिन पहले डा. परमात्मा सिंह ने एम्स थाने में गरिमा सिंह और उसके साथियों के विरुद्ध 1.40 करोड़ रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले को घटना की पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूरे मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। सुसाइड नोट में लिखी गई बातों, पहले दर्ज मुकदमे और संबंधित लोगों से जुड़े तथ्यों की जांच की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ठगी की घटना के बाद डॉक्टर किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे और मामले में उनकी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई थी।

चुनावी तैयारी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अंटू मिश्रा बसपा से बाहर, मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों पर दी चेतावनी

मायावती ने अंटू मिश्रा को पार्टी से किया निष्कासित

एजेंसी, लखनऊ

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस कार्रवाई को बसपा के संगठनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। मायावती ने इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी आगामी चुनाव के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल तेजी से गर्म हो रहा है और ऐसे समय में विरोधी दल विभिन्न प्रकार की राजनीतिक चालें चल सकते हैं।

मायावती ने अपने संदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से विरोधियों की कथित साजिशों से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बसपा के आंबेडकरवादी मिशन को सफल बनाने के लिए जुटने की अपील की। इसी संदेश के साथ उन्होंने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा के निष्कासन की जानकारी भी सार्वजनिक की। पार्टी की ओर से उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। हालांकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है।

अनंत कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और पार्टी के पुराने नेताओं में उनकी पहचान रही है। ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच उनका निष्कासन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बसपा इस समय उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी है। पार्टी नेतृत्व लगातार संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है और नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

मायावती ने अपने संदेश में चुनाव के दौरान राजनीतिक विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे किसी भी प्रकार के बहकावे में न आएं और पार्टी की विचारधारा तथा संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखें। उनका संदेश ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में सभी प्रमुख राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर रहे हैं। बसपा के लिए संगठन को एकजुट रखना इस समय बड़ी प्राथमिकता है।

बसपा चुनावी तैयारी के लिए मजबूत स्थिति में

पार्टी नेतृत्व बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अंटू मिश्रा के निष्कासन को भी इसी व्यापक संगठनात्मक अनुशासन के संदर्भ में देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का स्पष्ट संकेत है कि संगठन विरोधी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का अपना मजबूत आधार रहा है और पार्टी आगामी चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को लेकर लिए जा रहे फैसले राजनीतिक दृष्टि से भी चर्चा का विषय बन रहे हैं।

43 यात्रियों से भरी बस पलटी, छह को आई गंभीर चोट

एजेंसी, लखनऊ

◆एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित हुई बस, डिवाइडर से टकराकर पलटी

कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार तड़के एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसा सुबह करीब 3:30 बजे किलोमीटर संख्या 216.900 के पास हुआ। बस जयपुर से गोरखपुर जा रही थी और उसमें कुल 43 यात्री सवार थे। हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में छह यात्री घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार गोला बस सर्विस की स्लीपर बस जयपुर से यात्रियों को लेकर गोरखपुर जा रही थी। जैसे ही बस आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रेस्ट एरिया के पास पहुंची तभी किसी कारण से चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित बस पहले डिवाइडर से टकराई और इसके बाद सड़क पर पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात यूपीडा के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। बस में फंसे और घायल यात्रियों को बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। उपचार के बाद सभी छह घायल यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

हरियाणा में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने बनाया छह महीने का रोडमैप

कांग्रेस ब्लॉक से जिला स्तर तक अधिवेशन कर कार्यकर्ताओं को देगी प्रशिक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के लिए अगले छह महीने का रोडमैप तैयार किया है। पार्टी प्रभारी संजय सतीशचंद्र दत्त ने संगठन को सक्रिय करने के साथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और आगामी चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत आधार देने की रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रदेश के सभी ब्लाक और जिलों में अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद तीन महीने तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

संजय दत्त हरियाणा के अब तक तीन चरणों में दौरे कर चुके हैं। उनका चौथा दौरा 17 से 21 अगस्त तक प्रस्तावित है। इस दौरान वह पंचकूला में हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने की मांग को लेकर होने वाले धरने में भी शामिल होंगे। इसके अलावा एसआइआर अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास से चंडीगढ़ में मुलाकात करेंगे। इसी दिन कांग्रेस की राज्य स्तरीय एसआइआर निगरानी समिति की बैठक भी होगी।

संजय दत्त ने अपने अब तक के दौरों की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सरकार बनाने की इच्छा और उत्साह मौजूद है, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं में सक्रियता और इच्छाशक्ति कमजोर हुई है। ऐसे में संगठन के भीतर इच्छा और शक्ति के बीच संतुलन स्थापित करने की जरूरत है।

गुटबाजी खत्म करना बड़ी चुनौती: हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी को पार्टी की बड़ी चुनौती माना जाता है। संजय दत्त अब तक अलग-अलग खेमों के नेताओं को दो बार एक मंच पर ला चुके हैं। अब उनके सामने इस एकजुटता को स्थायी संगठनात्मक ताकत में बदलने की चुनौती है। वह देश के 16 राज्यों में अलग-अलग संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर काम कर चुके हैं।

हाईकमान की ओर से नियुक्त चार पर्यवेक्षक डॉ. रघुवीरा रेड्डी, यशोमति ठाकुर, उमंग सिंगर और अजय कुमार लल्लू भी प्रदेश के संगठनात्मक जिलों की समीक्षा करेंगे। संजय दत्त ने स्पष्ट किया है कि पर्यवेक्षक किसी जिलाध्यक्ष को हटाने या नियुक्त करने के लिए नहीं बल्कि जिलों में संगठन के कामकाज की समीक्षा के लिए भेजे गए हैं।

हरियाणा में स्मार्ट बागवानी को बढ़ावा 1000 एकड़ में आधुनिक खेती का लक्ष्य

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार प्रदेश में स्मार्ट बागवानी तकनीकों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत संरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीनहाउस और वर्टिकल फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस वर्ष लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में स्मार्ट बागवानी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश के लिए नई बागवानी नीति तैयार की जा रही है। इसे जल्द लागू किया जाएगा। नई नीति के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए बेहतर सुविधाएं और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने की योजना है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सफेद बटन मशरूम के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को मशरूम इकाइयां स्थापित करने पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। वहीं, अनुसूचित जाति के किसानों को बागवानी गतिविधियों के लिए 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि किसानों को उत्पादन से लेकर मूल्य संवर्धन और बाजार में बेहतर विपणन तक मजबूत संस्थागत सहयोग देना भी है।

इसी उद्देश्य से बागवानी विभाग के ढांचे में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत विभाग का नया नाम बागवानी एवं विपणन विभाग रखने का प्रस्ताव है।

न्यूज ब्रीफ

रोहनात में 71 साल बाद फहरा तिरंगा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। भिवानी जिले का रोहनात गांव स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की दर्दनाक कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांव अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा था। ग्रामीणों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। विद्रोह से नाराज अंग्रेजी हुकूमत ने गांव पर तोपों से हमला किया और कई ग्रामीणों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बचे लोगों को हांसी ले जाकर कथित तौर पर रोड रोलर से कुचलने की घटना का भी उल्लेख मिलता है। जिस मार्ग पर यह घटना हुई, वह आज भी 'लाल सड़क' के नाम से जाना जाता है। इन घटनाओं की वजह से रोहनात का इतिहास बेहद गौरवशाली और दुखद माना जाता है। आजादी के 71 साल बाद 23 मार्च 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव पहुंचकर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह दिन ग्रामीणों के लिए ऐतिहासिक बन गया।

नरवाना में कुत्तों का खौफ, एक दिन में छह लोगों को काटा

भारतेन्दु संवाददाता, नरवाना। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पंजाबी चौक सहित विभिन्न इलाकों में एक ही दिन में छह लोगों को कुत्ते ने काट लिया। पीड़ितों में गोपाल, प्रीति, बलबीर सैनी, कमलेश, नीलम मुंजाल और नरेंद्र मुंजाल की पत्नी शामिल हैं। नरेंद्र मुंजाल की पत्नी को कुत्ते के काटने के बाद नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जींद रेफर कर दिया गया।बीरबल नगर, पतराम नगर, मॉडल टाउन और हरि मंदिर पंजाबी चौक सहित कई क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के झुंड घूमने से लोग परेशान हैं। बच्चों के बाहर खेलने और बुजुर्गों के अकेले निकलने पर भी डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों ने नगर परिषद और प्रशासन से तत्काल अभियान चलाकर आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग की है। उनका कहना है कि नरवाना नागरिक अस्पताल में पर्याप्त उपचार सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को जींद रेफर करना पड़ रहा है। लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार क्यों कर रहा है।

अमेरिका भेजने के नाम पर दो युवकों से लाखों की ठगी

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र। अमेरिका भेजने के नाम पर कुरुक्षेत्र के दो युवकों से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव ठोल निवासी नीरज ने अपनी पत्नी पूनम रानी के साथ मिलकर नायब सिंह और सचिन ढींडसा को अमेरिका भेजने का झांसा दिया। इसके बजाय आरोपियों ने दोनों युवकों को थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, दुबई और कजाकिस्तान समेत सात देशों में घुमाया। गांव गनोली निवासी किसान नरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2023 में उसने अपने बेटे नायब सिंह को अमेरिका भेजने के लिए अपने साले के माध्यम से नीरज और पूनम रानी से संपर्क किया था। आरोपियों ने दोनों युवकों को अमेरिका भेजने के लिए प्रति युवक 37 लाख रुपये खर्च बताया। शिकायत के अनुसार, 22 सितंबर 2023 को पूनम रानी के बैंक खाते में दोनों युवकों की ओर से 2.50-2.50 लाख रुपये, कुल पांच लाख रुपये ऑनलाइन भेजे गए। इसके बाद पांच अक्टूबर को पासपोर्ट, वीजा और डॉलर उपलब्ध कराने के नाम पर दोनों से दो-दो लाख रुपये नकद लिए गए। आर्थिक अपराध शाखा अंबाला की जांच के बाद नारायणगढ़ पुलिस ने आरोपी दंपती के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बारिश को लेकर हरियाणा में अलर्ट, अधिकारियों को मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बारिश के मौसम को देखते हुए अधिकारियों को मुख्यालय न छोड़ने और जल निकासी व्यवस्था की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जलभराव से निपटने के लिए सुपर सकर, जेटिंग मशीन, मोटर, पाइप सहित सभी जरूरी संसाधन तैयार रखे जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई हो सके। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने जल निकासी, पेयजल व्यवस्था, वाटर टैंकों और विभागीय ढांचे की समीक्षा की। उन्होंने पुराने और खराब ईंटों से बने वाटर टैंकों का सर्किलवार ब्योरा और उनके उन्नयन के अनुमान मुख्यालय भेजने को कहा। गंगवा ने विभागीय आधारभूत ढांचे के लिए लाइफ साइकिल प्लानिंग तैयार करने पर जोर दिया।

सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर सरकार ने दिया जोर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा राज्य सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो से जुड़े बोर्डों, निगमों और संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अधिक परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है। ब्यूरो के चेयरमैन मोहन लाल बडौली ने कहा कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी संस्थाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ नियमित समीक्षा और प्रभावी प्रचार-प्रसार जरूरी है।

हरियाणा निवास में ब्यूरो से संबद्ध बोर्डों, निगमों, स्वायत्त निकायों, सोसायटियों और संस्थाओं के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रबंध निदेशकों, मुख्य लेखा अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में विभागीय लक्ष्यों,

बोर्डों और निगमों को जवाबदेह बनाकर योजनाओं की नियमित समीक्षा के निर्देश

योजनाओं, मुख्यमंत्री की घोषणाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

मोहन लाल बडौली ने निर्देश दिए कि प्रत्येक संस्था अपने कार्यालय में योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी वाले प्रदर्शन पट्ट लगाए। वेबसाइटों को नियमित रूप से अद्यतन करने के साथ योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रचार किया जाए।

तिरंगा यात्रा में बच्चों की तबीयत बिगड़ी, गर्मी और भीड़ से मचा हड़कंप

भारतेन्दु संवाददाता, पलवल। पलवल जिले में आयोजित भाजपा की तिरंगा यात्रा के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यात्रा में शामिल कई स्कूली बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई। राज्य के खेल मंत्री गौरव गौतम की मौजूदगी में निकाली जा रही यात्रा में भारी भीड़, गर्मी और अव्यवस्था के बीच कई विद्यार्थियों को उल्टियां होने लगीं, जबकि कुछ बच्चे चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए।

घटना के बाद शिक्षकों और अभिभावकों में हड़कंप मच गया। यात्रा में सरकारी और निजी स्कूलों के बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए थे। यात्रा आगे बढ़ने के दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने और घुटन जैसी स्थिति बनने से कुछ बच्चों को परेशानी होने लगी। स्थिति बिगड़ती देख शिक्षकों ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने बेहोश हो रहे बच्चों को गोद में उठाकर सड़क किनारे छायादार स्थानों पर पहुंचाया।

हरियाणा में प्राइम खसरा पहचान की नई डिजिटल व्यवस्था लागू

प्राइम खसरों के निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाएगी नई डिजिटल व्यवस्था

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में प्राइम खसरों की पहचान और निर्धारण के लिए नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत पूरे राज्य में प्राइम खसरा तय करने की प्रक्रिया एक समान और पारदर्शी तरीके से लागू की जा सकेगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राजस्व हरियाणा पोर्टल पर प्राइम खसरा मॉड्यूल को मंजूरी देने के साथ इसके संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और उपयोगकर्ता पुस्तिका भी स्वीकृत की है।

राजस्व एवं भूमि अभिलेखों में प्राइम खसरा उस विशिष्ट भूखंड या जमीन के नंबर को कहा जाता है, जो मुख्य सड़क, बाजार या विकसित शहरी एवं व्यावसायिक क्षेत्र के नजदीक होने के कारण अधिक वित्तीय और बाजार मूल्य रखता है। ऐसे खसरों पर स्टांप शुल्क और कलेक्टर रेट सामान्य जमीन की तुलना में अलग या अधिक दरों से

निर्धारित किए जा सकते हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डा. सुमिता मिश्रा ने बताया कि नए मॉड्यूल के माध्यम से अधिकृत राजस्व अधिकारी संबंधित अभिलेखों की जांच कर सकेंगे। आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने के बाद प्राइम खसरे का चयन और निर्धारण किया जा सकेगा। इससे अधिकारियों को सत्यापन और दस्तावेज तैयार करने की स्पष्ट प्रक्रिया मिलेगी। विभाग ने सभी जिलों में एक समान व्यवस्था लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी है। इसमें प्राइम खसरा निर्धारित करने से जुड़े विभिन्न चरणों और अधिकारियों की जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। इससे अलग-अलग जिलों में प्रक्रिया के अलग तरीके अपनाने की संभावना कम होगी।

मॉड्यूल का परीक्षण भी पूरा किया जा चुका है। परीक्षण से जुड़े मामलों और सुरक्षा प्रमाण-पत्र को भी दस्तावेजों के साथ शामिल किया गया है। इन दस्तावेजों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

मोबाइल तस्वीर से फसल की बीमारी बताएगा एआई, किसानों को मिलेगा तुरंत उपचार

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला

आइआइटी रोपड़ में खेती को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने के लिए एआइ आधारित टूल्स पर काम किया जा रहा है। इन टूल्स की मदद से किसान अपने खेत की फसल की तस्वीर मोबाइल से अपलोड कर संभावित बीमारी या कीट की समस्या तथा उसके उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल इस तकनीक को विकसित करने पर काम चल रहा है। इसकी जानकारी एफपीओ की ओर से नार्दर्न फार्मर फेडरेशन के अध्यक्ष पुनीत सिंह थिंद ने गांव बलाना में किसानों को जागरूक करते हुए दी।

मोबाइल से फसल की तस्वीर भेजकर किसान जान सकेंगे बीमारी और उपचार की जानकारी

मार्केट कमेटी अंबाला शहर की ओर से बुधवार को गांव बलाना स्थित माता मनसा देवी मंदिर में किसान जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, वन, बैंकिंग, स्वयं सहायता समूह, राजस्व विभाग, एफपीओ, वीटा और मार्केट कमेटी से जुड़े प्रतिनिधियों ने किसानों को विभिन्न योजनाओं, तकनीकों और आधुनिक सुविधाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के फायदे बताए गए। विशेषज्ञों ने कहा कि इससे मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण संरक्षण और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर की जा सकती है। खेती के साथ पशुपालन को जोड़कर एनिमल हास्टल मॉडल विकसित करने पर भी चर्चा हुई। पशुओं के गोबर और मूत्र का उचित प्रबंधन कर बायोगैस तैयार की जा सकती है। वहीं इससे निकलने वाले जैविक अवशेषों से जैविक खाद और जैव उर्वरक तैयार किए जा सकते हैं।

मार्केट कमेटी अंबाला शहर के चेयरमैन जसविंदर सिंह उगाड़ा ने कहा कि किसानों को खेती को केवल पारंपरिक तरीके तक सीमित नहीं रखना चाहिए। प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसे प्रयासों से किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

नार्दर्न फार्मर फेडरेशन के अध्यक्ष पुनीत सिंह थिंद ने किसानों को पोर्टेबल मिट्टी जांच प्रयोगशाला का मॉडल भी दिखाया। इसके माध्यम से मौके पर ही मिट्टी की जांच कर उसकी रिपोर्ट तुरंत प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत के एफपीओ के साथ मिलकर किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में किसानों को एक नाम एक पौधा अभियान के तहत पौधे वितरित किए गए।

जीवन कुंडू हत्याकांड में दो और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी फरार

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

हिसार जिले के बहुचर्चित जीवन कुंडू हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खाप पंचायतों और किसान संगठनों की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिए गए 13 अगस्त के अल्टीमेटम के आखिरी दिन पुलिस ने भाटला निवासी गजेंद्र उर्फ गज्जू पंडित और उसके साथी सिंघवा राघो निवासी साहिल को काबू किया। हालांकि पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की जगह का अभी खुलासा नहीं किया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या छह हो गई है।

हत्याकांड का मुख्य आरोपी सूर्यनगर निवासी रमेश शर्मा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फरार मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

एसपी हिसार सिद्धांत जैन के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी

के लिए 10 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें हरियाणा के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस ने सभी वांछित आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है।

मामले को लेकर खाप पंचायतें और किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस को 13 अगस्त तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया था। इसी दौरान हिसार में चल रहे धरने में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे।

पुलिस ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ घर पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। परिवार के पुनर्वास और रोजगार उपलब्ध करवाने के संबंध में भी आवेदन किया गया है।

हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए मंत्रियों सांसदों की ड्यूटी तय

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह यमुनानगर में आयोजित किया जाएगा। यहां राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ध्वजारोहण करेंगे। वहीं नए जिले हांसी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे।

राज्य सरकार ने जिला मुख्यालयों और उपमंडल स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की ड्यूटी निर्धारित कर दी है। सभी स्थानों पर सुबह नौ बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शाम को हरियाणा लोकभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन होगा।

राज्यपाल करेंगे ध्वजारोहण, हांसी में मुख्यमंत्री रहेंगे मुख्य अतिथि

सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार अंबाला में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, भिवानी में सांसद सुभाष बराला, चरखी दादरी में सांसद रेखा शर्मा और फरीदाबाद में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ध्वजारोहण करेंगे। फतेहाबाद में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, गुरुग्राम में विधानसभा उपाध्यक्ष डा. कृष्ण लाल मिढा और हिसार में सांसद नवीन जिंदल मुख्य अतिथि होंगे।

झज्जर में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, जींद में सांसद संजय भाटिया, कैथल में सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्री कृष्ण कुमार और करनाल में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ध्वजारोहण करेंगे। कुरुक्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और नारनौल में सांसद धर्मबीर सिंह मुख्य अतिथि होंगे।

नूंह में सांसद कार्तिकेय शर्मा, पलवल में युवा सशक्तीकरण एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम, पंचकूला में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी और पानीपत में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ध्वजारोहण करेंगे।

रेवाड़ी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर, रोहतक में सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, सिरसा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और सोनीपत में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह मुख्य अतिथि होंगे।

रेलवे की नई लाइसेंस व्यवस्था से देशभर में कंटेनर ट्रेन संचालन होगा आसान

रेलवे के नए लाइसेंस नियम से माल ढुलाई होगी आसान, निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला

भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई व्यवस्था को अधिक सरल, प्रतिस्पर्धी और निवेश के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। रेल मंत्रालय ने कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को आसान करते हुए अब एक ही लाइसेंस से देशभर में कंटेनर ट्रेन चलाने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को अलग-अलग रेल मार्गों या क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपये के एकसमान शुल्क पर ऑल इंडिया लाइसेंस दिया जाएगा।

रेल मंत्रालय के इस फैसले को देश के माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे कंटेनर ट्रेन संचालकों को नए क्षेत्रों और मार्गों पर कारोबार विस्तार के लिए बार-बार अलग अनुमति लेने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

रूट आधारित लाइसेंस व्यवस्था खत्म : नई नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए पहले लागू रूट आधारित लाइसेंस श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया है। अब ऑपरेटर एक ऑल इंडिया लाइसेंस लेकर देश के विभिन्न रेल नेटवर्क पर अपनी कंटेनर सेवाओं का संचालन कर सकेंगे। इससे कारोबार विस्तार में लगने वाला समय और प्रशासनिक प्रक्रिया दोनों कम होने की उम्मीद है।

पहले अलग-अलग मार्गों और श्रेणियों के आधार पर लाइसेंस लेने के कारण ऑपरेटरों को कई स्तरों पर अनुमति और शुल्क संबंधी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। नई व्यवस्था में इन प्रक्रियाओं को एकीकृत किया गया है।

20 साल का अतिरिक्त विस्तार बिना शुल्क : नई व्यवस्था में ऑपरेटरों को लंबी अवधि की कारोबारी स्थिरता भी मिलेगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार शुरुआती कंसेशन अवधि पूरी होने के बाद संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटर को 20 वर्ष का अतिरिक्त विस्तार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दिया जाएगा।

इस प्रावधान से कंटेनर ट्रेन संचालन में लंबे समय के निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है। कंपनियां आधुनिक कंटेनर, टर्मिनल, माल संभालने की सुविधाओं और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में निवेश के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं।

पुराने ऑपरेटरों को भी विकल्प : रेलवे बोर्ड ने मौजूदा कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के हितों को भी ध्यान में रखा है। वर्तमान लाइसेंसधारी अपनी मौजूदा लाइसेंस अवधि पूरी होने तक पुरानी व्यवस्था के तहत काम जारी रख सकेंगे। वहीं कैटेगरी-2, 3 और 4 के मौजूदा ऑपरेटरों को नई व्यवस्था में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए उन्हें 15 करोड़ रुपये का अंतर शुल्क जमा करना होगा।

माल परिवहन में बढ़ सकती है रेल की हिस्सेदारी : रेलवे के इस फैसले से देश के लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। एकल लाइसेंस व्यवस्था से कंटेनर ट्रेन संचालकों की कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक लागत कम होगी। इससे वे अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार तेजी से कर सकेंगे।

रेल मंत्रालय का एक प्रमुख उद्देश्य माल परिवहन को सड़क से रेल की ओर आकर्षित करना भी है। कंटेनर ट्रेन नेटवर्क मजबूत होने से लंबी दूरी तक माल पहुंचाने में रेल की भूमिका बढ़ सकती है। इससे सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कम होने के साथ ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी आने की भी संभावना है।

निजी निवेश और प्रतिस्पर्धा को मिलेगा बढ़ावा : नई लाइसेंस व्यवस्था से निजी कंपनियों के लिए रेलवे के माल ढुलाई क्षेत्र में निवेश करना आसान हो सकता है। एक समान लाइसेंस और लंबी अवधि की कारोबारी निश्चितता कंपनियों को नए टर्मिनल, कंटेनर और परिवहन सुविधाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर सकती है ।

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार ठहरा, सरकार के विकास मॉडल पर उठे गंभीर सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में रोजगार से जुड़े सवाल के माध्यम से देश में रोजगार की स्थिति पर चिंता जताई है। उनके सवाल के जवाब में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कार्यबल में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी से संबंधित आंकड़े सदन में रखे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र की कुल कार्यबल में हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 12.1 प्रतिशत थी और वर्ष 2025 में भी यह 12.1 प्रतिशत ही रही।

आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020-21 में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी घटकर 10.9 प्रतिशत रह गई थी। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे सुधार हुआ, लेकिन 2025 तक यह वर्ष 2017-18 के स्तर से आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं इसी अवधि में सेवा क्षेत्र की कार्यबल में हिस्सेदारी 31.1 प्रतिशत से बढ़कर 31.8 प्रतिशत हो गई।

दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से पूछा था कि क्या देश में रोजगार सृजन का स्तर पर्याप्त है और यदि नहीं है तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं। हुड्डा के अनुसार सरकार ने इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय रोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से वास्तव में कितने रोजगार पैदा हुए, इसका स्पष्ट आंकड़ा जवाब में नहीं दिया गया।

हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार के विकास मॉडल में रोजगार सृजन अपेक्षित गति से नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी लंबे समय से लगभग स्थिर बनी हुई है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के दावों के बावजूद रोजगार के अवसर उसी अनुपात में क्यों नहीं बढ़े, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों में खाली पड़े पदों को भरने तथा युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

हुड्डा ने कहा कि देश की बड़ी युवा आबादी को रोजगार उपलब्ध कराना आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। उनके मुताबिक सरकार को ऐसी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए जिनसे विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा हों।

दिल्ली में दो बड़े आरओबी बंद, पुरानी दिल्ली जाने वालों की बढ़ेगी परेशानी

असुरक्षित घोषित हुए दो रेलवे ओवरब्रिज, लंबे समय तक बंद रहेगा यातायात

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। उत्तरी रेलवे द्वारा पुल बंगश और पुल डफरिन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के पुनर्निर्माण के चलते दोनों पुल लंबे समय तक यातायात के लिए बंद रहेंगे। दोनों पुलों को यातायात के लिहाज से असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद इन्हें तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। इस कारण पुरानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों आरओबी के बंद होने से संबंधित क्षेत्रों में यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है।

खासकर उन वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है, जो रोजाना इन पुलों का इस्तेमाल कर पुरानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में पहुंचते हैं। दिल्ली ट्रैफिक

पुलिस ने यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले निर्धारित वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लें और अनावश्यक जाम से बचने के लिए मार्ग की योजना बनाकर निकलें। पुल बंगश और पुल डफरिन पुराने रेलवे ओवरब्रिज हैं और इनकी संरचनात्मक स्थिति को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता सामने आई थी। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन्हें यातायात के लिए बंद करने और पुनर्निर्माण कराने का फैसला लिया गया है।

दिल्ली में पुराने पुलों और फ्लाईओवरों की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर संरचनात्मक जांच भी की जाती है। पुनर्निर्माण अवधि के दौरान यातायात को वैकल्पिक रास्तों पर मोड़ा जाएगा। इसके चलते कुछ प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ सकता है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में यात्रियों को अधिक समय लगने की संभावना है। ऐसे में निजी वाहन चालकों के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वालों को भी अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी का उद्देश्य वाहन चालकों को बंद रास्तों और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी देना तथा यातायात को व्यवस्थित रखना है। वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने और प्रतिबंधित मार्गों पर जाने से बचने की अपील की गई है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रबंधन के लिए अलग-अलग कॉरिडोर और मार्गों की निगरानी करती है। दोनों पुलों के पुनर्निर्माण से भविष्य में यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर संपर्क सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि निर्माण कार्य पूरा होने तक स्थानीय निवासियों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को अस्थायी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पुरानी दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए खास तौर पर यह जरूरी होगा कि वे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, अलीगढ़ के दारोगा की मौत

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लालकुआं के पास गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में अलीगढ़ पुलिस के एक दारोगा की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब पुलिस की स्विफ्ट कार एक कैंटर से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार मडराक थाने में तैनात दारोगा उपेंद्र सिंह की जान चली गई। वहीं, दो सिपाही और दो अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ पुलिस की टीम दिल्ली से दो आरोपित पिता-पुत्र को गिरफ्तार करके अलीगढ़ लेकर जा रही थी।

इसी दौरान लालकुआं क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर पुलिस की स्विफ्ट कार की कैंटर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार पुलिसकर्मी तथा अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस

मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद दारोगा उपेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया। घायल दो सिपाहियों और दोनों आरोपितों का उपचार कराया जा रहा है। उनकी हालत को लेकर चिकित्सकों की निगरानी जारी है।

उपेंद्र सिंह अलीगढ़ के मडराक थाने में तैनात थे और पुलिस टीम के साथ आरोपित पिता-पुत्र को पकड़कर अलीगढ़ ले जा रहे थे। ड्यूटी के दौरान हुए इस हादसे में उनकी मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। अधिकारियों ने घटना की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और उस समय दोनों वाहनों की स्थिति क्या थी। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार मार्गों पर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस मामले की जांच के साथ दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को भी जुटा रही है। दारोगा की मौत से उनके सहकर्मियों और परिवार में गहरा दुख है।

नोएडा में डॉक्टरों ने 20 फ्रैक्चर वाले मरीज को 74 दिन बाद दिया नया जीवन

एजेंसी, नई दिल्ली

नोएडा के सेक्टर-27 स्थित कैलाश सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक मरीज का जटिल उपचार कर उसे नया जीवन दिया। हादसे में मरीज नकुल बरुआ को शरीर के अलग-अलग हिस्सों में 20 से अधिक फ्रैक्चर हुए थे। गंभीर स्थिति में अस्पताल लाए गए नकुल का करीब 74 दिनों तक इलाज चला। बुधवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सड़क दुर्घटना के बाद नकुल की हालत बेहद गंभीर थी।

हादसे में उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थीं, जिसके कारण इलाज चुनौतीपूर्ण हो गया था। मरीज को तत्काल चिकित्सकीय निगरानी और विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता थी। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद डॉक्टरों ने उनकी स्थिति का विस्तृत आकलन किया और उपचार की प्रक्रिया शुरू की।

मरीज के इलाज के लिए क्रिटिकल केयर, आर्थोपेडिक्स और थोरेसिक सर्जरी विभाग की विशेषज्ञ टीमों ने मिलकर काम किया। गंभीर चोटों और कई फ्रैक्चर के कारण उपचार को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया। चिकित्सकों ने मरीज की स्थिति को लगातार निगरानी में रखा और आवश्यकतानुसार उपचार किया। कई फ्रैक्चर होने के साथ मरीज की स्थिति को देखते हुए यह मामला बेहद जटिल था। ऐसे में विभिन्न विशेषज्ञ विभागों के बीच बेहतर समन्वय इलाज की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहा। क्रिटिकल केयर टीम ने मरीज की गंभीर स्थिति पर नजर रखी, जबकि आर्थोपेडिक्स विशेषज्ञों ने हड्डियों से जुड़ी चोटों के उपचार पर काम किया। थोरेसिक सर्जरी टीम ने भी अपनी विशेषज्ञता के अनुसार इलाज में योगदान दिया।

लगातार 74 दिनों तक चले उपचार के बाद नकुल की हालत में सुधार हुआ। चिकित्सकों की निगरानी और उपचार के बाद उनकी स्थिति इतनी बेहतर हो गई कि उन्हें बुधवार को अस्पताल से छुट्टी देने का निर्णय लिया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मरीज और उनके परिवार ने इलाज में शामिल चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों का आभार जताया।

फरीदाबाद में बस के नीचे आकर युवक की मौत, पहचान में जुटी पुलिस

एजेंसी, नई दिल्ली

फरीदाबाद के एनआईटी स्थित बाबा दीप सिंह चौक पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में युवक की बस के नीचे आने से मौत हो गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए। जानकारी के अनुसार, एनआईटी के प्याली चौक का नाम बदलकर अब बाबा दीप सिंह चौक कर दिया गया है। इसी चौक पर गुरुवार को एक युवक अचानक बस की चपेट में आ गया।

बस के नीचे आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और मृतक की पहचान के लिए आवश्यक

जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस बस की चपेट में युवक आया, वह किसी निजी कंपनी से जुड़ी हुई है। यह बस कंपनी के कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुलिस बस और उसके चालक की भी पहचान करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतक की पहचान और हादसे की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और युवक बस की चपेट में कैसे आया। मृतक की पहचान होने के बाद ही घटना से जुड़ी आगे की जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

नरेला में दर्दनाक हादसा: बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबे दो मासूम

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के नरेला इलाके में बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसा बृहस्पतिवार को 100 फुटा, डीडीए फ्लैट्स इलाके में हुआ। मृतकों की उम्र नौ और 11 वर्ष बताई जा रही है। दोनों बच्चे बवाना इलाके के रहने वाले थे। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चे खेलते-खेलते बारिश के पानी से भरे गड्ढे के पास पहुंच गए। इसी दौरान वे गड्ढे में गिर गए और पानी में डूबने लगे।

आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी मिलने पर बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों बच्चों का इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी रही। इलाज के दौरान दोनों ने दम

नरेला में गड्ढे में डूबने से दो मासूमों की मौत

तोड़ दिया। बच्चों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों की ओर से यह भी पता लगाया जा रहा है कि गड्ढा किस कारण से बना था और उसमें बारिश का पानी किस तरह जमा हुआ। मानसून के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में खुले गड्ढों और निर्माण स्थलों पर पानी भर जाने से हादसे का खतरा बढ़ जाता है।

ऐसे में नरेला की यह घटना बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। पानी से भरे गड्ढे ऊपर से सामान्य दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। बच्चों के लिए ऐसे स्थान विशेष रूप से खतरनाक साबित हो सकते हैं।

नौकरी का झांसा देकर 2.20 लाख ठगे, ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

एजेंसी, साहिबाबाद

प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत पर संविदा कर्मी से नौकरी दिलाने के नाम पर 2.20 लाख रुपये ठगने और धमकाने का आरोप लगा है। मामले की शिकायत अधिकारियों तक पहुंचने के बाद जिला विकास अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया। जानकारी के अनुसार, मऊ जिले के मधुबन गांव के रहने वाले अश्वनी कुमार शंकरगढ़ ब्लॉक में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं।

इसी ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत की भी तैनाती है। आरोप है कि करीब एक वर्ष पहले शशिकांत ने अश्वनी को मध्य प्रदेश में डाक विभाग में संविदा की नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। उसने बताया कि वहां मिलने वाला मानदेय शंकरगढ़ ब्लॉक की नौकरी

से अधिक होगा। नौकरी का झांसा देकर ग्राम विकास अधिकारी ने अश्वनी से कथित तौर पर 2.20 लाख रुपये ले लिए। अश्वनी का आरोप है कि रकम लेने के बाद भी एक साल तक उसे नौकरी नहीं दिलाई गई। जब उसने अपने रुपये वापस मांगे तो शशिकांत ने कथित रूप से उसे धमकाना शुरू कर दिया। लगातार इंतजार और परेशान होने के बाद अश्वनी ने पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। शिकायत सामने आने पर प्रकरण की जांच और कार्रवाई शुरू हुई। बताया गया कि जिला विकास अधिकारी की फटकार के बाद ग्राम विकास अधिकारी ने अश्वनी के रुपये वापस किए।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला विकास अधिकारी ने आरोपी ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत को निलंबित कर दिया। अधिकारियों की कार्रवाई के बाद संविदा कर्मी को उसके रुपये वापस मिल गए। घटना के बाद ब्लॉक स्तर पर भी यह मामला चर्चा में है।

आगरा की डॉक्टर जागृति ने कौन बनेगा करोड़पति में जीते 25 लाख

एजेंसी, नई दिल्ली

आगरा की चिकित्सक डॉ. जागृति अग्रवाल ने लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन-17 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 लाख रुपये की धनराशि जीती। उन्होंने पहली बार इस शो के लिए आवेदन किया था और अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास तथा सूझबूझ के दम पर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट तक पहुंचीं। बुधवार को प्रसारित एपिसोड में डॉ. जागृति अग्रवाल ने कई सवालों का आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया और लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए 25 लाख रुपये जीतने में सफलता हासिल की। उनके प्रदर्शन की खास बात यह रही कि उन्होंने कठिन सवालों का भी धैर्य और समझदारी के साथ सामना किया। में हिस्सा लेना उनके लिए खास अनुभव रहा। पहली बार आवेदन करने के बाद चयनित होकर हॉट सीट तक पहुंचना और फिर इतनी बड़ी धनराशि जीतना उनके लिए गौरव का क्षण बना।

मेरठ की बेटी अदिति सिंह का नाम देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों में शामिल

एजेंसी, नई दिल्ली

मेरठ की बेटी और पंचकुला की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अदिति सिंह को देश के 100 सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारियों में शामिल किया गया है। फेम इंडिया-एशिया पोस्ट की ओर से किए गए चयन में उनकी कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण और जनमित्र पुलिसिंग जैसे मानकों को आधार बनाया गया। इस उपलब्धि ने मेरठ के साथ-साथ पुलिस विभाग का भी गौरव बढ़ाया है। अदिति सिंह की पहचान एक ऐसी पुलिस अधिकारी के रूप में बनी है, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ आम लोगों के साथ संवेदनशील और सहयोगात्मक व्यवहार को भी प्राथमिकता देती हैं।

उनकी कार्यशैली में अनुशासन, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी के साथ जनसरोकारों को महत्व दिया जाता है। अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए

उनकी सक्रिय भूमिका को भी सराहा गया है। देववाणी संस्कृत में 'अदिति' शब्द का अर्थ असीम और अनंत माना जाता है। यानी जिसकी कोई सीमा न हो। उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली को देखते हुए यह नाम उन पर काफी सार्थक नजर आता है। अदिति सिंह स्वतंत्र सोच, आत्मविश्वास और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों को गंभीरता से संभालने के साथ लोगों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करने पर भी जोर दिया।

जनमित्र पुलिसिंग के तहत नागरिकों के साथ बेहतर संवाद और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश उनकी कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फेम इंडिया-एशिया पोस्ट की सूची में शामिल होना उनके करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। अदिति सिंह की उपलब्धि से मेरठ का गौरव बढ़ा। उनकी कार्यशैली, अपराध नियंत्रण और जनमित्र पुलिसिंग ने उन्हें देश के 100 सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारियों में स्थान दिलाया।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा मौका, नरेला में 25% छूट पर फ्लैट

कर्मयोगी आवास योजना: सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट पर भारी छूट

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक खास मौका पेश किया है। डीडीए की कर्मयोगी आवास योजना के तहत दिल्ली के नरेला इलाके में 1224 रेडी-टू-मूव फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन फ्लैट्स की कीमत पर 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। योजना का लाभ सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं। खास बात यह है कि फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी। डीडीए की यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो दिल्ली में अपना स्थायी घर खरीदना चाहते हैं।

योजना के तहत उपलब्ध सभी फ्लैट्स नरेला के सेक्टर-1 से-4 और पॉकेट-11 में स्थित हैं। ये फ्लैट्स पहले से तैयार हैं, यानी खरीदारों को लंबे समय तक निर्माण पूरा होने का इंतजार नहीं करना

डीडीए नरेला में सरकारी कर्मचारियों को 25% छूट पर फ्लैट देगा।

पड़ेगा। 25 प्रतिशत की छूट के कारण इन घरों की कीमत सामान्य दरों की तुलना में काफी कम हो सकती है, जिससे पात्र आवेदकों को आर्थिक रूप से लाभ मिल सकता है। योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता संपत्ति संबंधी पात्रता को लेकर है। ऐसे सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनके नाम दिल्ली या देश के किसी अन्य हिस्से में पहले से कोई संपत्ति मौजूद है। इसका मतलब यह है कि पहले से मकान या जमीन रखने वाले पात्र सरकारी कर्मचारी भी योजना में शामिल होकर नरेला में डीडीए का फ्लैट खरीद सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, जो भविष्य में दिल्ली में दूसरा घर या निवेश के उद्देश्य से संपत्ति लेना चाहते हैं।

इसके अलावा, एक आवेदक को अलग-अलग श्रेणियों में एक से अधिक फ्लैट खरीदने की अनुमति भी दी गई है। इससे पात्र कर्मचारियों के पास अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। हालांकि, फ्लैट खरीदने से पहले आवेदकों को योजना की विस्तृत शर्तों, पात्रता मानदंड, भुगतान व्यवस्था, दस्तावेजों और अन्य नियमों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा। पहले आओ, पहले पाओ' व्यवस्था के कारण इच्छुक आवेदकों के लिए समय पर आवेदन करना अहम रहेगा। उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या सीमित होने के कारण पसंदीदा स्थान या श्रेणी के फ्लैट जल्दी बुक हो सकते हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना की आधिकारिक जानकारी देखकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

नरेला में तैयार फ्लैट्स, 25 प्रतिशत की छूट, संपत्ति रखने वाले लोगों को आवेदन की अनुमति और एक से अधिक फ्लैट खरीदने की सुविधा इस योजना को खास बनाती है। डीडीए की इस पहल से सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली में अपेक्षाकृत किफायती दर पर घर खरीदने का अवसर मिल सकता है।

गुरुग्राम में सनसनीखेज वारदात कमरे में युवक की चाकू से हत्या

एजेंसी, नई दिल्ली

गुरुग्राम के सेक्टर-14 थाना क्षेत्र स्थित राजीव नगर की गली नंबर पांच में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव गुरुवार सुबह एक कमरे से बरामद हुआ। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि वारदात के बाद कमरे में रहने वाला किराएदार फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। उसकी उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस कमरे से शव बरामद हुआ, उसमें एक युवक किराए पर रहता था। बताया जा रहा है कि उसने बुधवार रात मृतक को किसी काम से कमरे पर बुलाया था। इसके बाद कमरे में ही युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से शव बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस अब फरार किराएदार की तलाश में जुटी है। जांच अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मृतक और किराएदार के बीच क्या संबंध था और हत्या के पीछे की वजह क्या रही। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपी तक पहुंचने में मदद मिल सके। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच तेज कर दी है। फरार किराएदार की तलाश जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हत्या की वजह और आरोपी की पहचान में जुटी है।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत गाजियाबाद में भव्य तिरंगा कॉन्सर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली

गाजियाबाद में जिला प्रशासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम गीत की जयंती के अवसर पर गुरुवार को पंडित दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों और प्रस्तुतियों के माध्यम से समां बांध दिया। विद्यार्थियों ने 'मैं रहूं या न रहूं, भारत रहना चाहिए', 'लहरा दो तिरंगा' सहित कई देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। उनकी शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों में देशप्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने देश के अमर बलिदानियों को नमन करते हुए उनके त्याग और समर्पण को याद किया। कार्यक्रम में सांसद अतुल गर्ग ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर केवल अवकाश घोषित कर दिया जाता था। आज इन पर्वों को उत्साह और गौरव के साथ मनाने की परंपरा विकसित हुई है।

न्यूज ब्रीफ

श्री साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन बधानी का एमएड चौथे सेमेस्टर का परिणाम 100 प्रतिशत

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। श्री साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बधानी, पठानकोट कैंपस के एमएड चौथे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। कॉलेज का परिणाम 100 प्रतिशत रहा। इस उपलब्धि पर ग्रुप के चेयरमैन एसके पुंज, एमडी तृप्ता पुंज और सीएमडी कंवर तुषार पुंज ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। एमएड चौथे सेमेस्टर में मनीषा ने 8.26 सीजीपीए प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। पलक ने 8.05 सीजीपीए के साथ दूसरा स्थान, जबकि पल्लवी ने 7.93 सीजीपीए प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर कॉलेज का नाम रोशन किया। ग्रुप के चेयरमैन एसके पुंज ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना व्यक्ति का मानसिक विकास संभव नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी तरह मेहनत और लगन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एमडी तृप्ता पुंज ने सभी विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन से कॉलेज ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. नवदीप सांवल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जसवंत कौर सहित कॉलेज का स्टाफ और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू की

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी इकाई ने प्रदेशस्तरीय छात्र मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल में विद्यार्थी परिषद के 18 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इकाई अध्यक्ष करण ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थियों के हितों और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाती रही है। प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र हितों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उचित निर्णय न लिए जाने के कारण परिषद को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बढ़ाई गई फीस को वापस लिया जाए और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का दायरा प्रदेश सरकार द्वारा बहाल किया जाए। करण ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों की जायज मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो परिषद लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेगी।

व्यापार मंडल ने जताया सरकार का आभार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। व्यापार मंडल भराड़ी ने भराड़ी और बाड़ा दा घाट में सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने पर प्रदेश सरकार और मंत्री राजेश धर्माणी का आभार जताया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि अजमेरपुर ग्रीष्म महोत्सव के दौरान क्षेत्रवासियों ने सार्वजनिक शौचालय की मांग मंत्री के समक्ष रखी थी, जिस पर उन्होंने प्राथमिकता से संज्ञान लेते हुए धनराशि उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि भराड़ी में प्रतिदिन सैकड़ों लोग, विशेषकर महिलाएं, बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग पहुंचते हैं। ऐसे में सार्वजनिक शौचालय लंबे समय से जरूरी था। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसमें अवरोध पैदा किया जा रहा है। व्यापार मंडल ने प्रशासन से निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर कर इसे जल्द पूरा करवाने की मांग की। प्रधान राजेश शर्मा ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह सुविधा आम जनता के लिए है। महासचिव दीनानाथ शर्मा ने भी मंत्री का आभार जताया।

पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दर्ज किए केस

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर पुलिस ने अलग-अलग शिकायतों के आधार पर दो मामले दर्ज किए हैं। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस थाना भराड़ी में अमर सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी गांव तडौन, डाकघर तडौन, उपतहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर की शिकायत पर उपप्रधान धर्मेंद्र सहित अन्य के खिलाफ सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं, पुलिस चौकी खारसी में भागीरथ पुत्र स्वर्गीय लेखराम निवासी गांव समोग ब्राह्मणा, डाकघर छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर की शिकायत पर तेलू राम पुत्र नथू राम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी उसके आंगन में आया और उसके साथ गाली-गलौच करने के साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों मामलों में शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि मामलों में नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नाहन में 17 अगस्त को होगा कैंपस इंटरव्यू

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। जिला रोजगार अधिकारी देविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मेसर्ज बारबीक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लि0 कोलकाता पश्चिम बंगाल द्वारा दिल्ली, पुणे, मुंबई, गुजरात, चिन्नेई और बैंगलोर स्थित रेस्तरां के लिए किचन हेल्पर/फूड एंड बेवरेज स्टीवर्ड के 500 पदों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरा जाना है जिसके लिए रोजगार कार्यालय नाहन में कैम्पस इंटरव्यू 17 अगस्त, 2026 को आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षिणक योग्यता 10वीं/12वीं, आयु 18 से 30 वर्ष रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ अपनी शैक्षिणक तथा योग्यता संबंधी सभी दस्तावेज स्थायी हिमाचली प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, 2 पासपोर्ट साईज फोटो सहित कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते है। इन पदों के लिए न्यूनतम वेतन 16 हजार सीटीसी/20 हजार सीटीसी (डिपलोमा होल्डर इन होटल मेनेजमैंट व समकक्ष) सहित खाना व मुफ्त आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियर्थियों के चयन होने के उपरांत दिल्ली में सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके खर्च का पूरा निर्वाहन कंपनी द्वारा किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : धर्माणी

कोट पंचायत में किसानों को प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। कोट पंचायत के सिद्ध बाबा गोदडिया मंदिर में कृषि विभाग व कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा), बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में किसानों को प्राकृतिक खेती तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास तथा तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने की।

राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत कम करने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं और मक्की के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। प्राकृतिक गेहूं का समर्थन मूल्य 80 रुपए तथा मक्की का 60 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। आगामी वर्ष हल्दी का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूध के समर्थन मूल्य में वृद्धि के माध्यम से पशुपालकों को भी उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य दिया जा रहा है। आत्मा बिलासपुर के अनुसार राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं मॉडल फार्मों का भ्रमण करवाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक 15,076 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 3,012 किसान 455 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। योजना के तहत देशी गाय की खरीद पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 हजार रुपये, गाय के रखरखाव के लिए फर्श पक्का करने पर 8 हजार रुपये तक तथा प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले घटकों की तैयारी के लिए प्लास्टिक ड्रम पर 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 750 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। संसाधन भंडार स्थापित करने के लिए 15 हजार रुपए तक का अनुदान भी उपलब्ध है।

सीएम के घुमारवीं प्रवास की तैयारियों का लिया जायजा

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के 14 अगस्त को घुमारवीं प्रवास को लेकर मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सभी आवश्यक कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के साथ-साथ यातायात, बैठने, पेयजल, बिजली व अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री 14 अगस्त को घुमारवीं के निहारी में 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह में बतौर मुख्यातिथि शामिल होंगे।

सिकरी धार सीमेंट प्लांट को धरातल पर उतारे सरकार : डॉ. राजीव भारद्वाज

◆ चंबा-कांगड़ा के हजारों युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने जिला चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से विचाराधीन सिकरी धार सीमेंट प्लांट को जल्द स्थापित करने की मांग उठाई है। उन्होंने इस संबंध में संबंधित केंद्रीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यह परियोजना चंबा जैसे आकांक्षी जिले के आर्थिक विकास और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि सिकरी धार सीमेंट प्लांट को लेकर पूर्व में टेंडर प्रक्रिया भी की गई थी, लेकिन किसी कंपनी द्वारा टेंडर नहीं लिया गया। इसके पीछे सड़क संपर्क की समस्या एक प्रमुख कारण के रूप में सामने आई थी। उन्होंने कहा कि वर्षों से विचाराधीन इस महत्वपूर्ण परियोजना को अब आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रदेश स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि चंबा एक आकांक्षी जिला है व भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां रोजगार व औद्योगिक विकास की संभावनाएं सीमित रही हैं। सिकरी धार सीमेंट प्लांट स्थापित होने से क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने की मजबूरी कम होगी।

डॉ. भारद्वाज ने कहा कि इस परियोजना का लाभ केवल चंबा जिले तक सीमित नहीं रहेगा। चंबा के साथ-साथ कांगड़ा जिले के युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सीमेंट प्लांट शुरू होने से परिवहन, छोटे व्यवसाय, स्थानीय बाजार, होटल-ढाबे और अन्य सहायक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।

ब्लॉक समिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा का दबदबा

अंकुश इंदौरिया अध्यक्ष और आकाश कटोच उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। ब्लॉक समिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने अपना दबदबा कायम करते हुए दोनों पदों पर निर्विरोध जीत हासिल की। अंकुश इंदौरिया को ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, जबकि आकाश कटोच को उपाध्यक्ष चुना गया। चुनाव में कुल 26 बीडीसी सदस्यों में से 25 सदस्य उपस्थित रहे। कांग्रेस की ओर से दोनों पदों के लिए कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया।

भाजपा नेताओं ने इस जीत का श्रेय पूर्व विधायक रीता धीमान, गगरेट के पूर्व विधायक राजेश ठाकुर व पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद इसे इंदौरा में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस मौके पर पूर्व विधायक रीता धीमान ने स्थानीय विधायक मलेंद्र राजन पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्लॉक समिति के चुनाव को करीब 74 दिनों तक रोके रखा गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा अध्यक्ष अंकुश इंदौरिया को चुनाव करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 21 जुलाई से पहले चुनाव करवाने के निर्देश एसडीएम इंदौरा को दिए गए थे। रीता धीमान ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के माध्यम से रिट याचिका दायर करवाई गई और इंदौरा थाने में 12 महिलाओं समेत कई लोगों को बुलाकर परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि विधायक को ऐसी राजनीति छोड़कर जनता की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। रीता धीमान ने कहा कि पिछले दो-तीन महीनों से मोहटली-इंदौरा मार्ग बंद पड़ा है, लेकिन विधायक ने मौके का दौरा तक नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जनता की समस्याओं के बजाय उद्घाटन और वाहवाही की राजनीति में अधिक रुचि ले रहे हैं। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य अभिमन्यु कंवर, महंत काली दास, मोतीलाल जोशी, अश्वनी शर्मा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बिलासपुर में मंदिर से तांबे का नाग चोरी, दो आरोपी काबू, एक नाबालिग

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर के अपर निहाल सेक्टर स्थित शिव चामुंडा माता मंदिर से तांबे का नाग चोरी करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को काबू किया है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया गया तांबे का नाग भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार, 11 अगस्त को दो आरोपियों को शिव चामुंडा माता मंदिर से तांबे का नाग चोरी करते हुए देखा गया था। इस संबंध में 12 अगस्त को थाना सदर बिलासपुर में मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को ट्रेस कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात में शामिल एक आरोपी नाबालिग है। नाबालिग आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार अलग से कार्रवाई की जा रही है। वहीं, दूसरे आरोपी की पहचान ऋषभ शर्मा (21) पुत्र राम पाल शर्मा, निवासी गांव चमलोग, डाकघर देवली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपी ऋषभ शर्मा से पूछताछ की। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर मंदिर से चोरी किया गया तांबे का नाग बरामद कर लिया गया है। पुलिस द्वारा मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एम्स बिलासपुर में नवजातों के उपचार के लिए स्थापित होंगे छह ह्यूमिडिफायर

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। एम्स बिलासपुर के नियोनेटोलॉजी विभाग में नवजात शिशुओं के उपचार के लिए छह ह्यूमिडिफायर स्थापित किए जाएंगे। यह सुविधा खासतौर पर गंभीर और समय से पहले जन्मे उन बच्चों के लिए उपयोगी होगी, जिन्हें ऑक्सीजन, सीपीएपी, वेंटिलेटर या अन्य श्वसन सहायता की आवश्यकता होती है। नियोनेटोलॉजी में भर्ती कई नवजातों को सांस लेने में परेशानी होती है, ऐसे में केवल ऑक्सीजन देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि गैस का उचित तापमान और नमी के साथ शिशु के श्वसन तंत्र तक पहुंचना भी जरूरी होता है। ह्यूमिडिफायर गैस को गर्म और नम बनाए रखने में मदद करता है, जिससे श्वसन मार्ग में सूखापन और जलन जैसी समस्याओं को कम करने में सहायता मिल सकती है। एम्स प्रशासन के अनुसार, संस्थान में नवजात देखभाल की सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के बुनियादी प्रशिक्षण का कैलेंडर जारी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों व उपप्रधानों के बुनियादी प्रशिक्षण का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। प्रशिक्षण जिला पंचायत संसाधन केंद्र बिलासपुर में सात बैचों में आयोजित होगा। यह जानकारी जिला पंचायत अधिकारी यशपाल ने दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बैच में चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें पंचायतीराज व्यवस्था, पंचायतों के अधिकार व दायित्व, ग्राम सभा की भूमिका, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन, विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पहले बैच में श्री नयना देवी विकासखंड की 25 पंचायतों के प्रतिनिधियों को 8 से 11 सितंबर तक प्रशिक्षण मिलेगा। इसके बाद झंडूता की 45 पंचायतों, घुमारवीं की 63 पंचायतों और सदर विकासखंड की 49 पंचायतों के प्रतिनिधियों को अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

व्यवस्था परिवर्तन नहीं, कर्मचारियों व युवाओं के व्यवस्था पतन की सरकार है सुक्खू सरकार : सुधीर

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। धर्मशाला के विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं, कर्मचारियों और आम जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाए व सत्ता में आने के बाद उन्हीं वादों से मुंह मोड़ लिया, जिस समय 'व्यवस्था परिवर्तन' का ढोल चुनाव के दौरान पीटा गया था, आज वही व्यवस्था वादाखिलाफी, वित्तीय अव्यवस्था और कर्मचारियों की अनदेखी का पर्याय बनती जा रही है, जिन कोरोना वॉरियर्स ने महामारी के सबसे कठिन दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर प्रदेश की सेवा की, सरकार ने उन्हें ही नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिन लोगों ने संकट के समय सरकार और जनता का साथ दिया, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।

सुधीर शर्मा ने कहा की चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने युवाओं को सरकारी नौकरियों और 58 वर्ष तक रोजगार की बातें बताईं, लेकिन सत्ता में आने के बाद रोजगार के बड़े वादे कहां चले गए? युवाओं के हाथ नौकरी की जगह निराशा आई व विभिन्न 'मित्र' श्रेणियों में नियुक्तियों को लेकर सरकार पर भाई-भतीजावाद और राजनीतिक लाभ के आम चर्चा हैं। उन्होंने कहा की आज कर्मचारी सवाल पूछे तो सरकार को इतना डर क्यों लगता है। कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग उठाए, तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करना किस प्रकार का लोकतंत्र है? कर्मचारियों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें डराने व दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को याद रखना चाहिए कि कर्मचारी किसी सरकार की निजी संपत्ति नहीं हैं। वे प्रदेश की व्यवस्था की रीढ़ हैं और उन्हें अपनी समस्याएं उठाने का पूरा अधिकार है, जो सरकार अपने ही कर्मचारियों की आवाज से डर जाए, वह व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था के पतन की निशानी होती है।

ठियोग कॉलेज में 'सृजन-2026' के साथ नवागत विद्यार्थियों का भव्य स्वागत

पियूष मिस्टर, स्नेहा ने जीता मिस फ्रेशर का खिताब

भारतेन्दु संवाददाता, ठियोग। राजकीय महाविद्यालय ठियोग में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रथम सेमेस्टर के बीए, बीकॉम और बीएससी के नवागत विद्यार्थियों के स्वागत के लिए गुरुवार को फ्रेशर्स पार्टी 'सृजन-2026' का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में महाविद्यालय के करीब 500 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. भूपिंदर सिंह ठाकुर मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। नवागत विद्यार्थियों के स्वागत के लिए गायन, नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं। मॉडलिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। मॉडलिंग प्रतियोगिता में रैंप वॉक, प्रतिभा प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर के विभिन्न चरण आयोजित किए गए। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर पियूष को मिस्टर फ्रेशर और स्नेहा को मिस फ्रेशर चुना गया। लड़कों की श्रेणी में सूर्यांश शर्मा और वंशज को क्रमशः प्रथम और द्वितीय रनर-अप घोषित किया गया। छात्राओं की श्रेणी में दीक्षा और अनामिका को क्रमशः प्रथम और द्वितीय रनर-अप का खिताब मिला। इसके अलावा ध्रुवकांत को मिस्टर पर्सनैलिटी और आयुषी को मिस पर्सनैलिटी, जबकि तुषार और दिव्यांशी को क्रमशः मिस्टर टैलेंटेड और मिस टैलेंटेड चुना गया।

अनमोल और अतिदी को मिस्टर अटायर और मिस अटायर के खिताब से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. भूपिंदर सिंह ठाकुर ने प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का महाविद्यालय परिवार में स्वागत किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन बनाए रखने तथा शैक्षणिक, सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई देते हुए पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज की डीन छात्र कल्याण डॉ. अनीता राठौर ने भी विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी और उन्हें महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के समापन पर डॉ. श्रद्धा शांडिल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने विद्यार्थियों तथा महाविद्यालय के समस्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके सहयोग की सराहना की। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी उपस्थित रहे।

हिमाचल में सेस राज : अनाथ-विधवा सेस के बहाने जनता की जेब काट रही सरकार : संजय

◆ ईंधन, बिजली और पानी पर लगातार नए टैक्स से प्रदेशवासी परेशान: भाजपा

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा जनकल्याण के नाम पर जनता पर लगातार थोपे जा रहे वित्तीय बोझ पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा प्रहार किया है।

प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लागू किए गए तथाकथित अनाथ व विधवा सेस पर हमला बोलते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि यह सरकार जनकल्याण के नाम पर प्रदेश की आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है। अनाथ और विधवा सेस के नाम पर नए-नए कर लगाकर प्रदेश सरकार असल में हिमाचल की जनता को ही आर्थिक रूप से अनाथ बनाने पर तुली है। वीरवार को जारी एक प्रेस बयान में संजय शर्मा ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से कांग्रेस सरकार का पूरा ध्यान जनसेवा के बजाय सिर्फ टैक्स और सेस लादने पर रहा है। चाहे ईंधन हो, बिजली हो, पानी हो या उद्योग, सरकार ने हर मोर्चे पर प्रदेशवासियों पर टैक्स की भारी मार मारी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर 'अनाथ व विधवा सेस' लादकर सरकार ने परिवहन और दैनिक उपभोग की वस्तुओं को महंगा कर दिया है।

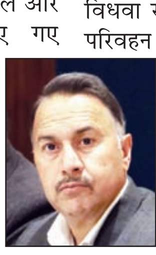

इससे पूर्व बिजली बिलों के माध्यम से प्रति यूनिट मिल्क सेस वसूला जा रहा है, जिससे आम उपभोक्ता से लेकर छोटे व्यापारी तक प्रभावित हैं। बिजली की खपत पर पर्यावरण सेस लगाकर उद्योगों और वाणिज्यिक गतिविधियों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। यही नही होटल, अस्पताल, मॉल और दुकानों जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली दर पर एक रुपये प्रति यूनिट तक का अतिरिक्त सेस थोप दिया गया है। जल उपकर की कोशिशों के साथ-साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के दाम बढ़ाकर जनता को बेहाल कर दिया गया है।

राहत जम्वाल ने कहा- अस्पताल को जल्द मिलेगा बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर व डेड बॉडी वैन

मरीजों की सुविधा के लिए शेड व 10 एसी लगेंगे

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रयासों से बिलासपुर अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके तीमारदारों की सुविधा के लिए शेड का निर्माण किया जाएगा।

शेड में 10 एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। एसी सुविधा वाला शेड बनने से गर्मी के मौसम में मरीजों और तीमारदारों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने और मरीजों की समस्याएं जानने के लिए विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बिलासपुर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर विभिन्न विकास कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। विधायक ने रक्त सहित विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए एक और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में माइनिंग फंड से अस्पताल के लिए करीब डेढ़ करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। करीब 20 लाख रुपए की लागत से एक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पहले ही अस्पताल को उपलब्ध करवाया जा चुका है। अब एक और मशीन जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने अस्पताल के लिए करीब 7 से 8 लाख रुपए की लागत से डेड बॉडी वैन उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। इससे बीमारी या हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को शव घर ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। त्रिलोक जम्वाल ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने तथा शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस दिशा में गंभीरता से कार्य किया जाएगा। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 50 लाख रुपये का एस्टीमेट विधायक को सौंपा। विधायक ने जल्द धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

पेट्रोल व डीजल पर सर्वाधिक टैक्स थोपने वाले मुख्यमंत्री बने सुक्खू : राकेश जम्वाल

◆ पेट्रोल-डीजल पर नया सेस लगाकर जनता की जेब पर डाला बोझ

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपने पूर्ववर्ती तमाम कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर ईंधन पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने का शर्मनाक कीर्तिमान अपने नाम दर्ज करा लिया है।

सत्ता में आने से पूर्व जनता को लोकलुभावन गारंटियों का झांसा देने वाली कांग्रेस का असली और जनविरोधी चरित्र अब पूरी तरह उजागर हो चुका है। 'व्यवस्था परिवर्तन' का नारा देने वाली इस सरकार का असल मकसद केवल जनता की जेब में डकैती डालना और नए-नए करों का चाबुक चलाकर आम नागरिक का जीना दूभर करना रह गया है। यहां जारी एक प्रेस बयान में राकेश जम्वाल ने जनाक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जनवरी 2023 से लेकर अब तक इस नकारा सरकार ने हिमाचल की जनता पर तीन-तीन बार कर का चाबुक चलाया है। केवल एक ही वर्ष में डीजल पर कुल 6 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त डाका डालकर बागवानों, किसानों, ट्रांसपोर्टरों और दैनिक यात्रियों की कमर तोड़ दी गई। भाजपा मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि अगस्त 2026 आते-आते सुक्खू सरकार ने जनता की जेब काटने का एक नया नायाब पैंतरा इजाद कर लिया। वैट कानून में गुपचुप संशोधन का खेल खेलकर पेट्रोल और डीजल पर 'अनाथ एवं विधवा सेस' के नाम पर एक नया कर लगा दिया गया। विधायक राकेश जम्वाल ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि झूठे वादों के बूते सत्ता में आई इस जनविरोधी और दोहरे चरित्र वाली कांग्रेस सरकार को हिमाचल की स्वाभिमानी जनता कभी माफ नहीं करेगी।

न्यूज ब्रीफ

बच्चों के पोषण पर महिलाओं से लिया फीडबैक

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। छोटे बच्चों में कुपोषण को रोकने और उनका सही पोषण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और महिला व बाल विकास विभाग की विशेष पहल के अंतर्गत भोरंज उपमंडल में पायलट आधार पर आरंभ किए गए न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन (पोषण हस्तक्षेप) कार्यक्रम की प्रगति एवं इसके बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने वीरवार को यहां मिनी सचिवालय में महिलाओं के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में छोटे बच्चों की माताओं सहित कुल 55 महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन (पोषण हस्तक्षेप) अभियान के तहत भोरंज में छोटे बच्चों को पौष्टिक गुणों से भरपूर रागी के पाउडर का वितरण आरंभ किया गया है। इन बच्चों की माताओं से रागी पाउडर के उपयोग, बच्चों की प्रतिक्रिया, प्राप्त अनुभवों एवं सुझावों के मद्देनजर ही यह संवाद सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कई माताओं ने रागी पाउडर के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भविष्य में भी बच्चों के पोषण में इसके उपयोग को जारी रखने पर सहमति जताई। डीसी ने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए स्थानीय एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक प्रयोग तथा अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। साथ में उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित होम विजिट करने तथा रागी पाउडर से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने रागी पाउडर के उपयोग, बच्चों की प्रतिक्रिया तथा माताओं से प्राप्त फीडबैक पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। एसडीएम भोरंज शशि पाल शर्मा ने उपायुक्त का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रागी पाउडर से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट के लिए भोरंज का चयन किया जाना बच्चों के बेहतर पोषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने इस पहल के लिए जिला प्रशासन का धन्यवाद किया।

सिरमौर की पंचायतों में कल होगी विशेष ग्राम सभा

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने यह आदेश जारी करते हुए बताया कि 15 अगस्त को जिला की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठक आयोजित की जाएगी। डीसी ने बताया कि 15 अगस्त को सभी ग्राम पंचायतों में एग्रीस्टैक पोर्टल के अंतर्गत विशेष किसान पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाना है। इसी के लिए यह विशेष ग्राम सभा बैठक निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस विशेष ग्राम सभा में कोरम को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टैक पोर्टल के तहत किसानों का पंजीकरण कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उपलब्ध करवाया जाएगा।

54 लेक्चररों को मिलेगा 47 हजार वेतन स्तर का लाभ

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए 54 लेक्चररों को दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर 47 हजार रुपए के उच्च वेतन स्तर का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। यह लाभ आगे होने वाली कानूनी कार्यवाही या संभावित अपील के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। विभाग के अनुसार इन लेक्चररों की नियुक्ति वर्ष 2013-14 में लेक्चरर (स्कूल न्यू) के पद पर हुई थी और सेवाएं वर्ष 2017 में नियमित की गई थीं। उन्होंने वर्ष 2019 में दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली थी। निदेशालय ने संबंधित कर्मचारियों का वेतन 47 हजार रुपए के स्तर पर निर्धारित करने और नियमानुसार बकाया राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, भविष्य में यदि फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो अतिरिक्त भुगतान वापस करना होगा। इसके लिए कर्मचारियों से लिखित आश्वासन लेकर सेवा पुस्तिका में दर्ज करने को कहा गया है।

अब ऑनलाइन होगी पुलिस कर्मचारियों की हाजिरी, छुट्टी के आवेदन भी डिजिटल

पुलिस विभाग में ई-एचआरएमएस अनिवार्य, कागजी हाजिरी रजिस्टर होंगे बंद

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में अब कर्मचारियों की हाजिरी से लेकर छुट्टी, तबादला, सेवा रिकॉर्ड और वेतन तक लगभग हर प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी।

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, बटालियनों, पुलिस थानों, चौकियों और अन्य इकाइयों में ई-एचआरएमएस (मानव संपदा) प्रणाली को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अधिकांश कार्यालयों में वर्षों से इस्तेमाल हो रहे कागजी उपस्थिति रजिस्टर बंद करने का फैसला भी लिया गया है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक इससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों से जुड़े मामलों का निपटारा अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सकेगा। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब सभी कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। बिना अनुमति अनुपस्थिति या देरी की जानकारी सीधे प्रणाली में दर्ज होगी और इसका असर वेतन प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए आवेदन और उनकी स्वीकृति केवल ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से होगी। कागजी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, तबादला, शैक्षणिक योग्यता, वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य सेवा संबंधी विवरण भी डिजिटल सेवा पुस्तिका में अद्यतन रखना अनिवार्य किया गया है।

प्रत्येक कर्मचारी को हर वर्ष अपनी सेवा पुस्तिका का सत्यापन करना होगा और किसी त्रुटि की स्थिति में उसे 15 दिनों के भीतर ठीक करना होगा।

तबादले से लेकर एसीआर तक सब कुछ डिजिटल

नई व्यवस्था के तहत आंतरिक समायोजन, शाखाओं के बीच तैनाती और विभिन्न इकाइयों के बीच तबादले भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे। कार्यभार ग्रहण करने और कार्यमुक्त होने की रिपोर्ट भी पोर्टल पर ही तैयार होगी। पुलिस कर्मियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तथा प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट भी अब ऑनलाइन भरी जाएंगी। हर जिला, बटालियन और इकाई में निरीक्षक, उपनिरीक्षक या अधीक्षक स्तर का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कर्मचारियों की सहायता करेगा और तकनीकी समस्याओं का समाधान करेगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी कार्यालय प्रमुखों को हर सप्ताह समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का पालन नहीं होने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख और आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

स्वदेशी, खादी और राष्ट्र निर्माण को जीवन का हिस्सा बनाएं युवा: अनुराग

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने वीरवार को नई दिल्ली के डीएवी स्कूल, यूसेफ सराय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल समुदाय के सदस्यों से संवाद करते हुए युवाओं से स्वतंत्रता संग्राम की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवा स्वदेशी को अपनाएं, खादी को बढ़ावा दें और भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि देश के प्रति आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना है। स्वदेशी को अपनाने से देश के किसान, कारीगर, उद्यमी और उद्योग मजबूत होते हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। अनुशासन, मेहनत, नवाचार और राष्ट्र सेवा के माध्यम से युवा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने वंदे मातरम् के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है व पीढ़ियों से यह देशवासियों की भावनाओं से जुड़ा रहा है।

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान भारत के राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता संघर्ष की दो समान रूप से सम्मानित अभिव्यक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की विरासत का सम्मान करना उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस गीत से प्रेरणा लेकर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों से स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष से प्रेरणा लेने तथा विकसित, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

हिमाचल के लोक कलाकार डॉ. जोगिंदर हब्बी को राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकार डॉ. जोगिंदर हब्बी को लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया।

यह जानकारी पद्मश्री सम्मान प्राप्त वरिष्ठ साहित्यकार एवं लोक संस्कृति विशेषज्ञ विद्यानंद सरैक और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित लोक कलाकार गोपाल हब्बी ने संयुक्त बयान में दी। उन्होंने बताया कि संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से देश के विभिन्न क्षेत्रों में कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। डॉ. जोगिंदर हब्बी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश, विशेष रूप से सिरमौर जिले की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। विद्यानंद सरैक और गोपाल हब्बी ने कहा कि डॉ. हब्बी के नेतृत्व में पिछले लगभग तीन से साढ़े तीन दशकों से लोक कलाकारों ने देश और विदेश के हजारों मंचों पर सिरमौर की हाटी संस्कृति को पहचान दिलाने का कार्य किया है। उन्होंने पारंपरिक लोक संस्कृति को मूल स्वरूप में बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इस दौरान उन्होंने रीमिक्स गीतों और इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों से दूरी बनाए रखते हुए पारंपरिक लोक वाद्य, लोक वेशभूषा, लोक गीत और लोक नृत्यों को बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि सिरमौरी नाटी सहित कई पारंपरिक और विलुप्ति की ओर बढ़ रही लोक कला विधाओं के संरक्षण में डॉ. हब्बी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिरमौरी नाटी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उनके प्रयासों को विभिन्न वैश्विक अभिलेखों में भी दर्ज किया जा चुका है।

एनएसयूआई के संगठनात्मक चुनावों के लिए सदस्यता अभियान शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में एनएसयूआई के संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया के तहत सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। प्रदेश चुनाव प्रभारी राकेश बैरवा ने बताया कि नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद 9 अगस्त को अंतिम नामांकन घोषित कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सदस्यता मंच 12 अगस्त सुबह 9 बजे से 10 सितंबर शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान पात्र विद्यार्थी सदस्यता लेकर निर्धारित शुल्क जमा कर चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तकनीकी या अन्य वास्तविक कारणों से समय पर शुल्क जमा न कर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए 11 सितंबर को विशेष अवसर दिया जाएगा। बैरवा ने कहा कि प्रथम वर्ष में नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी भी पात्रता शर्तों और शुल्क रसीद के आधार पर सदस्यता ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान के दौरान विद्यार्थियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

बिजली बोर्ड के कर्मी की मौत पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सरकार व संबंधित पक्षों को नोटिस

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड के एक कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से हुई मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है।

अदालत ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को नोटिस जारी किए हैं। यह मामला मृतक बारू राम की पत्नी की ओर से भेजे गए एक प्रतिवेदन के आधार पर हाईकोर्ट के संज्ञान में आया। बारू राम बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्यरत थे। 5 जुलाई 2026 को काम के दौरान उनका संपर्क बिजली प्रवाहित लाइन से हो गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया व न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बिजली बोर्ड की ओर से प्रस्तुत टिप्पणियों में इस घटना की जिम्मेदारी निजी ठेकेदारों पर डाली जा रही है। इनमें रेल विकास निगम लिमिटेड, उसका संयुक्त उपक्रम ठेकेदार मेसर्स एयरेफ इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और उप-ठेकेदार मेसर्स निहाल इंफ्राटेक का नाम शामिल है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा मानकों और संबंधित दायित्वों का उचित पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बारू राम की मृत्यु हुई। खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसी परिस्थितियों में मृतक के परिवार के पास राहत प्राप्त करने का कोई प्रभावी उपाय नहीं बचता दिखाई देता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर लिया और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की गई है।

भारत माता के जयकारों से गूंजा मंडी

पायल वैद्य बोलीं- आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ना जरूरी

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मंडी शहर में भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर भाजपा कार्यकर्ता, युवा, बच्चे और शहर के प्रबुद्ध लोग यात्रा में शामिल हुए।

भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से मंडी शहर गूंज उठा। यात्रा के दौरान लोगों में देशभक्ति का उत्साह देखते ही बना। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि देशभर में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार 'हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा और हर मन तिरंगा' का संदेश दिया है। इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मंडी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। पायल वैद्य ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान व शान है। 15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ और यह दिन प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को यह याद रहना चाहिए कि देश सबसे पहले आता है और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं और बच्चों को देश के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और वीर शहीदों के बलिदान से अवगत करवाना जरूरी है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवा पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य का संदेश दिया जा रहा है। पायल वैद्य ने बताया कि प्रदेश में आठ अगस्त को भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से शामिल हुए थे। इसी कड़ी में जिला और विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं।

तिरंगा देश की आन, बान व शान का प्रतीक: निहालचंद

भाजपा जिलाध्यक्ष निहालचंद शर्मा ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। युवाओं को तिरंगे के महत्व और इसके पीछे छिपे देश के गौरव, संघर्ष और बलिदान को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों को राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ना और आने वाली पीढ़ी को देश के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास करवाना है। आज के युवा देश का भविष्य हैं और उनके मन में राष्ट्र प्रथम की भावना मजबूत होना जरूरी है। मेयर सुमन ठाकुर, डिप्टी मेयर जितेंद्र जॉनी सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा, बच्चे और प्रबुद्धजन भी यात्रा में शामिल हुए। पायल वैद्य ने लोगों से आह्वान किया कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर में तिरंगा लहराए और हर मन में तिरंगा बसाए।

छोटा शिमला स्कूल पहुंचे गौरव सिंह छात्रों को नशे के खतरों से किया आगाह

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला शिमला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत वीरवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोटा शिमला का दौरा कर विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों, इसके सामाजिक और मानसिक असर तथा नशे से दूर रहने के महत्व के बारे में जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों से सीधे बातचीत की और उन्हें बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में सही दिशा चुनने, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने का आग्रह किया। संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया।

विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और इस सामाजिक बुराई से दूर रहने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार भी साझा किए। गौरव सिंह ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने मित्रों, परिवार और आसपास के लोगों को भी नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करें। उन्होंने युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नशामुक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण में विद्यार्थियों की भागीदारी आवश्यक है।

पीएम मोदी से मिले सांसद सिकंदर, प्रदेश के विकास और आपदा राहत पर हुई चर्चा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रो. (डॉ.) सिकंदर कुमार ने वीरवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

उन्होंने इस बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास से जुड़ी विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही हाल के दिनों में प्रदेश में हुई भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुद्दा भी उठाया गया। मुलाकात के बाद जारी बयान में डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी दी। प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मौजूदा हालात पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष जुड़ाव रहा है और बातचीत के दौरान प्रदेश के विकास तथा लोगों के हितों को लेकर उनकी चिंता दिखाई दी। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और परिवहन क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

बैठक के दौरान इन परियोजनाओं की प्रगति और उन्हें आगे बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ऊना में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क, नालागढ़ का मेडिकल डिवाइस पार्क, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, आईआईटी मंडी, ट्रिपल आईटी ऊना और केंद्रीय विद्यालयों सहित शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की कई योजनाएं प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार इन परियोजनाओं से विकास को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डॉ. सिकंदर कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल की सड़क और रेल संपर्क परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कीरतपुर-नेरचौक, शिमला-मटौर, पठानकोट-मंडी और पिंजौर-नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अहम हैं। इसी तरह भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन और चंडीगढ़-बद्दी रेल परियोजना से प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर सकारात्मक आश्वासन मिला है।

नूरपुर के दो सरकारी स्कूलों का पुनर्गठन, एक सीबीएसई व दूसरा हिमाचल बोर्ड से रहेगा संबद्ध

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले के नूरपुर स्थित दो सरकारी विद्यालयों के पुनर्गठन संबंधी पहले जारी आदेशों में संशोधन किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब दोनों विद्यालय स्वतंत्र सहशिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के रूप में संचालित होंगे। इनमें एक विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध रहेगा, जबकि दूसरा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होगा।

शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत बख्शी टेक चंद प्रधानमंत्री श्री राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूरपुर का नाम बदलकर बख्शी टेक चंद प्रधानमंत्री श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूरपुर कर दिया गया है। यह विद्यालय मुख्य विद्यालय के रूप में कार्य करेगा और इसकी संबद्धता सीबीएसई से बनी रहेगी। वहीं, राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूरपुर का नाम बदलकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूरपुर कर दिया गया है। यह विद्यालय हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा और स्वतंत्र रूप से संचालित होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से दोनों संस्थानों के पुनर्गठन का निर्णय लिया था। उस समय दोनों विद्यालयों को अलग-अलग सहशिक्षा संस्थानों के रूप में गठित करने की योजना बनाई गई थी। उस व्यवस्था में एक विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और दूसरे को उच्च विद्यालय के रूप में संचालित किया जाना था। अब शिक्षा विभाग ने पूर्व व्यवस्था में बदलाव करते हुए दोनों संस्थानों को सहशिक्षा वाले वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में चलाने का फैसला लिया है। विभाग के अनुसार दोनों विद्यालय स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और उनकी प्रशासनिक तथा शैक्षणिक पहचान अलग-अलग रहेगी। नई अधिसूचना के बाद बख्शी टेक चंद प्रधानमंत्री श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूरपुर सीबीएसई से संबद्ध मुख्य विद्यालय के रूप में कार्य करेगा, जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूरपुर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा।

सुविधा लोक निर्माण मंत्री ने 18 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

शिमला ग्रामीण को मिलीं 30 इलेक्ट्रिक बसें

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के पुराने बस अड्डे से विभिन्न क्षेत्रों के लिए 18 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने क्षेत्रवासियों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू एवं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का समान विकास करवाना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए हर संभव प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर क्षेत्र शिमला शहर के साथ सटा हुआ है व यहां के अधिकतर लोग सरकारी नौकरी के साथ-साथ किसान व बागवान भी हैं, जिनका शिमला शहर में रोज का आना जाना रहता है। उनकी समस्याओं को देखते हुए उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से बस रूट बढ़ाने के लिए चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एचआरटीसी के बेड़े में खरीदी गई 300 नई इलेक्ट्रिक बसों में से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को 30 इलेक्ट्रिक बेस मिली हैं। उन्होंने कहा कि 18 नई इलेक्ट्रिक बसों को विभिन्न रूट पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिससे काफी हद तक बसों की कमी पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में शेष बची 12 इलेक्ट्रिक बसों को जल्द ही सुन्नी से विभिन्न रूट के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इलेक्ट्रिक बसें एक बार फुल चार्ज करने के बाद 150 किलोमीटर तक चलेंगी, इसलिए इन इलेक्ट्रिक बसों को दूर के रूटों पर ना भेजकर छोटे रूटों पर ही भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला के आसपास के क्षेत्र के लोगों विशेषकर बुजुर्गों की एचआरटीसी के छोटे वाहनों या टैक्सी की मांग को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा टैक्सियां लगाई जाएगी जिसके लिए निगम के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि टैक्सियों की सुविधा के साथ-साथ निजी बसों के रूट भी दिए जाएंगे, ताकि शहर के आसपास के क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित आवाजाही की सुविधा मिल सके।

शिमला ग्रामीण में चल रहे 650 करोड़ के विकास कार्य

उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 650 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है, जिसमें से अधिकतर कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और कुछ कार्यों का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान प्रदेश की सभी सड़कें बहाल रहे व आवाजाही बनी रहे, इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनी सारी मशीनरी सड़कों को खोलने में लगाई गई है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा हर डिवीजन में आवश्यकता अनुसार निजी मशीनरी भी हायर की गई है और प्रतिदिन उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, ताकि किसानों बागवानों व आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों तारकोल के रेट में बढ़ोतरी होने के कारण सड़कों को पक्का करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने के बावजूद मेटलिंग व टायरिंग का कार्य नहीं हो पाया है जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मानसून खत्म होगा, हर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की मेटलिंग व टायरिंग का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।

15 अगस्त पर सभी सरकारी स्कूलों में होगा सीएम के संबोधन का सीधा प्रसारण

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के संबोधन का प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में सीधा प्रसारण किया जाएगा।

इस प्रसारण को बिना किसी बाधा के सफल बनाने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शिमला में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों और विद्यालयों को पहले से आवश्यक तैयारियां पूरी करने तथा प्रसारण व्यवस्था की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान यदि किसी विद्यालय में तकनीकी समस्या आती है या प्रसारण बाधित होता है तो उसके समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों की तैनाती की गई है। 15 अगस्त को नियंत्रण कक्ष में व्याख्याता रीना शर्मा, नंद किशोर, दिनेश कुमार और विनोद कुमार ड्यूटी पर रहेंगे। इन अधिकारियों को निर्धारित समय पर नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहकर प्रदेशभर के सरकारी विद्यालयों में होने वाले सीधे प्रसारण की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय ने कहा है कि नियंत्रण कक्ष में तैनात अधिकारी विभिन्न जिलों से मिलने वाली प्रसारण संबंधी शिकायतों और तकनीकी समस्याओं पर तत्काल समन्वय स्थापित करेंगे।

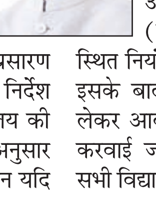

यदि किसी सरकारी विद्यालय में मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किसी कारण से प्रभावित होता है तो संबंधित जिले के उपनिदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) सीधे शिमला स्थित नियंत्रण कक्ष से संपर्क करेंगे। इसके बाद समस्या की जानकारी लेकर आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों और स्कूल प्रशासन को यह भी निर्देश दिए हैं कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों, इंटरनेट कनेक्शन और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं की पूरी तरह जांच कर ली जाए। विभाग का मानना है कि पूर्व तैयारी से कार्यक्रम के दौरान आने वाली संभावित तकनीकी दिक्कतों को कम किया जा सकेगा।

खूबसूरत अदा में एंड्रिया

एंड्रिया वर्गास कोस्टा रिका की प्रसिद्ध एथलीट हैं, जो 100 मीटर बाधा दौड़ में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में कोस्टा रिका का प्रतिनिधित्व किया है। अपनी तेज गति, शानदार तकनीक और निरंतर मेहनत के कारण वह देश की प्रमुख महिला खिलाड़ियों में शामिल हैं।

टी20 लीग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को बैकफुट पर धकेला : हरभजन

कहा- टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए इसे बढ़ावा देना जरूरी

एजेंसी, दिल्ली

पूर्व भारतीय दिग्गज हरभजन सिंह ने कहा है कि विश्व भर की प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसी टी20 लीग की बढ़ती लोकप्रियता के कारण द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के खत्म होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हरभजन ने पीटीआई के साथ एक पॉडकास्ट साक्षात्कार में टी20 लीग की बढ़ती संख्या के कारण लगातार व्यस्त होते जा रहे क्रिकेट कैलेंडर को देखते हुए खेल के तीनों प्रारूपों के भविष्य के बारे में खुलकर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उनकी आत्मकथा इस साल के अंत में प्रकाशित होगी। वह इस पर पिछले कुछ समय से काम कर रहे हैं।

हरभजन से जब पूछा गया कि क्या टी20 लीग आखिर में वह जगह ले लेंगी जो पारंपरिक रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए रही है, तो उन्होंने कहा, 'ऐसा पहले ही हो चुका है, 70 प्रतिशत लोग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बजाय क्लब क्रिकेट देख रहे हैं।' भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच को देखने के लिए पर्याप्त संख्या में दर्शक पहुंचते हैं लेकिन अगर भारत श्रीलंका या अफगानिस्तान से खेलता है तो बहुत कम दर्शक वह मैच देखते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच में दर्शक संख्या अच्छी होती है लेकिन इंग्लैंड-बांग्लादेश श्रृंखला में ऐसा नहीं होता है।'

वनडे में 236 मैचों में 269 विकेट लेने वाले हरभजन ने कहा, ''अगर भारत-ऑस्ट्रेलिया, भारत-दक्षिण अफ्रीका या भारत-इंग्लैंड के बीच कोई श्रृंखला होती है, तो मैं उसे देखना पसंद करूंगा। मैं टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए भुगतान करने के लिए भी तैयार हूं।

मुझे वनडे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने इसे देखा है, खेला है।' हरभजन ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में एक क्रिकेटर के कौशल और जज्बे की परीक्षा होती है और इसे खेल के चरम पर बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ''टेस्ट क्रिकेट ही मुख्य क्रिकेट है। खेल से जुड़े सभी हितधारकों को टेस्ट क्रिकेट को बचाए रखना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट है। यह एक क्रिकेटर के तौर पर आपकी हर तरह से परीक्षा लेता है।' भारत में बेहद लोकप्रिय आईपीएल से लेकर ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) और इंग्लैंड की द हंड्रेड तक, फ्रेंचाइजी क्रिकेट ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। दर्शकों ने भी इसको पूरा समर्थन दिया है।

अगर फिटनेस और प्रदर्शन अच्छा तो उम्र मायने नहीं रखती

हरभजन सिंह ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर लियोनेल मेस्सी खेल सकते हैं, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों नहीं? उन्होंने इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर उनमें खेलने की प्रतिबद्धता है तो वे अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप में खेल सकते हैं। पीटीआई के मुख्यालय में एक पॉडकास्ट साक्षात्कार में 46 वर्षीय पूर्व ऑफ स्पिनर ने रोहित और कोहली के भविष्य को लेकर चल रही अंतहीन बहस पर अपने विचार व्यक्त किए। यह दोनों खिलाड़ी 35 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और अब केवल एक ही प्रारूप में खेलते हैं। हरभजन ने साक्षात्कार के दौरान यह भी खुलासा किया कि उनकी आत्मकथा तैयार है और उसके इस वर्ष के आखिर में प्रकाशित होने की उम्मीद है। हरभजन ने कहा, ''खिलाड़ी कोई भी हो, मेरा मानना है कि मापदंड प्रदर्शन होना चाहिए, उम्र नहीं।''

गॉल टेस्ट में तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर उतार सकता है भारत

एजेंसी, गॉल

भारत गॉल टेस्ट में तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर उतार सकता है। टीम के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके संकेत दिए। टीम कुलदीप यादव, मानव सुथार और रवींद्र जडेजा को प्लेइंग-11 में मौका दे सकती है। मोर्केल ने कहा- 'तीनों गेंदबाज की स्कील्स अलग-अलग है। इनमें 20 विकेट लेने की काबिलियत है। कुलदीप बाएं हाथ की कलाई वाली स्पिन से गेंदबाजी करते हैं। जडेजा लगातार विकेट पर गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं सुथार ऊंचे कद के साथ पुराने दौर वाली बाएं हाथ की स्पिन डालते हैं।'

टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने दिए संकेत

कहा- कुलदीप, जडेजा और सुथार की स्कील्स अलग

गॉल की पिच पर स्पिनर अटैकिंग बेहतर ऑप्शन

मोर्केल ने कहा कि- गॉल की पिच पर भारत के स्पिन गेंदबाज टीम को अटैकिंग ऑप्शन देते हैं। मैच आगे बढ़ने के साथ पिच पर स्पिनरों को मदद करेगी।' उन्होंने कहा- यहां खेले गए मैचों पर नजर डालें तो तीन स्पिनरों के साथ जाना सही लगता है।' हालांकि मोर्केल का मानना है कि कप्तान शुभमन गिल इन गेंदबाजों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसपर काफी कुछ निर्भर करेगा।

2 पेसर के साथ मैदान में उतर सकती है टीम

टीम में सिराज के साथ एक और तेज गेंदबाज खेल सकता है। मोर्केल ने कहा कि प्रसिद्ध और गुरनूर में से जिसे प्लेइंग-11 में जगह मिलेगी, वह जिम्मेदारी निभाएंगे। दोनों ने काफी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। मोर्केल ने माना कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती गर्मी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा- तेज गेंदबाज के लिए 20 से 35 ओवर के बाद गेंद नरम हो जाएगी।

स्पोर्ट्स विंडो

बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप : 17 को एक मंच पर आएंगे शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाली बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए दुनिया भर के बैडमिंटन खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रशंसकों का स्वागत किया है। विश्व के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने वाली यह चैंपियनशिप खेल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में शामिल है। इसके आयोजन के साथ भारत ने बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए खुद को एक भरोसेमंद और सक्षम देश के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आईओए ने वीरवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि चैंपियनशिप की सफल मेजबानी भारत सरकार के निरंतर सहयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के खेल तंत्र को मजबूत करने तथा भारत को वैश्विक खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है। खेल बुनियादी ढांचे, खिलाड़ियों के विकास, उच्च प्रदर्शन कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी में लगातार निवेश के माध्यम से भारत ने विश्व खेल मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की है।

सिंकफील्ड कप: भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद को कीमर ने दी मात

एजेंसी, सेंट लु। भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद की सिंकफील्ड कप 2026 में अजेय शुरुआत तीसरे दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर के हाथों हार के साथ समाप्त हो गई। काले मोहरों से खेल रहे 21 वर्षीय प्रज्ञानानंद को रोमानिया के सुपर चेस क्लासिक के चैंपियन कीमर ने शिकस्त दी। इस हार के बाद प्रज्ञानानंद 1.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। उनके साथ अमेरिका के फैबियानो करूआना, जर्मनी के विंसेंट कीमर और अमेरिका के सैम सेवियन भी संयुक्त चौथे स्थान पर हैं। अमेरिका के वेस्ली सो ने हमवतन फैबियानो करूआना को हराकर प्रतियोगिता में एकमात्र बढ़त हासिल कर ली है। सो के खाते में 2.5 अंक हैं। फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव और अमेरिका के लेवोन अरोनियन ने क्रमशः जावोखिर सिंदारोव और जॉर्डन वान फोरेस्ट के खिलाफ मुकाबले ड्रॉ खेले। दोनों खिलाड़ी तीन दौर के बाद दो-दो अंकों के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। उधर, कैन्स कप में भारत की दिव्या देशमुख ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्विटजरलैंड की ग्रैंडमास्टर एलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुक को हराकर अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। दिव्या की इस जीत के साथ उनके खाते में दो अंक हो गए हैं। वहीं, कोस्टेनियुक को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा और वह अंक तालिका में पिछड़ गई हैं।

बेन शेल्टन व ब्रैंडन नाकाशीमा नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में

एजेंसी, मॉन्ट्रियल। मौजूदा चैंपियन बेन शेल्टन ने बुधवार रात को अपने हमवतन अमेरिकी खिलाड़ी लर्नर टिएन को 6-2, 6-3 से हराकर नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में पांचवीं वरीयता प्राप्त शेल्टन का सामना अमेरिका के ही एक अन्य खिलाड़ी ब्रैंडन नाकाशीमा से होगा। 28वीं वरीयता प्राप्त नाकाशीमा ने पहले सेमीफाइनल में स्पेन के 19 वर्षीय राफेल जोडर को 7-6 (3), 6-4 से हराकर पहली बार किसी एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। शेल्टन ने अब तक अपने करियर में छह खिताब जीते हैं। इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने इस साल डलास, म्यूनिख और स्टटगार्ट में खिताब जीते थे। नाकाशीमा ने 2022 में सैन डिएगो में अपना एकमात्र टूर खिताब जीता था।

फुटबॉल: नीदरलैंड ने 48 साल बाद नियुक्त किया पहला विदेशी कोच

एजेंसी, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड ने स्पेन के दिग्गज फुटबॉलर ज़ावी हर्नांडेज़ को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। यह 1978 के बाद पहला अवसर है, जबकि नीदरलैंड ने किसी विदेशी को अपनी राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। वह रोनाल्ड कोमैन की जगह लेंगे जिन्होंने विश्व कप के बाद अपना पद छोड़ दिया था। ज़ावी उस स्पेनिश टीम के सदस्य थे जिसने 2010 में विश्व कप फाइनल में नीदरलैंड को हराया था। 46 वर्षीय ज़ावी इससे पहले बार्सिलोना के मुख्य कोच थे, लेकिन उन्होंने मई 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नीदरलैंड पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को से हारने के बाद विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया था।

बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने बनाया अपना लोएस्ट टेस्ट स्कोर

एजेंसी, डर्विन। बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 198 रन पर ऑलआउट हो गई। यह टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 2017 में मीरपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 217 रन पर सिमट गई थी। बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने 17 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट लिए। तस्कीन अहमद और इबादत हुसैन को 2-2 विकेट मिले। जवाब में बांग्लादेश ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एकमात्र विकेट मिचेल स्टार्क ने लिया। उन्होंने टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लने वाले गेंदबाजों में कपिल देव की बराबरी कर ली। दोनों के 434 विकेट हैं। स्टार्क टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने करियर में 434वां विकेट लेकर श्रीलंका के रंगना हेराथ को पीछे छोड़ा। हेराथ के 433 विकेट हैं।

पीएसजी ने दूसरी बार जीता यूईएफए सुपर कप

फाइनल में क्वारात्सखेलिया-डुए के गोलों की बदौलत एस्टन विला को 2-1 से हराया

एजेंसी, साल्जबर्ग

चैंपियंस लीग विजेता पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) ने एस्टन विला को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार यूईएफए सुपर कप का खिताब अपने नाम कर लिया। पीएसजी की जीत में खिचा क्वारात्सखेलिया और देसिरे डुए ने गोल किए, जबकि एस्टन विला की ओर से 17 वर्षीय ब्रायन मैडजो ने गोल दागा। पीएसजी ने 12 महीने पहले टोटेनहम हॉटस्पर को हराकर पहली बार सुपर कप जीता था। इस बार भी टीम ने प्रीमियर लीग की एक अन्य टीम को मात देकर यूरोप की शीर्ष क्लब टीम के रूप में अपना दबदबा कायम रखा। दोनों टीमों ने अपने घरेलू सत्र की शुरुआत से पहले मजबूत प्लेइंग इलेवन उतारी। पीएसजी की शुरुआती टीम में चैंपियंस लीग फाइनल में खेलने वाले नौ खिलाड़ी शामिल थे। मैच का पहला गोल 20वें मिनट में आया। क्वारात्सखेलिया ने बाएं छोर से अंदर की ओर आते हुए

शानदार शॉट लगाया, जिसे एस्टन विला के गोलकीपर मार्को बिजोट रोक नहीं सके। पीएसजी ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

हालांकि, एस्टन विला ने हार नहीं मानी। 17 वर्षीय मैडजो ने पहले हाफ के अंतिम मिनट में कप्तान जॉन मैकगिन के शानदार पास का फायदा उठाते हुए गेंद को पीएसजी के गोल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ मुकाबला 1-1 की बराबरी पर आ गया।

दूसरे हाफ में पीएसजी ने आक्रामक शुरुआत की। 61वें मिनट में फ्रांस के देसिरे डुए ने दाएं छोर से आगे बढ़ते हुए शानदार फिनिश के साथ गेंद को विला के गोल में पहुंचा दिया। हालांकि सहायक रेफरी ने शुरुआत में ऑफसाइड का संकेत दिया, लेकिन वीडियो असिस्टेंट रेफरी (वीएआर) की समीक्षा के बाद गोल को मान्य कर दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि एस्टन विला के डिफेंडर मैटी कैश ने डुए को ऑनसाइड रखा था।

इसके बाद एस्टन विला ने बराबरी की भरपूर कोशिश की। जॉर्ज हेमिंग्स और जॉन मैकगिन के पास अच्छे मौके आए, लेकिन पीएसजी के गोलकीपर मातवे सफोनोव ने शानदार बचाव करते हुए अपनी टीम की बढ़त बरकरार रखी। मैच के अंतिम चरण में एस्टन विला लगातार हमले करता रहा। टैमी अब्राहम के पास भी बराबरी का बेहतरीन मौका आया, लेकिन वह गोल के सामने मिले पास को छूने से मामूली अंतर से चूक गए। पीएसजी ने आखिरी मिनटों में दबाव झेलते हुए 2-1 की बढ़त कायम रखी और लगातार दूसरी बार यूईएफए सुपर कप जीत लिया। अब पीएसजी की नजरें नए सत्र में लगातार तीसरी चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीतने पर होंगी।

जुलाई में बढ़ी खुदरा महंगाई खाद्य वस्तुओं ने बढ़ाई चिंता

एजेंसी, नई दिल्ली

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश की खुदरा महंगाई दर जुलाई में मामूली बढ़ोतरी के साथ 4.45 प्रतिशत हो गई। जून में यह दर 4.38 प्रतिशत थी। महंगाई में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आया उछाल रहा। जुलाई में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.52 प्रतिशत पर पहुंच गई।

सब्जियों और मसालों के दाम बढ़े : जुलाई के दौरान रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई। अदरक की महंगाई दर 83.62 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसी तरह लहसुन की महंगाई दर 35.36 प्रतिशत और प्याज की 22.54 प्रतिशत रही। इन वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है।

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की जरूरतों पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि, खुदरा महंगाई अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सहनशीलता सीमा के भीतर बनी हुई है।

एसबीआई ने 50 करोड़ डॉलर के बॉन्ड का सफल मूल्य निर्धारण किया पूरा

एजेंसी, मुंबई

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से 5.25 प्रतिशत कूपन दर वाले 50 करोड़ डॉलर के रेगुलेशन एस बॉन्ड का सफलतापूर्वक मूल्य निर्धारण पूरा किया है। पांच वर्ष की अवधि वाले इन बॉन्ड को पांच वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी के मुकाबले 88 आधार अंक अधिक की कीमत पर तय किया गया है। इन बॉन्ड को एसजीएक्स-एसटी, इंडिया आईएनएक्स और एनएसई-आईएफएससी पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

इस लेनदेन को वैश्विक निवेशकों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। विभिन्न देशों और क्षेत्रों के निवेशकों ने इसमें मजबूत रुचि दिखाई। बॉन्ड की ऑर्डरबुक अपने उच्चतम स्तर पर 2.46 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसमें कुल 145 निवेशकों ने भाग लिया। मजबूत मांग को देखते हुए शुरुआती मूल्य निर्धारण अमेरिकी ट्रेजरी बेंचमार्क से 120 आधार अंक ऊपर रखा गया था। बाद में निवेशकों की मजबूत भागीदारी के चलते इसे संशोधित कर 88 आधार अंक ऊपर कर दिया गया।

रेगुलेशन एस बॉन्ड ऐसे ऋण प्रतिभूति होते हैं जिन्हें अमेरिका के बाहर जारी किया जाता है और इनमें

अमेरिकी निवेशकों के लिए प्रत्यक्ष पेशकश नहीं होती। इस व्यवस्था के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार से पूंजी जुटाने में मदद मिलती है।

एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 50 करोड़ डॉलर के बॉन्ड का सफल मूल्य निर्धारण बैंक के प्रति निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है।

एयरटेल ने बंद किए पांच सस्ते प्लान, बढ़ा मोबाइल का रिचार्ज खर्च

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने प्रीपेड पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव करते हुए रोजाना 1.5 जीबी डेटा देने वाले पांच लोकप्रिय और किफायती प्लान बंद कर दिए हैं। कंपनी की वेबसाइट और थैंक्स ऐप से 299 रुपये, 319 रुपये, 579 रुपये, 619 रुपये और 649 रुपये वाले प्लान हटा दिए गए हैं। इन प्लान के बंद होने से उन ग्राहकों पर सीधा असर पड़ेगा जो कम कीमत में रोजाना डेटा और लंबी वैधता वाले रिचार्ज का इस्तेमाल कर रहे थे।

अब कम से कम 349 रुपये का रिचार्ज : पांच सस्ते प्लान हटाए जाने के बाद ग्राहकों के लिए नया विकल्प 349 रुपये का प्लान है। इससे मोबाइल रिचार्ज की शुरुआती लागत में करीब 16 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि, नए 349 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को रोजाना 2 जीबी डेटा के साथ अनलिमिटेड 5जी डेटा का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्लान में मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा कंपनी की ओर से ग्राहकों को कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। नए प्लान के कारण अधिक डेटा की जरूरत वाले ग्राहकों को राहत मिल सकती है। हालांकि कम बजट में रिचार्ज कराने वाले ग्राहकों के लिए यह बदलाव जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।

उतार-चढ़ाव मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स मजबूत, निफ्टी में मामूली गिरावट

सेंसेक्स में तेजी, निफ्टी फिसला; बाजार में रहा उतार-चढ़ाव

एजेंसी, मुंबई

विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के अधिकांश समय प्रमुख सूचकांक दबाव में रहे, हालांकि अंतिम कारोबारी दौर में खरीदारी बढ़ने से बीएसई का सेंसेक्स बढ़त में बंद होने में सफल रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।

बीएसई का सेंसेक्स 113.61 अंक यानी 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 78,079.96 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बाजार में कई बार उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दूसरी ओर निफ्टी-50 सूचकांक 40.10 अंक यानी 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,395.85 अंक पर बंद हुआ। इस तरह दोनों प्रमुख सूचकांकों में कारोबार की दिशा अलग-अलग रही।

व्यापक बाजार में तेजी : व्यापक

बाजार की बात करें तो ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक में 0.22 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.27 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ। इससे संकेत मिला कि व्यापक बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही और कई मध्यम तथा छोटी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली।

इन क्षेत्रों में रही तेजी : क्षेत्रवार कारोबार में एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, रियल्टी, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और रसायन समूहों के सूचकांकों में तेजी रही। इसके विपरीत धातु, बैंकिंग, वित्त, फार्मा, स्वास्थ्य तथा तेल एवं गैस समूहों के सूचकांक गिरावट में रहे। क्षेत्रीय प्रदर्शन में अंतर के कारण बाजार में पूरे दिन अस्थिरता बनी रही।

सेंसेक्स की कंपनियों में मिला-जुला प्रदर्शन : सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इंडिगो का शेयर करीब तीन प्रतिशत चढ़कर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में रहा।

बाजार में कारोबार के दौरान निवेशकों की नजर प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर बनी रही। सेंसेक्स में शामिल अन्य कंपनियों में एनटीपीसी के शेयर में करीब दो प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। बीईएल, एलएंडटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इटरनल, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और आईटीसी के शेयर भी बढ़त में रहे। दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन के शेयरों में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

एनटीपीसी समेत दिग्गज शेयर चढ़े बैंकिंग और आईटी शेयर फिसले

एनटीपीसी के शेयर में करीब दो प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। बीईएल, एलएंडटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इटरनल, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और आईटीसी के शेयरों में भी दो प्रतिशत तक की तेजी रही। इसके अलावा मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी बढ़त में बंद हुए। दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन के शेयर एक प्रतिशत से अधिक टूटे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंफोसिस और टाटा स्टील के शेयर भी लाल निशान में बंद हुए।

स्वतंत्रता दिवस पर इंडिगो की खास सेल हवाई टिकट पर 20 प्रतिशत की छूट

एजेंसी, नई दिल्ली

यात्री संख्या के हिसाब से देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यात्रियों के लिए 'हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेल' की घोषणा की है। इस विशेष पेशकश के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर यात्रा के लिए टिकट बुक कराने वाले ग्राहकों को मूल किराये में 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

कंपनी के अनुसार यह ऑफर 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच नॉन-स्टॉप उड़ानों के लिए की गई बुकिंग पर लागू होगा। इस ऑफर के तहत यात्री 16 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 के बीच यात्रा कर सकेंगे। छूट का लाभ लेने के लिए यात्रियों को यात्रा से कम से कम तीन दिन पहले टिकट बुक करना होगा। बुकिंग के दौरान प्रोमो कोड 'इंडिगो80' का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

ग्राहक टिकट की बुकिंग इंडिगो की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, एआई आधारित सहायक 6ईस्काई तथा चुनिंदा यात्रा साझेदारों की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। टिकट किराये में छूट के अलावा कंपनी ने अन्य सेवाओं पर भी आकर्षक ऑफर पेश किए हैं।

कंपनी के मुताबिक 6ई ईट्स, फास्ट फॉरवर्ड और 6ई सीट्स पर भी 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। फेयर होल्ड सुविधा 20 रुपये से शुरू होगी, जबकि इंडिगो अफ्रंट अपग्रेड 999 रुपये से उपलब्ध होगा। हालांकि फेयर होल्ड और अफ्रंट की सुविधा केवल इंडिगो के सीधे माध्यमों से की गई बुकिंग पर ही मिलेगी।

इसके अलावा इंडिगो ब्लूचिप सदस्यों को इंडिगो के सीधे माध्यमों से की गई इंडिगो स्ट्रेच बुकिंग पर 20,000 तक इंडिगो ब्लूचिप अर्जित करने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा 24 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच की यात्रा के लिए उपलब्ध होगी। कंपनी ने यात्रियों को समय रहते बुकिंग कर इस विशेष सेल का लाभ उठाने की सलाह दी है।